हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 अप्रैल, 1972

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार 5 अप्रैल, 1972

	पृष्ठ संख्या
शोक प्रस्ताव	(2)1
प्रश्न काल सम्बन्धी औचित्य प्रश्न	(2)4
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(2)8
सभापति–तालिका	(2)10
मेज पर रखा गया राज्यपाल का अभिभाषण	(2)10
सचिव द्वारा घोषणा	(2)14
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(2)14
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	(2)15
राजयपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)15
उपाध्यक्ष का निर्वाचन (बधाई भाषण)	(2)16
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)16

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 5 अप्रैल, 1972

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में मध्यान्होपरान्त 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारी पिछली विधान सभा के आखिरी सैशन के बाद से अब तक हमारी कई डिस्टींगुइश्ड आत्माएं इस नश्वर संसार से चल बसीं। मैं सदन से आपके जरिये प्रार्थना करूंगा कि उनके कुटुम्ब के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए इस शाक प्रस्ताव को पास करके भेजा जाए। ये आत्माएं है:–

'किंग महेन्द्रा आफ नेपाल': किंग महेन्द्रा का जन्म सन् 1920 में हुआ। 1955 में वह नेपाल की गद्दी पर बैठे। सन् 1959 में उन्होंने वहां पर पापुलर गर्वनमैंट बनाई। वह एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके परिवार के प्रति और उनकी नेशन के प्रति शोक प्रस्ताव पास करने का मैं सदन से अनुरोध करता हूं।

दूसरे व्यक्ति हैं, श्री ए.एन. झा, लैफ्टीनैन्ट गवर्नर, दिल्ली। उनका जन्म 1911 में हुआ और सन् 1934 में उन्होंने

आई.सी.एस. की लिस्ट में टाप किया। 1954 से 1958 तक वह यू. पी. स्टेट के चीफ सैक्रेटरी रहे। इसके बाद वह संस्कृत यूनिवर्सिटी, वाराणसी के फर्स्ट वाईस चांसलर भी रहे। सन् 1966 से वह दिल्ली के लैफ्टीनैन्ट गवर्नर थे।

इसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं श्री दुर्गा दास भाटिया, एम. पी.। उनका देहान्त 2 फरवरी, 1972 को हुआ। वह एक सीजन्ड पार्लियामैंटेरियन थे और पिछले साल ही लोक सभा के लिए चुने गये थे। वह बहुत अच्छे सोशल वर्कर और सैकुलरिजम में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। 1952 के बाद 14 साल तक वह अमृतसर म्युनिस्पैलिटी के प्रैसीडैंट भी रहे।

इसके बाद श्री बी.एम. गुप्ता, फौर्मर एम.पी. हैं। उनका देहान्त 21 फरवरी, 1972 को हुआ। वह एक फ्रीडम फाईटर और बहुत अच्छे पार्लियामैंटेरियन थे। वह देश की कांस्टीच्युएंट असैम्बली के मैम्बर भी रहे।

इसके बाद हैनरी सैम्युल हैं, जिनका देहान्त 16 फरवरी, 1972 को हुआ। वह एक बहुत ही अच्छे पार्लियामैंटेरियन और पावरफुल डिबेटर थे। इसके अलावा वह एक जर्नलिस्ट भी थे। वह सोसाइटी के एक बहुत ही ऊंची कोटी के आदमी थे।

इसके बाद श्री एन. गोपाला मैनन, फार्मर स्पीकर आफ दी कम्पोजिट मद्रास असैम्बल हैं जिनका देहान्त 9 फरवरी, 1972 को हुआ।

इसके उपरान्त श्री मोहन लाल, एक्स एम.एल.सी. हैं जिनका देहान्त 18 फरवरी, 1972 को हुआ। श्री मोहन लाल जी लाला लाजपतराय कै बहुत ही क्लोज एसोशियेट थे और बहुत बड़े सोशल (वर्कर) रिफार्मर थे। उन्हीं की मेहनत की वजह से द्वारिका दास लाइब्रेरी, चण्ड़ीगढ़ ओर गुलाब देवी टी.बी. हास्पिटल, जालन्धर को स्टार्ट किया जा सका। इसके बाद पंडित अमीर चन्द बमबवाल हैं जिनका देहान्त 10 फरवरी, 1972 को हुआ। यह भी एक बहुत बड़े रैवाल्यूशनरी और फ्रीडम फाईटर थे।

इसके बाद श्री के.टी. जार्ज, फाईनांस मिनिस्टर, केरल हैं। वे 1965 में केरल विधान सभा के लिए सदस्य चुने गये। उसके बाद 1967 से लेकर 1970 तक वह कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप ओर केरल विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर रहे। अब वह केरल के फाईनांस मिनिस्टर थे।

मैं आपके जरिये सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस शोक प्रस्ताव को पारित किया जाये।

चौधरी रिजक राम (राई): मानयोग अध्यक्ष महोदय, जिन महानुभावों के स्वर्ग सिधारने पर मुख्य मंत्री जी ने शोक प्रस्ताव पेश किया है मैं उनके प्रति शोक प्रकट करने ओर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुख्य मंत्री जी ने उनके प्रति जो भावना प्रकट की है मैं उनसे विरोधी पार्टी की तरफ से पूर्णरूप से एसोशियट करता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता

हूं कि हमारे पड़ोसी देश के राजा महेन्द्रा जी से मुझे सम्पर्क में आने का अवसर मिला था। वह भाखड़ा पावर प्रोजैक्ट ओर हमारे प्रदेश के कुछ दूसरे हिस्सों के दौरे पर अयो हुये थे। मुझे उनके साथ रहने और बातचीत करने का मौका मिला था इसलिये मैं उनकी खूबियों से कुछ वाकफियत रखता हूं। जैसे कि लीडर आफ दी हाउस ने फरमाया है कि वह बहुत काबिल एडमिनिन्ट्रेटर थे, मैं उनसे सहमत हूं। अपने देश की ही नहीं बल्कि इस देश की तरक्की में भी उनकी बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। उनकी यह कोशिश थी कि दोनों देश आपस में मिल–जुल कर एक अच्छे तरीके से तरक्की के रास्ते पर चल सकें। उनके देहान्त से नेपाल को ही नहीं बल्कि हमारे देश को और सारे विश्व भर के लोगों को बहुत भारी धक्का पहुंचा है और भारी हानि हुई है।

इसके अलावा सर्व श्री दुर्गा दास जी भाटिया और मोहन लाल जी से भी मेरा सम्पर्क रहा है। दुर्गा दास जी भाटिया म्युनिस्पैलिटी, अमृतसर के बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अमृतसर जो कि एक बहुत ही बड़ा कस्बा है, मैं जितने साल भी उन्हें काम करने का मौका मिला, उसने बहुत ही नुामयां तरक्की की। पार्लियामैंट में जाने के बाद भी वह बहुत अच्छी तरह सें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। अगर भगवान उनको और आयु देता तो वह चोटी के पार्लियामैंटेरियनों में से एक होते, ऐसी मुझे आशा है। मोहन लाल जी को बहुत से वे आदमी जानते थे जिनको पंजाब मे असैम्बली में आने–जाने का मौका मिला है।

मोहन लाल जी बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के कल्याण के कामों में लगाया। जालन्धर में ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी उन्होंने बहुत काम किया। वह हमारे साथ सदन के मैम्बर भी थे। वहां हमें उनसे मिलने जुलने का बहुत वास्ता पड़ता रहा है। जहां वे कौंसिल के मैम्बर के तौर पर अपनी लियाकत जाहिर करके हाउस के और अपने इलाकों के मुफाद के लिये हमेश सरगर्म रहे वहां देश की सेवा में भी कभी पीछे नहीं रहै। इन शब्दों के साथ मैं इन सारे लोगों के, जिनका वर्णन मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव में किया हैं, निधन पर बहुत ही शोक प्रकट करता हूं और जो प्रस्ताव इस हाउस के सामने आया है उसकी ताईद करता हूं। इसके साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकीरूह को शान्ति दें ओर उनके परिवारों को इतना हौसला दे कि वे उनके देहान्त से जो सदमा पहुंचा है, उसको सहन कर सकें।

श्री अध्यक्षः मननीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो प्रसताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है ओर जिन दिवंगत आत्माओं के प्रति सदन के नेता ने अपने भाव व्यक्त किए हैं ओर विपक्षी दल के नेता ने जिस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, मैं भी उन दोनों की भावनाओं के साथ अपने आपको सम्बन्धित करता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि शोक प्रस्ताव में जिन दिवंगत आत्माओं की चर्चा की गयी है, वे महान् व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण

काम किये। यद्यपि आज के शरीर उपस्थित नहीं है फिर भी जो कार्य उन्होंने किये हैं वह हमेशा–हमेशा के लिए याद रहेंगे।

यहां पर महाराजा महेन्द्रा का जिक्रक आया। वह हमारे पड़ोसी देश के राजा थे और हमारे उनके साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थे। उनके निधन से जो क्षति हुई है वह ऐसी है जिसके घाटे को पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसा कि चौधरी रिजक राम ने बतलाया, एक–दो व्यक्ति जैसे श्री दुर्गादास भाटिया तथा श्री मोहन लाल, उनसे मैं भी व्यक्तिगतरूप से सम्बन्धित रहा हूं। भाटिया जी बड़े अच्छे पार्लियामैन्अेरियन थे और अमृतसर जैसी म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान पद पर रहते हहुए नगर को सुन्दर बनाने में उनका जो योगदान रहा है वह सराहनीय है। श्री मोहन लाल जी के बारे में अगर यह कहा जये कि वे राजनैतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक सन्त भी थे तो अतिश्योक्ती नहीं है।

दिल्ली के उप–राज्यपाल श्री झा जहां एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वहां दूसरी और वे एक बहुत ही अच्छे भाषाविज्ञ, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे और एक साहित्यिक व्यक्ति थे। इन सब महानुभावों के स्वर्गवास होने पर इस सदन का चिन्ता व्यक्त करना स्वाभाविक है। जो भावना, जो विचार यहां व्यक्त किये गये हैं, ए प्रस्ताव के द्वारा मैं उनके संतप्त परिवारों को पहुंचाऊंगा और तमाम विधायकगण से प्रार्थना करूंगा कि दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दो मिनट के लिए खड़े होकर मौन धारण करें।

(इस समय दो मिनट के लिए खड़े होकर सभी सदस्यों ने मौन धारण किया)

प्रश्न काल सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That Rule 30 of the Rules .....

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, अभी एक लैटर मुझे दिया गया हैं जिसमें लिखा हुआ है – 'मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि क्योंकि बुधवार, 5 अप्रैल, 1972 के लिए कोई भी प्रश्न मौखिक उतर के लिए नहीं है, अतः पंजाब विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 28 के अधीन माननीय अध्यख महोदय ने निदेश दिया है कि उस दिन सभा की बैठक में प्रश्न समय नहीं होगा।' स्पीकर साहब, वास्तविकता यह है कि मैंने 27, 28 को यह लिखकर भेज दिया था that all these question be considered as starred quesiton for oral answers. इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि जब मैंने प्रश्न भेजे थे तो क्वैश्चन आवर होना चाहिए था और उसमें हमारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: आप तशरीफ रखिए। मैं आपको अपने पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह स्टार्ड क्वैश्चन है या अनस्टार्ड क्वैश्चन है।

Ch. Bansi Lal: And, Sir, my submission is that even if they are starred questions, fifteen clear days notice is required, and the House was summoned well in time.

चौधरी राम लाल वधवा: सम्मन आने के पहले ही क्वैश्चन भेज दिए थे अगर पन्द्रह दिन नहीं बनते तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम क्वैश्चन भेज ही नहीं सकेंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष: राम लाल जी, आप तशरीफ रखिए। आपके क्वैश्चन का 22 तारीख को नोटिस आया है और सात को ड्यू होता है। 15 दिन का क्लीयर नोटिस होना चाहिए। जितने और प्रश्न आए हैं मेरे पास उनकी लिस्ट है कि किस तारीख को सचिवालय में रिसीव हुए हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: मैंने 28 तारीख को ही लिख दिया था और मैंने डाक से भेजा था। उसमें लिखा था that my question should be considered as starred questions. How does the office say that? It means that the office is not working propely.

श्री अध्यक्ष: आपने जो 22 तारीख को प्रश्न भेजे उनमें यह स्पष्ट नहीं किया कि यह स्टार्ड क्वैश्चन हैं या अनस्टार्ड हैं। प्रैक्टिस ऐसी है कि यदि कोई विधायक प्रश्न के साथ यह नहीं लिखता कि यह स्टार्ड ट्रीट किया जाए या अनस्टार्ड ट्रीट किया जाए तो उसको अनस्टार्ड ट्रीट कर लिया जाता है। जब आपने 28

तारीख को पत्र लिखा तो आपका 28 तारीख का ही नोटिस समझा गया। इस प्रकार से 15 क्लीयर डेज नहीं बनते।

चौधरी बसी लालः मेरे ख्याल से हैं कि हर क्वैशन के साथ यह शो करना चाहिए कि यह स्टार्ड हैं या अनस्टार्ड हैं। एक ही चिट्ठी से सारे क्वैंशचंज स्टार्ड या अनस्टार्ड नहीं होगें।

श्री अध्यक्षः आपरूल 43 देखिए।

चौधरी राम लाल वधवाःरूल के अनुसार तो तीन क्वैश्चन्ज का जवाब हर रोज आना चाहिए लेकिन यहां तो बिल्कूल साफ कर दिया।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, गुजारिश यह हैं कि यह ठीक हैं कि सवाल पर यह लिखना चाहिए था कि यह स्टार्ड हैं या अनस्टार्ड हैं लेकिन चूकिं अभी–अभी चुनाव होकर चूके हैं, नए मैम्बर को सप्लाई हैं। सैक्टिेरियट की तरफ से अगररूल्ज की एक कापी हरेक मैम्बर को सप्लाई हो जाती तो अच्छा रहता। अगर मैम्बर ने स्टार्ड या अनस्टार्ड नहीं लिखा तो कम से कम जवाब हासिल करने के लिए कार्यवाही तो शुरू हो जानी चाहिए थी। यह चीज तो बाद मैं देखी जा सकती थी कि यह स्टार्ड है या अनस्टार्ड हैं। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।रूल्ज की कापी अगर भेज दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता।

चौधरी बंसी लालः यह तो मिल गई थी।

चौधरी रिजक रामः किसी मैम्बर को भेजी नहीं गई।रूल मतें कीं ऐसी बात नहीं हैं कि 15 दिन के टाइम की कंडीशन को वेव नहीं कर सकते। स्पीकर साहब को यह अधिकार हैं कि अगर थोड़ा नोटिस हो तो उसमें कम पीरियड के लिए तैयारी नहीं हैं तो कल भी सैशन है, परसों भी हैं, फिर जवाब दे दिया जाए।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैंने भी 22 तारीख को 14 प्रश्न भेजे थे और उसमें साफ लिखा था कि यह स्टार्ड हैं।

श्री अमर सिंहः मैंने भी 22 तारीख को ही भेजा था और लिख दिया था कि यह स्टार्ड हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः जब असैम्बली पहले ही समन कर ली गई तो फिर 15 दिन का टाईम कैसे हो सकता हैं ?

चौधरी हरद्वारी लालः जहां तक एतराजात का ताल्लुक हैं वह दुरस्त हैं जो सवाल आये थें उन पर कार्यवाही शुरू हो जानी चाहिए थी। बात यह हैं कि हाउस गैर मामूली हालात में बुलाया गया . . . . .।

चौधरी बंसी लालः गैर मामूली हालात में तो नही बुलाया गया।

चौधरी हरद्वारी लालः मैं आपकी बात की ही ताईद या हिमायत करने जा रहा हूं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह

आपके हक में ही जाएगी। मैंने यह कहा कि हाउस गैर–मामूली हालात में बुलाया गया हैं।

श्रीमति चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैं यह जानना चाहती हूं कि यह गैर–मामूली हालात कैसे थे।

चौधरी हरद्वारी लालः मुझे इतनी हिन्दी तो आती नही हैं। गैर–मामूली उसे कहते हैं जो नार्मल न हों। मैंने कहना यह हैं कि यह कोई ऐसी बात नहीं हैं। जिन सवालों का जवाब दिलवा सकते हैं उनका दिलवां दे ओर जिनका नही दिला सकते उनको रहने दिया जाए।

श्री अध्यक्षः देखिये, यह ठीक हैं कि एक विधायक का यह अधिकार हैं कि वह प्रश्न पूछे और साथ ही उसकी यह इच्छा भी होती हैं कि उसका उत्तर भी मिल जाए। लेकिनरूल्ज के मुताबिक असैम्बली बैठने से पहले 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिये और अगर इस कंडीशन को वेच भी किया जाए तो कन्सर्ड मिनिस्टर की शार्ट नोटिस पर उत्तर देने के लिये कन्सेन्ट लेनी जरूरी होती हैं। अगर वह चाहे तो इस कन्डीशन को वेब किया जा सकता हैं।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, क्या हम इसका मतलब यह समझें कि सैशन अगर 5 दिन का नोटिस देकर बुलाया जाए तो हम प्रश्न ही नहीं पूछ सकते ?

श्री अध्यक्षः हमेशा ऐसा थोड़ा ही होगा।

चौधरी शिव राम वर्माः अध्यक्ष महोदय, यहां से 15 दिन का नोटिस जारी हुआ तो वह भी शायद अगले ही दिन मिलेगा, फिर क्वैश्चनज् भेंजेगे, तो फिर 12 दिन रह जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि हमें उत्तर मिलेगा ही नहीं। या तो यह नोटिस काफी समय पहले जारी होना चाहिए या इस कंडीशन को वेव किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह डिफिकलट्री नहीं हैं क्योंकि आनरबेल मैंम्बर अपने प्रश्न कभी भी भेज सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि असैंम्बली बुलाये जाने का नोटिस आने पर ही प्रश्न भेजे जाएं।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, आगे से यह ऐसा हो सकता हैं लेकिन हम तो इस सैशन की बात करते हैं क्योंकि यह पहला सैशन हैं।

श्री अध्यक्षः यह तो चौधरी हरद्वारी लाल जी ने ही बतला दिया कि यह सैशन गैर–मामूली हालात में बुलाया गया हैं।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, हमनें 15 दिन का नोटिस दिया था और उसी शाम को रेडियो पर भी आ गया था कि हरियाणा विधान सभा का सत्र 3 अप्रैल को बुलाया गया हैं। यह हमारी जिम्मेवारी नहीं कि हम उनके घर जाकर सवाल लाएं।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, हमें तो 25 तारीख को यह नोटिस मिला।

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, 22 तारीख को यह नोटिस इशू हो गया था और इससे पहले रेडियो पर भी आ गया था कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन 3 अप्रैल को हो रहा हैं।

Pandti Chiranji Lal Sharma: On a piont of order, Mr. Speaker.

Somne Hon. Members from the oppostition have raised an objection regarding admissibility of questions which sere unstarred till 28th. Now whether the subnsequesnt letter addressed to the Hon. Speaker by the Hon. Members will make them starred and bring them within the limitation, whether this can conmdone the delay that is prescribed under the Rules? That is the piint,

The Hon.Chief Minister has bneen pleased to tell this House that there was a spcific notice that the House will meet on such and such date. There was a clear notice of 15 days. Why this argument then?

श्री अध्यक्षः 21 तारीख को राज्यपाल महोदय का आर्डर आया था कि हरियाणा विधान सभा की बैठक 3 अप्रैल 1972 को बुलाई गई हैं। सम्मन तो 22 तारीख को इशू किया गया।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, नोटिस कब आया, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो सम्मन से मतलब हैं।

Chaudhry Ram Lal Wadhwa: We are concerned with the summons. We are not concerned with the order of the Governor. That is with the offfice and not with the Members.

Chaudhry Bansi Lal: If yoy like I can clarify the position.The Hon. Member claims that unless summons reach him he will not exercise hsi right. The Government has got a right to summon the House even on 2, 3 days' notice. So, our right cannot be challenged. If the opposition adopts that attitude, the Government will also adopt similar attitude.

श्री अध्यक्षः मेरी सदन के नेता से और विपक्षी दल से भी यह प्रार्थना हैं कि दोंनों तरफ का ऐसा अच्छा ऐटीच्यूड होना चाहिए कि जो कुछ विधायक पूछें उसका उत्तर आना चाहिए। मेरी प्रार्थना हैं कि अब इस विवाद को खत्म किया जाए क्योंकि काफी समय इस पर बीत चुका हैं, आगे के लिए विषयों पर ध्यान रखा जाएगा। अब हम अगले विषय को लेते हैं।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं। मेरी गुजारिश है कि कम से कम अन–स्टार्ड क्वैश्नज् का जवाब तो आ जाए।

श्री अध्यक्षः अन–स्टार्ड क्वैश्चन्ज का उत्तर आ जाएगा।

Chaudhry Bansi Lal: There can be no point of Order, during the Question Hour. There is no provision for that during the Question Hour.

श्री अध्यक्षः क्वैश्चन्ज आवर तो आज हैं नहीं, इसलिए प्वांयट आफ आर्डर किया जा सकता हैं।

ध्यानकर्षण सूचनाएं

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, 8 काल अटैन्शान मोशन्ज दिये गये थे लेकिन वह भी आज के एजण्डे में नही आये।

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए अब हम ध्यानकर्षण प्रस्तावों की ही चर्चा करते हैं।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या 1

हरिजन कल्याण योजनाओं आदि की देखभाल करने के लिये विधायकों की या संसदीय समिति बनाने के सम्बन्ध में श्री शिव राम वर्मा, एम0 एल0ए0 द्वारा दी गई ध्यानकर्षण सूचना सं0 1 इस आधार पर अस्वीकृत की जाती हैं कि मामला अविलम्बनीय प्रकार का नहीं हैं तथा सदस्य के पास राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर होगा।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या 2

राज्य विधान सभा के निर्वाचन सरकार द्वारा उचित तथा निष्पक्ष ढंग से न करवाए जाने तथा सरकारी मशीनरी को विस्तृतरूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में श्री राम लाल चौधरी, एम0 एल0 ए0 द्वारा दी गई ध्यानकर्षण सूचना संख्या 2 इन आधरों पर अस्वीकृत की जाती हैं कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचन करवाने का कर्तव्य (संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार) भारत के निर्वाचन अयोग का हैं तथा पीड़ित पक्ष यदि चाहे(चाहे) तो निवार्चन याचिका (याचिकाएं) निवेशित कर सकता हैं(सकते हैं)। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मामले पर चर्चा उठा सकते हैं।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या 3

दो वर्ष से अधिक समय पहले भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा दिये गये निणर्य के अनुसार फाजिल्का तथा अबोहर के क्षेंत्रों को हिरियाणा राज्य में शीघ्र सम्मिलित करवाने की सरकार द्वारा मांग न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लाल चौधरी, एम0 एल0 ए0 द्वारा दी गई ध्यानकर्षण सूचना सं0 इन आधारों पर अस्वीकृत की जाती हैं कि यह एक निरन्तर प्रकार का मामल हैं तथा यह अभी की घटना नहीं हैं और न ही यह अविलम्बनीय प्रकार का मामला हैं। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधिकार में भी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मामले को उठा सकते है।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या 4

जोरां कुआं, करनाल नगर के निवासी श्री ईश्वर चन्द की पत्नी श्रीमति अंगूरी देवी का, जिसका अपहरण 4 फरवरी, 1972 को दिन–दहाड़े करनाल नगर से किया गया था, पता लगाने में सरकार के असफल रहने के सम्बन्ध में श्री राम लाल चौधरी, एम0 एल0 ए0 द्वारा दी गई ध्यानकर्षण सूचना सं0 4 निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृत की जाती हैं।

(i) पीड़ित पक्ष इसका वैध उपचार प्राप्त करने के लिए विधि न्यायालय में जा सकता हैं।

(ii) इस मामले का सम्बन्ध एक व्यक्ति से है।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मामले के उठा सकते हैं।

(iii) इसका सम्बन्ध विधि के नित्य प्रति के प्रशासन से हैं

(iv) यह अविलम्बनीय प्रकार का नही हैं

ध्यानकर्षण सूचना संख्या 5

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर अन्तरिम सहायता तथा मंहगाई भत्ता देने के लिये बार–बार आश्वासन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लाल चौधरी, एम0 एल0 ए0 द्वारा दी गई ध्यानकर्षण सूचना नं0 5 इस आधार पर अस्वीकृत की जाती हैं कि यह अविलम्बनीय प्रकार के मामले के सम्बन्ध में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य के पास राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरानप इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर होगा।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या 6

बी0 ए0 बी0 एड0 अध्यापकों को उनके जिले से बाहर तथा जे0 बी0 टी0 अध्यापकों के बीच मील दूर स्थानान्तरित करने की सरकार की नीत

के सम्बन्ध में श्री राम लाल चौधरी एम0 एल0 ए0 द्वारा दी गई ध्यानकर्षण सूचना सं0 6 इस आधार पर अस्वीकृत की जाती हैं कि यह मामला अविलम्बनीय प्रकार का नहीं हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य के पास राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस मामले पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर होगा।

सभापति–तालिका

श्री अध्यक्ष : पंजाब विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्यों केरूप में कार्य करने के लिये नाम निर्देशित करता हूं।

1. श्री ईश्वर सिंह

2. राव अभय सिंह

3. चौधरी मनफूल सिंह

4. चौधरी चांद राम

मेज पर रखा गया राज्यपाल का अभिभाषण

श्री अध्यक्षः पंजाब विधान सभा के प्रकिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में मैंने यह सूचना देनी हैं कि संविधानप के अनुच्छेंद 176(1) के अधीन राज्यपाल महोयदय ने 4 अप्रैल, 1972 को 3–30 बजे मध्याहन–पश्चात् हरियाणा विधान सभा को सम्बोधन करने की कृपा की। उनके अभिभाषण की एक प्रति सदन को मेज पर रखी जाती हैं।

मित्रो,

विधान सभा के चुनावों में आपकी शान्तिपूर्ण तथा व्यवस्थित ढ़ंग से सम्पन्न हुए। इन चुनावों में लगभग 35

लाख मतदाताओं ने, जोकि कुल मतदाताओं के लगभग 70 प्रतिशत हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 1968 के मध्यावधि चुनावों में लगभग 57 प्रतिशत मतदाताओं ने इस अधिकार का प्रयोग किया था। मैं आप सभी सदस्यों को जिन्होंनें मतदाताओं का विश्वास प्राप्त किया हैं, अपनी शुभ कामनाएं अर्पित करता हूं तथा कामना करता हूं कि आप सबके सम्मिलित ज्ञान एंव कर्मठता का उपयोग राज्य को प्रगतिशील तथा समृद्ध बनाने की दीशा में होगा।

हाल में ही देश ने युद्ध में विजयश्री प्राप्त की। इस युद्ध को हमें उन सिद्धांतों तथा आदर्शों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा, जिनमें हमारी निष्ठा हैं। इस युद्ध के परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ हैं, जो विश्व के राष्ट्रों में उत्तरोत्तर अपना उचित स्थान प्राप्त कर रहा हैं। बंगला देश को अधिकांश शक्तिशाली राष्ट्रों ने तथा बडी़ संख्या में अन्य देशों ने मान्यता प्रदान कर दी हैं। आशा हैं कि इस राष्ट्र के जन्म से इस उप–महाद्वीप में शाति के एक नए युग का आरम्भ होगा।

युद्ध के दौरान हरियाणा के अनेक वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस युद्ध में हरियाणा के 421 सैनिकों न अपने जीवन की परमाहुति दी, और इसके अतिरिकत 663 सैनिक घायल हुए व 75 लापता हैं। हमारे राज्य के सैनाअधिरियों एवम् सैनिकों द्वारा प्राप्त किए गए अनेक शौर्यपदको तथा अन्य पुरस्कारों से उनकी वीरता की यथेष्ट पुष्टि

होती हैं। उन्हें 1 परमवीरचक्र, 21 वीर चक्र तथा 69 अन्य पुरस्कार प्राप्त हैं। यह प्रभावशाली संख्या हैं। राज्य को अपने वीर सेनाधिकारियों एंव जवानों पर गर्व हैं।

इस वर्ष के आरम्भ में मैंने गत विधान सभा के बजट अधिवेशन के अवसर पर दिए गए अभिभाषण में विकास के विभिन्न क्षेंत्रों में राज्य द्वारा की गई प्रगति कीरूपरेखा दी थी। तब से थोड़ा ही समय गुजरा हैं, और यदि इस अभिभाषण में मैं वही बातें दोहराऊ तो यह पुनरावृत्ति मात्र होगी। तथापि, मैं आपकों अधिक महत्तवपूर्ण विभागों द्वारा किए गए प्रमुख विकास कार्यो से सक्षेंप में अवगत करवा रहा हं।

राज्य सरकार का भूमि–सुधारों को अविलम्ब लाने की आवश्यकता में दृढ़ विश्वास हैं, ताकि ऐसी सामजिक एंवम् आर्थिक व्यवस्था की जा सके जिसमें सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। वर्तमान काश्तकारों कानूनों में मौलिक परिवर्तन एंव सुधारो लाने की आवश्यकता हैं। पैप्सू और गैर पैप्सू क्षेत्रों में भी वर्तमान भेद को दूर करने की आवश्यकता हैं। राज्य सरकार उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करेगी।

राज्य में कानून एवम् व्यवस्था की स्थिति लगातार पूर्णतया नियंत्रण में रही। आम चुनावों में हुए भारी मतदान से यह सिद्ध हैं कि पुलिस प्रबन्ध पर्याप्त थे, और इनसे जनता में विश्वास

की भावना उत्तपन्न हुई। पुलिस के लिए संचार के कुशल साधनों की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं, जिनमें उचित स्थानों पर स्थिम और रेडियो–टेलिफोनों और टेलीप्रीटरों से परस्पर सम्बद्ध नियंत्रण–कक्षों की स्थपना भी सम्मिलित हैं। सभी महत्तवपूर्ण पुलिस थानों में रेडियो टेलीफोन पहले लगाए जा चुके हैं।

आर्थिक क्षे़त्र में प्रशसनीय प्रगति हुई हैं। राज्य की चौथी–पंचवर्षीया योजना (1969–74) के लिए आरम्भ में 225 करोड़रूपये नियत किए नए थें, परन्तु विकास की गति गए अनुमान की अपेंक्षा कहीं अधिक तेज हो रही हैं। वर्ष 16969–70 के दौरान योजना खर्च 39.26 करोड़रूपये था और 1970–71 में यह खर्च बढ़ कर 53.18 करोड़रूपये हो गया। वर्ष 1971.72 में इस वर्ष के 77.83 करोड़रूपये हो जाने की संभावना हैं। इस प्रकार योजना के प्रथम तीन वर्षो में170.27 करोड़रू खर्च होने का अनुमान हैं। आशा हैं कि आगामी दो वर्षो में भी प्रगति की यही गति बनी रहेगीं तथा चौथी– पंचवर्षीया योजना के खर्च को बढ़ाकर लगभग 250 करोड़रूपये कर दिया जायेगा। वर्ष 1970–71 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 444रूपये थी जबकि समूचे देश की औसत आय 347रूपये रही। चौथी–पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो में राज्य की वार्षिक वृद्धि दर 15.91 प्रतिशत रही जबकि सारे देश की वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत थी।

राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सिंचाई सुविधाओं के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया, तथा इसके प्रभावशाली परिणाम निकले हैं। जिन महत्तवपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा हैं, उनमें से एक , 13.50 करोड़रूपये की लागत वाली पश्चिमी यमुना नहर आवर्धन परियोजना हैं, जिसका उल्लेख मेरे पिछले अभिभाषण में भी था। जुई उठान सिंचाई स्कीम के रिकार्ड अवधि में पूर्ण होने पश्चात्, अब लोहारू तथा सिवानी उठान सिंचाइ स्कीमों पर कार्य चल रहा हैं। 11 करोंड़रूपये से अधिक लागत वाली लोहारू उठान सिंचाई स्कीमों से हिसार तथा महेन्द्रगढ़ जिलों के सूखा–ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकेगी। सिवानी उठान सिंचाई स्कीम के अधीन जुलाई, 1972 तक 3 पम्प घरों तथा लगभग 100 मील लम्बे जलमार्गों को चालू किए जाने की सम्भावना हैं। अनुमान हैं कि जब जुई, लोहारू तथा सिवानी परियोजनओं को राबी–ब्यास नदियों से सारा वर्ष जल–सप्लाई प्राप्त होगी, जिसके लिए सरकार अथक प्रयत्न कर रही हैं, इनसे प्रतिवर्ष 17 करोड़रूपेय के मूल्य की अतिरिक्त फसलें पैदा होंगी।

कृषि के क्षेत्र में विकास ने सचमुच क्रान्ति पैदा कर दी हैं, तथा जहां पहले खाद्यान्नों की कमी थी अब प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा होने लगा हैं। किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य–सग्रंह कार्यक्रम भी तेज किया जा रहा हैं, तथा इस वर्ष की रबी फसल में लगभग 10 लाख टन गेहूं जमा

करने का अनुमान हैं, जबकि गत वर्षो की फसल के दौरान 7.1 लाख टन गेहूं जमा किया गया था।

राज्य में बड़े तथा छोटे दोनों क्षेत्रों मे औद्योगिक विकास की गति में निरन्तर वृद्धि होती रही हैं।1971–72 के दौरान 1,300 नई छोटी यूनिटों को पंजीकृत किया गया, जबकि 1970–71 की समाप्ति यूनिट विद्यमान थे। सहायक उद्योगों के विकास तथा ग्राम–औद्योगिकरण को विशेष महत्तस दिया जा रहा हैं।

राज्य सरकार 26 जनवरी,1973 से पूर्व सभी गांवो को पक्की सड़को से मिलाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कम समय में अधिक कार्य करने में लगी हुई हैं। हाल ही में पाकिस्तान से युद्ध के कारण कार्य को धक्का लगा, क्योंकि बंगाल–बिहार क्षेत्रों से स्लैक कोयले का परिवहन कठिन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ईटों के उत्पादनों में की हो गई। अब राज्य सरकार अधिक स्लैक कोयला प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न कर रही हैं, तथा इस प्रयोजन के लिए रेलवे प्राधिकारियों को अधिक से अधिक रेल के डिब्बो उपलब्ध करने के लिए कहा जा रहा हैं।

गत वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण की सफलता के पश्चात् हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने बिजली के अधिक से अधिक कनैक्शन देने के लिए प्रयत्न तेज कर दिए हैं। फरवरी,1972 के अन्त में उपभोक्ताओं की कुल संख्या 6,12,511 थी जबकि मार्च, 1967 के अन्त में यह संख्या केवल 3,11,904 थी।

उसी अवधि में नलकूपों की संख्या 20,190 से बढ़कर 1,00,629 हो गई।

अस्पतालों की विभिन्न श्रेणियों के लिए, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य–केन्द्र भी शामिल हैं, प्लान एवम् अमला पैटर्न का मानकीकरण किया गया हैं। सरकार मैंडिकल कालेज, रोहतक को देश की एक प्रमुख चिकित्सा संस्था केरूप में विकसित करने के लिए प्रयत्नशील हैं, और चौथी योजना के अन्त तक मैडिकल कालेज में कुल बिस्तरो की संख्या बढ़कर 1,000 हो जाने की सम्भावना हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों और पंचायती राज संस्थओं को शामिल करने से अत्यधिक लाभ हुआ हैं। यह अनुमान लगाया गया हैं कि इस कार्यक्रम के अधीन पात्र दम्पतियों में से 36.2 प्रतिशत ने किसी न किसी तरीके को अपना कर लाभ उठाया है।

राज्य द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीन के पानी की व्यवस्था करना हैं, विशेषकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों में। आशा हैं कि मार्च 1972 के अन्त तक लगभग 510 गांव में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, जबकि 1970–71 के अन्त तक ऐसे गांव की संख्या केवल 404 थी। इस समस्या का अधिक प्रभावशाली ढ़ग से समाधान करने के लिए एक स्वायत्तशासी गाम्य स्वच्छता बोर्ड संगठित किया जा रहा हैं और यह आशा की जाती हैं कि 1972–73 के दौरान 150

से अधिक नए गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी।

राज्य आवास बोर्ड ने 1972–73 में 1,000 घरों के निर्माण की योजना को पहले ही अन्तिमरूप दे दिया हैं और 1,500 से अधिक घरों के निर्माण के लिए तीन नई योजनाएं तैयार की जा रही है।

राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं और अब हरियाणा भारतीय एंव विदेशी पर्यटकों के पर्यटन मानचित्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा हैं। चण्डीगढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित पिंजौर बाग को नयारूप देकर बहुत ही सुन्दर बना दिया गया हैं। हाल में ही करनाल से लगभग 4 मील की दूरी पर उचाना में एक रमणीक झील कम्पलैक्स सर्वधारण के लिए खोल दिया गया हैं। गुडगांव से कुछ मीलों की दूरी पर सुलतानपुर झील पक्षी–शरण स्थल भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए पहलें ही विशेष आकर्षण का केन्द्र बन चुका हैं।

मैं पुनः आपको अपनी शुभ कामनांए अर्पित करता हूं तथा हृदय से कामना करता हूं कि आने वाले वर्षों में इस राज्य की प्रगति एवं समृद्धि में सार्थक योगदान हो सदैव आपका उद्देश्य रहेगा। जय हिन्द!

सचिव द्वारा घोषणा

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Budget (January) Session,1972, and which have since been asented to by the Governor.

Statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Budget (January) Session,1972, and which have since been Assented to by the Governor.

1. The Haryana Appropriation Bill, 1972.
2. The Haryana Appropriation (No.2) Bill,1972.
3. The Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill,1792.
4. The Haryana Offical Language(Amendment) Bill,1972
5. The Punjab Agriculltural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill,1792.
6. The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) (Haryana Amendment) Bill,1792.
7. The Haryana Rural Sanitation Board Bill, 1972.

नियम 30 के अधीन

Chief Minister (Chaudhry Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That Rule 30 of The Rules of Procedure and Conduct of BNusiness in the Punjab Legislative Assembly as applicabel to the Haryana Vidhan Sabha be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 6th April, 1972.

Mr.Speaker: Motion moved:-

That Rule 30 of The Rules of Procedure and Conduct of BNusiness in the Punjab Legislative Assembly as applicabel to the Haryana Vidhan Sabha be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 6th April, 1972.

Mr.Speaker: Question is:-

That Rule 30 of The Rules of Procedure and Conduct of BNusiness in the Punjab Legislative Assembly as applicabel to the Haryana Vidhan Sabha be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 6th April, 1972.

The motion was carried.

मेज पर रखे गये कागज–पत्र

Chief Minister (Chaudhry Bansi Lal): Sir, I beg to lay on the Table the Apporpriation Accounts of the bGovernment of Haryana for the year 1970-71.

I aslo beg to lay on the Table the report of the Comptroller and Auditor General of India in regard to Government of Haryanafor the year 1970-71

I also beg to lay on the Table the Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1970-71

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

Chief Minister (Chaudhry Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That Shrimati Lekhwati Jain, a member of the haryana Legislative Assembly, who is p[resent in the House, bne elected as Deputy Speaker of House.

Shri Ram saran mital: Sir, I second the proposal made by the Chief Minister.

श्री के0 एन0 गुलाटी0 (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, हाउस के इंट्रैस्ट्र में मैं एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर का इतना काम नही होता हैं। क्योंकि यह सरकार और जनता पर डबल बोझा हैं इसलिये सरकार इस खर्च को बचाये (शोर)

चौधरी बंसी लाल: पहले आप चौधरी रिजक राम से बात तो कर लें।

Mr.Speaker: Motion moved by the Chief Minister and sconded by Shri Ram Saran Chand Mital is

That Shrimati Lekhwati Jain, a member of the haryana Legislative Assembly, who is p[resent in the House, bne elected as Deputy Speaker of House.

Is there any other proposal?

श्री के0 एन0 गुलाटीः मैं यह फिर चाहता हूं.....(शोर)

Mr. Speaker: This is no proposal, आप बैठ जाइये।

Since there is only one proposal before the House that Shrimati Lekhwati Jain be elected as Deputy Speaker, I declare her to have been elected as the Deputy Speaker unanimously.....

(At thsi stage Shrimati Lekhwati Jain, escorted by the leader of the House occupied the seat meant ofr the Deputy Speaker.)

(Thumping from the House)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री राम सरण चन्द्र मित्तल (नारनौल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राज्यपाल को निम्नलिखित शब्दों में एड्रेस पेश किया जाए:

'' कि इस सैशन में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंनें 4 अप्रैल, 1972 को सदन में देने की कृपा की हैं ''

अध्यक्ष महोदय, चुनावों के बाद इस विधान सभा का यह पहला अधिवेशन हैं। राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने इस

बात की चर्चा की हैं कि हरियाणा में 35 लाख मतदताओं ने वोट दिये जिनका अनुपात 70 प्रतिशत बनता हैं। गर्वनर साहब ने इस बात को भी बड़ी सराहना की कि यहां बड़े शन्ति पूर्वक ढंग से चुनाव हुए।

(इस समय चौधरी हरद्वारी लाल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः क्या आप प्वांयट आफ आर्डर के लिये खड़े हुए हैं ?

चौधरी हरद्वारी लालः जी हां, प्वांयट आफ आर्डर ही समझ लिजिये। यह बड़ी गम्भीर सी बात हैं कि श्रीमति लेखवती जैन के डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर हमें बधाई देने का मौका भी नहीं मिला।

श्री अध्यक्षः अब तो दूसरा विषय शुरू हो चुका हैं।

श्री राम सरन चंद मित्तलः अध्यक्ष महोदय, बधाई देने के लिये आप चाहें मो समय दे दें, इसमें कोई हर्ज भी नही हैं।

श्री अध्यक्षः अगर आप सब की ऐसी राय हैं तो ठीक हैं।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन (बधाई भाषण)

गृहमन्त्री(श्री के0 एल0 पोसवाल): स्पीकर साहब, बहिन जी के डिप्टी स्पीकर चुने जाने मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारी विधान सभा में अगर सबसे पुराने लैजिस्टर हैं तो बहिन जी हैं। जब मैं तीसरी जमात में था तो आप पहली दफा सन् 1933 में इलैक्ट हुई थी। तब से लेकर अब तक ये लगातार इलैक्ट होती रही हैं और एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी हैं। मैं इनको एक बार फिर बधाई देता हूं।

चौधरी हरद्दारी लाल(बहादूरगढ़): स्पीकर साहब, अच्छी रवायत तो यह हैं कि सर्वसम्मति से स्पीकर मुन्तखिब हों और सर्वम्मति से ही डिप्टी स्पीकर मुन्तखिब हों। अपोजीशन की तरफ से इस रवायत को निभाया भी गया हैं लेकिन मुख्य मंत्री साहब ने इस बात को मुनासिब नहीं समझा कि अच्छी रवायत यहां पर जारी रखी जाये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं हैं कि मैं किसी तरह से बहन जी को मुबारिकबाद देने में पीछे रहूं। यह बिल्कूल सही हैं जैसे पोसवाल साहब ने फरमाया जैसे कहा करते हैं। father of House. She is probable the mother of the House. तो यह वाकई ठीक हैं। श्री पोसवाल जी ने कहा कि वह तीसरी जमात में पढ़ते थे जब बहन लेखवती जी पहली बार 1933 में मैंम्बर इलैंक्ट हुई थी। मैं भी उस वक्त स्पीरक साहब किसी जमात में हीं था स्कूल में या कालेज में, मेरा ख्याल हैं कालेज में मुश्किल से हूंगा जब श्रीमति लेखवती जैन पहली बार मुंतखिब हुई थी बतौर एम0 एल0 ए0 पंजाब के अन्दर। स्पीकर साहब बहुत कम ऐसे मैम्बासप हैं जो

हर टर्म के बाद मुन्तखिब होते हैं, मैं भी उन में से एक हूं, मैं भी कई दफा आ चुका हूं लेकिन मैं थोड़ी–थोड़ी टर्म के लिए आता रहता हूं। हमारी डिप्टी स्पीकर साहिबा हमेशा कमीयाब होती जा रही हैं और पिछले कई सालों से हम इनको डिप्टी–स्पीकर के ओहदे के फरायज संरअंजाम देते हुए देखते आ रहे हैं, और जिस ढंग से, जिस खुशअसलूबी से इन्होंनें अपने फरायज को निभाया उसकी सभी तारीफ करते हैं। स्पीकर साहिब शायद हमारे मुख्य मंत्री साहिब सुन नही सकें मैंने पहले यह कहा था कि अच्छी रवायत यह होती हैं कि जैसे सर्वसम्मति से स्पीकर साहब मुन्तखिब हुए थे उसी तरह से यकजहती से आपोजीशन की तरफ से डिप्टी स्पीकर बना देते तेा बेहतर होता।

Chief Minister (Chaudhry Bansi Lal): You are too late to suggest this.

चौधरी हरद्वारी लालः खैर वह चीज तो हो चुकी है। बहरलाल जिस ढंग से उन्होंनें आज तक इस ओहदे के फरायज को सरअन्जाम दिया उसके पेशेनजर में तह लिउ से उनको मुबारिबाद देता हूं और इसके साथ ही लीडर आफदी हाउस को भी मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंनें इस ओहदे के लिए अपनी पार्टी से एक ऐसे मैंबर को सिलैक्ट किया जो कि इस ओहदे के लिए निहायद ही मौजूं हैं। मैं फिर तहे दिल से उनको मुबारिकबाद देता हूं।

उपमंत्री (श्रीमति शारदा रानी): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बहन जी को आज इस हाउस की डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर बधाई देती हूं और जैसा कि मुझ से पहले हमारे आनरेबल मैम्बर्ज ने बताया वह इस हाउस की बहुत पुरानी समय से सदस्य हैं और बहुत पुरानी सोशल वर्कर हैं। इसके साथ ही साथ पीछे जब वह डिप्टी स्पीकर रहीं तो उन्होंनें अपने कर्तव्य को बहुत मजबुती के साथ निभाया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि जहां उन्होंनें मजबूती के साथ अपने कर्तव्य को निभाया वहां पर मधुरता में भी कम न थी। तो मैं इन शब्दों के साथ सब बहनों की ओर से उनको हृदय से मुबारिकबाद देती हूं।

पण्डित चिरंजीव लाल शर्मा(सोनीपत): जनाब स्पीकर साहब,आपोशन के आनरेबल मैंबर चौधरी हरद्वारी लाल जी ने कहा हैं कि ट्रैयरी बैचिज को अपोजीशन का डिप्टी स्पीकर इलैक्ट करके फराख दिली का सबूत देना चाहिए था। स्पीकर साहिब यहां पर गर्वनर साहिब के एड्रैस पर मोशन आफ थैंकस पर मित्तल साहिब ने बोलना शुरू कर दिया था लेकिन चौधरी हरद्वारी लाल जी के प्वांयअ आऊट करने पर उसको ड्राप कर आप ने डिप्टी स्पीकर साहिबा को मुबारिकबाद देने के लिए हाउस को मौका देकर फराखदिली दिखाई। चौधरी साहिब ने दूसरी बात के लिए फराख दिली दिखाने के लिए कह दिया कि आपोजीशन से डिप्टी स्पीकर इलैक्ट किया जाना चाहिए था But, the Opposition did not have the guts to put up therir candidate. उन्होंनें अपना

कोई कैंडीडेट परोपोज नही किया, अगर वह परोपोज करने का हौसला करते तो शायद ट्रैयरी बैंचिज वाले फराख दिली का सबूत दे देते खैर स्पीकर साहिब यह तो मैंने वैसे ही उनकी बात का जवाब दे दिया। मैं बहन लेखवती जैंन के डिप्टी स्पीकर चुने जाने पर उनको बधाई देता हूं। उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं हैं और वह वैटिरन पार्लियामैंटिरियन हैं और जैसा कि मुझ से पहले भी बताया जा चुका हैं वह सब से पुरानी मैंबर हैं। वह पंजाब के वक्त में अपर हाउस की डिप्टी चेयरमैन भी रही हैं और बड़ी खुशअसलूबी से अपने फरायज सरअंजाम देती रही हैं। मैं उनके चुनाव पर उनको मुबारिकबाद पेश करता हूं और इस के साथ–साथ लीडर आफ दी हाउस को भी मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंनें इतनी अच्छी सिलैक्शन की हैं।

श्रीमति लेखवती जैन (अम्बाला): स्पीकर साहिब, आज सदन ने मुझे डिप्टी स्पीकर इलैक्ट किया हैं जिसके लिए मैं सदन की बहुत अभारी हूं और आप सबका बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। इस के अलावा मैं अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लीडर चौधरी बंसी लाल जी की आभारी हूं कि उन्होनें इस हाउस में मुझे दोबारा डिप्टी स्पीकर चुना हैं । स्पीकर साहब मैं आपके द्वारा सारे हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूं कि आप जब कभी भी मुझे उस कुर्सी पर बैठने का मौका देंगे मैं हाउस के कार्य को ठीक तरह से चलाने का पूरा–पूरा यतन करूगीं और हाउस के डैकोरम को कायम रखूगी। इन शब्दों के साथ में फिर हाउस का

बहुत –बहुत धन्यवाद करती हूं कि और आप सबकी अभारी हूं कि आपने मुझें दोबारा इस हाउस की डिप्टी स्पीकर चुना हैं और इस रवायत को कायम रखा हैं जैसा कि अक्सर इलैक्शन के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उनका दोबारा ओहदा जाता हैं।

श्री के0 एन0 गुलाटीः स्पीकर साहिब, मैंने कुछ अमैंडमैंट्स लिखकर दी हुई हैं वह हाउस में आनी चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए वे सब आएंगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम सरन चंद मित्तलः स्पीकर साहब, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर थैंक्स के प्रस्ताव पर स्पीच शुरू की थी। गर्वनर साहिब के एड्रैस में मुझें दो तीन बातें बहुत अच्छी नजर आई हैं, इसका यह मतलब न समझा जाए कि बाकी का एड्रैस अच्छा नहीं हैं, बाकी का सारे का सारा भाषण जो उन्होंनें दिया हैं अच्छा हैं। उन्होंनें इस बात की बहुत सराहना की हैं कि हमारी स्टेट में बड़े पीसफूली और औरडलीं तरीकें से इलैक्शन हुए हैं और 70 फीसदी वोट डोले गए हैं और बाद में उन्होंनें बताया कि इससे यह इन्फ्रेंस निकलता हैं कि हमारे सूबे में ला एंड आर्डर की पोजीशन बहुत साऊड हैं। मैं उनकी इस आवजर्वेशन से 16 आने सहमत हूं। बल्कि इससे भी ज्यादा मुझेइस बात का गौरव हैं कि तमाम भारत में जो डैमोक्रेसी ने जोरूट्स ली हैं वह सारे एशिया में एक एग्जैम्पलरी चीज हैं। हमारा भारत संसार में काफी बड़ा मुल्क हैं

और ईस्ट के अन्दर पार्लियामैट्री डैमोक्रेसी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश हैं। यहां पर पार्लियामैट्री डैमोक्रेंसी ने जोरूट्स ली हैं वह आयंदा के लिए हमारे बराईट फ्यूचर का एक फोरटैलर हैं (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) (थम्पिग)। डिप्टी स्पीकर साहिबा, पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था लेकिन वहां पर जो हालात होते रहे हैं वह सब जानते हैं। वहां पर कई सालो सें डिक्टेटरशिप रही और इस के अलावा एशिया के अन्दर जहां–जहां पर भी पार्लियामैंट्री सिसटम एडाप्ट हुआ वह लगभग सब जगह पर फेल हुआ। हमारी कामीयाबी का कारण क्या हैं, इसका कारण यह हैं कि भारत के अन्दर लीडरशिप ऐसे अच्छे नेताओं के हाथों में थी, यहां राज प्रंबध को काम ऐसे अच्छे नेताओं के हाथों में था जिन्हौनें डैमोक्रेसी की जड़ो को मजबूत बनाया। अभी पिछले इन्डो पाकिस्तान बार के अन्दर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान रेडियो से ऐसी फाल्स औरा बेसलैस चीजें ब्राडकास्ट होती थी कि जिसका विश्वास नही किया जा सकता था लेकिन इसके मुकाबले हिन्दोस्तान में हमेशा से सही खबरें दी जाती थी जिसकी कि कन्फर्मेशन बी0 बी0 सी0 वाले भी करते थे। मेरा कहने का मतलब यह हैं कि यहां पर सैसं आफ रिसपांसिबिलिटी जो डिवैलप हुई वह शायद ही किसी एशिऐटिक कंट्री में डिवैलप् हुई हो। हमारे देश की एक बड़ी भारी खुशकिस्मती यह हैं कि हमें एक चेन आफ गुड प्राइमम मिनिस्टर्ज मिली हैं। पहले पंडित जवाहर लाल जी रहे उनके बाद लाल बहादूर शास्त्री जी आये और उनके बाद आजकल मौजूदा प्रधान

मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी जी हैं और इन्होंनें तो सारे संसार में ही भारत का नाम रोशन और ऊंचा कर दिया हैं। मैं पार्लियामैंटरी के प्वांयट आफ व्य से बात कर रहा हूं कि हमारा देश.....

चौधरी रिजक रामः हरियाणा की भी कोई बात कह दो।

श्री राम सरन चन्द मित्तलः चौधरी रिजक राम जी बड़े उत्सुक हैं कि हरियाणा की बात की जाये। चलो मैं हरियाणा की ही बात कह देता हूं ताकि उनकी तसल्ली हो जाये। हरियाणा की इसके अलावा और क्या बात होगी कि मुख्यमंत्री जी का जिस हल्का से चुनाव हुआ वहां खुद नही गये, न वहां जाकर कोई स्पीच की, पोलिंग एंजट काऊंटिग एजंट मुकर्रर नहीं किये और फिर उनके मुकाबले में वह आदमी खड़ा था जो अपने आपको हरियाणा का बहुत बड़ा लीडर कहता हैं। इससे ज्यादा और क्या आप हरियाणा की सुनना चाहते हैं ?

कृषि मंत्री(चौधरी भजन लाल): इतिहास में यह पहली बात हुई हैं।

श्री राम सरन चंद मित्तलः वाकई पहली बात हैं कि कैंडीडेट अपने हल्का में न जाये, स्पीच न करें, पोलिंग एजंट मुकर्रर न करे और मुकाबले में ऐसा आदमी खड़ा हो जिसके बारे में अखबारों में बड़ा जिकर आता था कि हरियाणा का बड़ा स्टालवर्ट हैं लेकिन फिर भी वह कैंडिडेट जीत जाये। इससे ज्यादा हरियाणा की बात आपको क्या मिलेगी जो आप सुनना चाहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था और पार्लियामेंटरी डैंमोक्रेसी के लिहाज से मैं हरियाणा की ही

बात पहले अर्ज कर देता हूं कि अभी जनवरी 1972 में पिछले असैम्बली की एक साल से ज्यादा लाइफ बाकी रहती थी। जो पार्टी आज इन पावर हैं वह पार्टी उस वक्त भी इन पावर थी, जो चीफ मिनिस्टर आज हैं वहीं चीफ मिनिस्टर उस वक्त थें और उस वक्त भी हमारा वहुमत था। 1968 के लिहाज से अगर देखा जाये तो उस वक्त 81 में से 48 हमारे मैम्बर थे और जब अब असेम्बली डिजाल्व हुई तो पार्टी में 54 थे। इसके बावजूद हमारे लीडर्ज ने यह मुनासिब समझा कि जब सारे देश में सिवा यू0 पी0 के चुनाव हो रहे हैं तो यहां भी हो जायें ताकि यह रोज का बार–बार झगड़ा खत्म हो। तो अब आप बताये कि हरियाणा की और कौन सी बात आप देखना सुनना चाहते हैं.....

चौधरी दल सिंहः आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री राम सरन चंद मित्तलः एड्रैस तो मैं चेयरा को ही कर रहा हूं लेकिन आपकी तरफ देख राह हूं (हंसी)

चौधरी रिजक रामः एड्रैस तो उनको ही करें लेकिन इस एड्रैस पर भी कुछ कह दो।

श्री राम सरन चंद मित्तलः चुनाव के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि मुझे इनके बारे में जैसे यह हुये गौरव हैं। आज आप और चुनाव करा कर देख लो यही पार्टी इन पावर रहेगी और इसकी वजह यह हैं कि हमारे यहां प्रापर तरीका से हर काम होता हैं। (चौधरी रिजक राम की तरफ से विघ्न) आप भी उस हरियाणा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे जिसका मैं प्रेजीडैंट हूं । यह जो हमारे रिजक राम जी हैं जब मैं कांग्रेस में प्रेंजीडैंट हुआ तो मैंने इनको जनरल सैक्रेटरी नामीनेट किया था। अब यह अगर छोड़ कर चले गये तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

चौधरी रिजक रामः मित्तल साहब आपको किसने नामीनेट किया था ? यह तो दान में मिली हैं प्रधानगी और चीफ मिनिस्टरी।

श्री राम सरन चंद मित्तलः इनका तजुर्बा बहुत ज्यादा हैं और यह राज्य सभा में भी हो आये हैं(विघ्न) मैं एड्रैस पर ही बोल रहा हूं... ....

उपाध्यक्षः आप चेयर को एड्रैस करें।

श्री राम सरन चंद मित्तलः पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी जिस ढंग से हमारे हा पनप रही हैं चल रही हैं उसके लिये हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों ही बधाई के मुस्तहक हैं और जिस अच्छे ढंग से हमारे हां पार्लियामैंटरी डैमोक्रेंसी काम कर रही हैं आयंदा भी इसकी तरह से करेगी। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि पारलियामैंटरी डैमोक्रेसी में ट्रेजरी का अहम रोल होता हैं अगर अपोजीशन भी होती हैं और इसमें अपोजीशन का बड़ा अहम रोल होता हैं अगर अपोजीशन की तरफ से सही अपोजीशन की स्प्रिट को कैरी आउट किया जाये। मैं चाहता हूं कि हमारे डिबेट्स का हमारे बात करने का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो कि हम ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसे Mother of Parliament कहते हैं उसके स्टैंडर्ड

तक पहुंच जाये और अपनी लोक सभा के ही स्टैंडर्ड पर आकर काम करे बल्कि उससे बैटर रहें। मैं अपोजीशन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह अपना सही तौर पर रौल अदा करें और अगर वह हैल्दी क्रिटिसिजम करे तो उससे गवर्नमैंट को भी फायदा पहुंचता हैं और सारे हाउस को भी फायदा पहुंचता हैं लेकिन अगर महज अपोजीशन की खातिर ही अपोजीशन करनी हो तो अलग बात हैं वरना अपोजीशन का हैल्दी रोल होता हैं और होना चाहिये। डिबेट का स्टैंडर्ड ऊंचा रखना ज्यादातर अपोजीशन के हाथ में होता हैं क्योकि उनकी बात का एक्श्ज्ञन और रीएक्शन होता हैं। राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के इस बात की बधाई दी हैं कि इस जगह बड़े शूरवीर पैदा हुये और यहां के जवानों ने फौजी अफसरों ने इस इन्डो पाकिस्तान वार में बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया हैं। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं। हमारी पिछली विधान सभा इस बारे में एक प्रस्ताव पास कर चुकी हैं और उनके शानदार काम की बहादूरी की तारीफ कर चुकी हैं लेकिन मैं इस मौके पर उनको जो इस लडाई में मैडल मिले हैं और डैकोरेशनप मिली हैं उनके लिये बधाई देता हूं और चाहता हूं कि हरियाणा का यह ट्रैडीशन हमेशा कायम रहे और यह हमेशा से कायम रही भी हैं। हरियाणा की वह भूमि हैं जहां कुरूक्षेत्र के मैदानप में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और हरियाणा के शूरवीरोंने उस पर हमेशा पूरी तरह से अमल किया हैं और करते रहेंगें। जय जवान जय किसान। राज्यपाल महोदय ने कहा हैं कि पिछले बजट सैशन के दौरान उन्होंने जो अभिभाषण दिया था

और जो आउट लाइन दी थी उसे वह दोहराना नहीं चाहते क्योंकि उसमें सारी बाते डीटेल से कही जा चुकी हैं। मैं भी उन सारी बातों को दोहराना नही चाहता। लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आज हरियाणा वह हरियाणा नहीं हैं जो 1966–67 में था। जिस वक्त हरियाणा बना था तो इसेइसे प्राब्लम स्टेट कहा जाता था। यहां बहुत उलट सुलट की बातें की जाती थी और उस वक्त यह समझा जाता था कि हरियाणा की फांयनैशल पोजीशन सांऊड नहीं हैं और पता नहीं वह गवर्नमैंट एम्पालाइज को तनखाहें भी दे सके या न दे सके। लेकिन आज यह हालात हैंकि आज भारत में कहीं भी चले जाओ हरियाणा की तरक्की की बातें होती हैं। जब उनको मालूम होती हैं। जब उनको मालूम होता हैं कि आप हरियाणा से आये हैं तो वह मिल कर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सच हैं कि हरियाणा के हर एक गांव में बिजली चली गई हैं, क्या यह सच हैं कि हर गांव में सड़के पहुंच गई हैं।

चौधरी दल सिंहः क्या यह सच हैं कि कुरप्शन बहुत ज्यादा हैं..... (विघ्न)

श्री राम सरन चंद मित्तलः वह कहते हैं कि यह ठीक हैं कि नहरें ऊपर से नीचे तो जाती हैं लेकिन हरियाणा में नहरें नीचे से ऊपर बहती हैं। मेरे कहने का मतलब यह हैं कि हरियाणा के विकास के कामों की हर जगह तारीफ होती हैं। आप मेरे जिला महेन्द्रगढ़ की ही बात देख लो। हमारे जिले में गेहू इतना भी पैदा नहीं होता

था कि वह हमारे गुजारा लायक ही हो जाये। हमें गेहूं दूसरे जिलों से या दूसरे सूबों से मंगवानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई हैं कि बजाये मंगवाने के बाहर भेज रहे हैं। पिछले साल इतनी ज्यादा गेंहूं हुई कि नारनौल से तकरीबन 53 हजार बोरियां या शायद इससे भी ज्यादा गेहू बाहर गई। मेरा ख्याल हैं कि महेन्द्रगढ़ जिले से तकरीबन 70/72 हजार बोरियां दूसरे जिलों में गई। आप समझ सकते हैं कि यह सब बिजली के विस्तार और कृषि की तरक्की का ही परिणाम ही हैं। जो पहले अनाज के मामले में डैंफिसिट हुआ करती थी वह अब अनाज के मामले में सरप्लस हो गए हैं इसलिए सभी बातों में भरपूर हो गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें सामने हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हैं, विकास के कार्य करने की बहुत गुंजाइश हैं। इन चीजों का जिक्र हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने एड्रैंस में किया हैं। हम चाहते हैं कि कैनाल सिस्टम तमाम हरियाणा में हो जाए। हरियाणा में कोई भी ऐसी जगह न रहें जहां पर कैनाल वाटर न पहुंच पाये। जहां–जहां कुएं खोदे जा सकते हैं वहां कुएं खोदने के लिए सरकार पैसा दें। लेकिन कई जगहों ऐसी होती हैं जहां पर कुए खोदे नहीं जा सकते क्योंकि खुदाई के दौरान चट्टान वगैरा आ जाती हैं और खुदाई मुकम्मल नहीं हो पाती। सिर्फ बिजली का पहुंचना ही इतना फायदा नहीं देता जब तक कुएं गहरे न हों और बोरिंग मशीने कूएं खोदने में किसान की सहायता न करें।

3.00P.M.

इसके अतिरिक्त, हस्पताल काफी बन रहे हैं। करीब–करीब हर डिस्ट्रिक्ट–हैडक्वार्टर, तहसील हैड–क्वार्टर और सब–डिवीजनल हैड–क्वार्टर में अच्छे–अच्छे हस्पताल बन रहे हैं। मेडिकल कालेज रोहतक के हस्पताल को स्ट्राग बना रहे हैं, इसके विकास के लिए कई चीजें पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आयुर्वैदिक सिस्टम को इग्नोर न किया जाए। आयुर्वैदिक सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम हैं, अजमाया हुआ सिस्टम हैं इसको भी इन्करेजमैंट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ गवर्नमैंट की तरफ से आयुर्वैदिक टीचिंग का इन्तजाम जरूर होना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, चूंकि इस समबन्ध में पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका हैं, इसलिए अब मैं इतना कहकर अपना भाषण खत्म करता हूं कि गवर्नमैंट ने हरियाणा का नाम ऊंचा कर दिया और उम्मीद करते हैं कि इसमें दी गई बातें पूरी होंगी जिससे हमारे हरियाणा की तरक्की होगी। मैं इतना ही कहकर गवर्नर साहब के बधाई के प्रस्ताव को सदन के सम्मुख पेश करता हूं।

Deputy Speaker: Now Chaudhri Sarup Singh will second the motion.

चौधरी सरूप सिंह(मुंढाल खुर्द): डिप्टी स्पीकर साहिबा, शुक्रिया अदा करने का जो प्रस्ताव मित्तल साहब ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पेश किया हैं, मैं इसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि सारे आनरेबल मैंम्बर, जो मेरे दोनो तरफ

बैंठे हैं, उनको सबसे पहले बधाई दूं क्योंकि हम सब बड़ी कड़ी आजमाईशो में से निकलकर आए हैं और जनता का विश्वास प्राप्त करके आये है; और जनता ने पांच साल तक इस प्रान्त की सेवा करने के लिए हमें यहां भेजा हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके साथ ही साथ मैं हरियाणा की जनता का भी शुक्रिया करना चाहता हूं जिसने इस चुनाव में बड़ी सूझबुझ दिखाई हैं और एक तरफ एक मजबूत और पायेदार सरकार बनाने का मौका दिया हैं वहां दूसरी तरफ हमारी अपोजीशन के भाइयों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी हैं। जनता ने अपोजीशन के भाई सुलझे हुए पुराने सियास्तदान चुनकर भेंजें हैं, बड़े–बड़े खिलाड़ी हैं। सन्त जी भी भेज दिए, महन्त जी भी भेज दिये और दौलता साहब भी भेज दिये, यह सब सूझबूझ की बात हैं। जब हम हरियाणा की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं वहां हमारा फर्ज बनता हैं कि जनता पर विश्वास रखें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा प्रान्त में हर चुनाव के बाद चुने हूए मैंम्बर एक नई कहानी देश के सामने पेश करते आये हैं।1967 में जब नये मैंम्बर आये तो आपने देखा होगा डिफैक्शन की कहानी सारे भारतवर्ष में हमारे हरियाणा ने दी। सारे भारतवर्ष की नजरें हमारे प्रान्त के तरफ लगी हई थी। उसके बाद दूसरा चुनाव 1968 में हुआ तो हमने डिवैंल्पमैंट की कहानी सारे भारतवर्ष को दी। जितनी तेजी के साथ तरक्की हरियाणा प्रान्त में पिछले चार सालों में हुई उतनी कहीं नहीं हुई और ऐसी मिशाल सारी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। उसके बाद 1972 में तीसरा चुनाव हुआ। इस चुनाव में हरियाणा की जनता ने सूझबूझ दिखाई

उसकी मिसाल कहीं नही मिलती और हमारे कंधो पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी हैं। इस चुनाव के बाद दूसरी कहानी डिफैक्शन की हमने देनी जरूर हैं क्योंकि वह पुरानी रवायत हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इन बुरी रवायात को छोड़ कर हमें चाहिए कि अच्छी राजनीति हरियाणा के अन्दर चलायें, अच्छी राजनीति की कहानी सारे भारतवर्ष को हम दें, इससे हमारा और हमारे देश का सम्मान बढ़ेगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी दोनों तरफ के भाइयों पर हैंरूलिंग पार्टी पर भी और अपोजीशन पार्टी पर भी।रूलिंग पार्टी अपोजीशन पार्टी खयालात करेगी। अपोजीशन पार्टी द्वारा दिये गए सुझावों में जान हो, वजन हो, उस वजन कोरूलिंग पार्टी समझें। दूसरी तरफ अपोजीशन सिर्फ महज अपोजीशन करने की खातिर नुक्ताचीनी न करे। ठीक हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपोजीशन करना तो डेमोक्रेसी के अन्दर अपोजीशन पार्टी का काम हैं लेकिन हल्दी अपोजीशन हो, कंस्ट्रक्टिव नुक्ताचीनी हो और सुझावों के साथ हो ताकि सारे एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकें। हरियाणा प्रान्त आगे बढ़े, हमारा नाम ऊंचा हो अगर इस उद्देश्य को सामने रख करा नुक्ताचीनी की जाए तो अपोजीशन भी अपना रोल ठीक ढंग से अदा कर सकती हैं। अगर इस ढंग से हम चलें तो मेरा विश्वास हैं, हरियाणा में सच्ची राजनीति का जन्म हो सकता हैं क्योंकि अब तक बहुत से भाई यही समझते आये हैं कि राजनीति झूठे और बेईमानी का नाम हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अच्छी और ऊंचे दर्जे की राजनीति सच्चाई और ईमानदारी से चलती हैं। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी की

कदर करना सीख जाए, एक दूसरे पर विश्वास करें, पूरी तरह से कोआप्रेशन तो दें मैं समझता हूं कि तीसरी कहानी भी हम सारे भारतवर्ष को दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय का भाषण मैंने पढ़ा हैं, भाषण छोटा बहुत हैं लेकिन छोटा होने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं हैं, इसके अन्दर मसाला बहुत थोड़ा हैं, ऐसी बात नहीं हैं। इस छोटे से भाषण में हरियाणा के डिवैल्पमैंटरूपी दरिया को कूजे में बन्द कर दिया हैं। एक साल की तरक्की इसमें दर्ज हैं। इसके साथ–साथ आने वाले पांच–छः सालो में हमने क्या करना हैं इस तरफ इशारा भी किया गया हैं। गवर्नर साहब ने सबसे पहले, डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछली लड़ाई का जिक्र किया हैं जो 1971 में होकर हटी हैं। वैसे तो आजादी के बाद हमारे देश ने तीन लड़ाईयां लड़ी हैं लेकिन जितनी मजबूती से हमारा देश 1971 की लड़ाई को लड़ कर कमीयाब हुआ उतना पहले कभी नही हुआ हैं। जितना आत्मविश्वास इस लड़ाई की वजह से बढ़ा हैं, जितनी एकता कि मिसाल इस लड़ाई के दौरान हमारे देश ने दिखाई हैं, ऐसा नजारा कभी पहले देखनें में , डिप्टी स्पीकर साहिबा, आया नहीं था। इस लड़ाई ने न सिर्फ हमारा भरोसा बढ़ाया हैं और न सिर्फ हमारे देश को मजबूत किया हैं बल्कि हमारा मान और इज्जत भी दूसरे देशों के निगाहों मे बढ़ी बड़ी हैं। आज हमारी गिनती चोटी के और मजबूत से मजबूत देशो के अन्दर होने लगी हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस लड़ाई में हरियाणा प्रान्त का भी बहुत बढ़ा हिस्सा हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हरियाणा प्रान्त जहां ऋषि

मुनियों की धरती रही हैं वहां वीरो की जन्म भूमि भी रही हैं। हरेक लड़ाई में हमने बहुत अहम रोल अदा किया हैं और इस लड़ाई में तो खासकर जैसा कि राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया हैं कि हमारे बहुत से वीरों ने बढ़–चढ़ कर कुर्बानी दी हैं। 421 जवानों ने अपने कीमती जीवन की आहुति दी इस देश की खातिर, आपकी और हमारी हिफाजत की खातिर और उन आदर्शों की खातिर जिन पर हमारा देश कयाम हैं। हमारे बहुत से जवान घयाल भी हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, लड़ाई में वीरता दिखाने की वजह से बहादूरों को जो बड़े–बड़े इनाम मिले हैं उनमें भी हमारा हिस्सा रहा हैं जैसा कि आप गर्वनर साहब का अभिभाषण पढ कर अन्दाजा लगा सकते हैं। बड़े–बड़े इनाम भी और दूसरे इनाम भी हमारे वीरों को प्राप्त हुए हैं। हमें अपने वीरों की कुर्बानी पर बड़ा भारी गौरव हैं। उनका नाम हम बड़ी इज्जत से लेते हैं। उनके और उनके परिवारों के प्रति जो भी सरकार की जिम्मेदारी हैं उसे सरकार पूरी तरह से संभालने के लिए तैयार हैं जैसा कि आपने पिछले सैशन में बहुत सी बातें सुनी थी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज से 20/25 साल पहले जब हम आजाद हुए और जम्हुरियत ने भारत में जन्म लिया, डैमोक्रेसी की स्थपना इस देश में हुई तो शुरू–शुरू में हमारे नेताओं और हमारे विधायकों की जिम्मेदारी कुछ और किस्म की थी। उस समय तो हमने देश को मजबूत करना था,संगठित करना था, अपने पांव पर खड़ा करना था और दूसरे देशों पर जो हम बहुत दिनों से निर्भर

रहते थे उस बात को हमेशा के लिए छोड़ना था लेकिन आज 20/25 साल के बाद अगर हम देखें तो हमारी जिम्मेवारियां कुछ बदल गई हैं, हमारे कर्त्तव्य भी कुछ और हैं और हमारे काम भी कुछ और हैं। अब हमारे सामने हरेक प्रान्त के अन्दर बहुत से प्रान्तीय मसले आ खड़े हुए हैं जिनको हमने हल करना हैं, बहुत बहादूरी से हल करना हैं, साहब से हल करना हैं और बड़े प्रेम से उनको सुलझाना हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अच्छी तरह से जानती हैं कि 1966 में जब हरियाणा प्रान्त बना तो इसकी क्या हालत थी और यह कैसे बना था। यह कहा जाता था कि बचे–खुचे इलाके नए प्रान्त की शक्ल में आए हैं। न यहां पानी हैं, न रोशनी हैं, न सड़के और न यहां पैसा हैं कुछ भी नहीं हैं। यह एक गरीब और टूटा हुआ प्रान्त था। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मसला गरीबी दूर करने का हैं। इस गरीब प्रान्त की गरीबी को मिटाना हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा काम हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरी बात , जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सारे हाउस का, वह हैं बेरोजगारी। ज्यों–त्यों तालीम बढ़ती हैं, लिखे–पढ़े नौजवानों के अन्दर बेरोजगारी भी बढ़ती हैं। प्रान्त हमारा छोटा हैं, सरकारी नौकरियां थोड़ी हैं, तालीम हम बढ़ा रहे हैं, तो बेरोजगारी का फैलाना कुदरती हैं। इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। बेरोजगारी के मसले को किस तरह से सुलझना हैं, आया इस तलीम के ढांचे को बदलकर सुलझना हैं या और ज्यादा नौकिरयां बना कर

लिखें–पढ़े नौजवानों को उन पर लगाना हैं, यह सारा काम इस सरकार के जिम्मे हैं। आने वाले पांच साल के अन्दर इस मसले को हल करना हैं। जहां तक अनपढ़ लोगों के अन्दर बेरोजगारी का ताल्लुक हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं और हरियाणा प्रान्त की जनता भी अच्छी तरह जानती हैं कि ये जो तरक्की के काम हुए इनसे हमारा बेरोजगारी का मामला बहुत हद तक हल हो गया हैं। जो अनपढ़ हैं उनको रोजगार मुतवातिर मिल रहा हैं और हम तो यहां तक देख रहे हैं कि हमारे प्रान्त के अन्दर काम करने वाले दूसरे प्रान्तों के भाई आते हैं। हमारे प्रान्त के अन्दर कोई ऐसा बेरोजगार नजर नही आता जो अनपढ़ हो और जिसको काम न मिलता हो।

तीसरा मसला, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे यहां गन्दगी को दूर करने का हैं आप अच्छी तरह जानती हैं कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर बड़े–बड़े शहर नहीं हैं। यह एक पिछड़ा हुआ प्रान्त था और इस पिछड़े हुए इलाके की तरफ पंजाब के अन्दर भी ध्यान नहीं हुआ। यहां या तो आमतौर पर गांव हैं या छोटे–छोटे शहर हैं, उनके अन्दर छोटे–छोटे मुहल्ले हैं, जो बड़े गन्दे हैं। उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। गांव की सफाई की तरफ और शहर के मुहल्लों में जहां गरीब लोग बसते हैं, हमारे हरिजन भाई और पिछड़ी जाति के भाई रहते हैं उनकी सेहत की तरफ हमें देखना हैं। उन मुहल्लों की सफाई की तरफ यदि हम देखेंगें तो

उनको एक नई जिन्दगी मिलेगी। यह काम भी हमारी सरकार के सामने हैं।

चौथी बात, जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और जो सबसे बड़ा काम हैं हरियाणा प्रान्त में वह हैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, पीने की पानी का काम। पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार पिछले तीन साल से लगी हुई हैं और राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में उसका अच्छे ढंग से जिक्र किया हैं। हरियाणा प्रान्त के अन्दर लोगों को अगर पीने का पानी न मिलें तो फिर हम उनकों कैसे कहेगें कि यह आजाद देश हैं और 25 साल आगे बढ़ चुके हैं। यह तो सबसे पहली जरूरत हैं कि मनुष्य को पीने का पानी मिले, खाने के लिए रोटी मिले और रहने के लिए मकान मिले। इस वास्ते यह जो आवश्यकता हैं आम लोगों की उसको हमने जल्दी से जल्दी तेजी के साथ के साथ पूरा करना हैं। खेती के पानी का जहां तक सम्बन्ध है, हरियाणा प्रान्त जिस वक्त बना उस वक्त पानी हमें बटवारे के हिसाब से मिला था। और उस वक्त हरियाणा प्रान्त का कुछ हिस्सा नहरी और बाकी हिस्सा बरानी था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बारानी हिस्से के अन्दर जो लोग रहते थें, उनमें से हमारे हाउस के लीडर हैं वे एक हैं और मित्तल साहब, जिन्होनें यह प्रस्ताव शुक्रिया का पेश किया है वे भी उसी इलाके के रहने वाले हैं। इन्होंनें देखा कि सारी उमर उन लोगों की कैसी गुजरती थी । खेती के पानी का तो सवाल ही नहीं मगर इन इलाकों में न तो

मवेशी जिन्दा रह सकते थें और न ही लोग। गर्मियों के कुछ महीनों में आदमी अपने घरों को छोड़कर दुसरे हिस्सों में चले जाते थें। तो इस काम को भी हमें करना हैं। खेती के पानी की बड़ी कमी थी। इस काम को पूरा करने के लिए भी सरकार ने पिछले तीन सालों में कुछ योजनांए बनाई हैं । हमारे राज्यपाल ने इसका विशेषता के साथ जिक्र भी किया हैं। एक तो दिल्ली पैरलल नहर हैं जो जमन गर्बी के साथ बनेगी। साढे तेरह करोड़ या पन्द्रह करोड़रूपये की वह स्कीम हैं। और भी कई योजनाएं हैं जैसे लोहारू कैनाल, इन्दिरा गांधी नहर और सिवानी नहर। व्यास का जो पानी हमें मिलेगा, हमारा हिस्सा जो होगा, उसकी हरियाणा प्रान्त के सूखे गांवों तक पहुंचाने का बन्दोबस्त करने के लिए भी एक बहुत बड़ी नहर हमें निकालनी पड़ेगी।

उसका बन्दोबस्त अभी जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योकि मैं समझता हूं अगर हम हरियाणा प्रान्त के अन्दर खेती के पानी को नही बढ़ाते हैं तो हमारी पैदावार भी नहीं बढ़ सकती हैं। जब तक हम पैदावर नहीं बढ़ायेंगें तब तक गरीबों के मैयारे जिन्दगी को भी ऊंचा नहीं उठा सकते। इसलिए आज के समय में यह बड़ा मुश्किल काम हैं, बड़ा भारी मासला हैं। हमें पानी की कमी को पूरा करना हैं और हमारी सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए ध्यान के साथ लगी हुई हैं। मैं तो यह चाहंता हूं कि यह काम और भी अधिक तेजी को साथ किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक पांचवा मसला भी हैं जो हरियाणा की जनता के सामने हैं वह हैं अमीर और गरीब के फर्क को मिटाना। पहले तो गरीबी को कम करना हैं और उनको बराबर की सतह पर लाना हैं। यह तो आप डिप्टी स्पीकर साहिबा अच्छी तरह जानती ही हैं कि हरियाणा प्रान्त गरीब लोगों का हैं लेकिन फिर भी बड़े–बड़े धनाढ्य लोग आकर बसें हैं, हमें खुशी हैं वें बसें, कोई उनके बसने मेंरूकावट नहीं हैं और न ही हमेंरूकावट डालनी हैं। वे यहां पर अपने कारखाने लगायें ताकि हरियाणा की तरक्की हो। लेकिन इसके साथ–साथ हम यह जरूर चाहते हैं कि जो मयारे–जिन्दगी गरीब लेागों का हैं, जो आम तौर पर झोपड़ी और कच्चे मकानों में रह रहे हैं उसका अन्तर बहुत कम होना चाहिए ताकि हमें यह एहसास हो कि हमने पुराने नक्शे को बदल दिया हैं। आज यहां पर जो कारखाने लगाते हैं और अमीर ठाठ दिखाते हैं यह फर्क दिखायी मिटाना चाहते हैं चाहे वह तन्खाह का फर्क हो, चाहे कमायी का फर्क हो अर्थात किसी भी ढंग का हो हमें उसमें सुधार करना ही पड़ेगा। जैसे कि जमीन का फर्क हैं किसी के पास अधिक हैं किसी के पास बिल्कूल नहीं हैं उसमे सुधार लाने की आवश्यकता हैं। इसी प्रकार से शहरी जायदाद हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा। हमें इन चीजों में सुधार लाने लिए हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी ने एक समाजवाद का रास्ता दिखाया हैं जिस पर हमें चलना हैं। हरियाणा प्रान्त की जिस तेजी के साथ पिछले चार सालों में तरक्की हुई हैं, सब प्रान्तों से

अधिक तरक्की करके दिखायी हैं उसी प्रकार से आने वाले सालों में भी हमें करनी हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, राज्यपाल महोदय ने जहां ऊपर कही गयी बातों की चर्चा अपने भाषण में की हैं वहां उन्होनें एग्रीकल्चर के मुताल्लिक भी कहा हैं। एग्रीकल्चर के अन्दर भी हमारे प्रान्त ने बड़ी भारी तरक्की हैं। जब हमारा हरियाणा प्रान्त बना उस वक्त हमारे पास एक बाजरे और दूसरे चने की फसल ही ऐसी थी जो मशहूर फसलें थी परन्तु जैसा कि सभी साथियों को मालूम होगा कि अब हम चावल और गन्दम के अन्दर भी सरप्लस होते जा रहे हैं। यह तरक्की की एक बड़ी भारी निशानी हैं । इस निशानी के पीछे भी एक बड़ा कारण हैं वह यह हैं कि पिछले चार सालो के अन्दर हरियाणा प्रान्त में ट्यूबवैलों का जाल बिछा दिया गया हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप करनाल जिले के अन्दर जाइये। करनाल जिले के चार–पांच साल पहले जो हालत थी उससे मुखतलिफ ही नजर आयेगी। आज करनाल जिले के अन्दर ट्यूबवैलौं का जाल बिछा हुआ हैं। आज वह खेती पानी के लिहाज से और दूसरी इरीगेशन फैसेलिटी के लिहाज से काफी उन्नति पर हैं। कहने का मेरा मतलब यह हैं कि वहां आज हजारों ट्यूबवैल चलतें नजर आ रहे हैं। हमने सारे प्रान्त के अन्दर बिजली सप्लाई करके जो पहल की हैं उसकी बदौलत ही हमारा प्रान्त सब प्रदेशों से आगे जा रहा हैं। इस हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश हैं जिसने सब से पहले अन्धेरें को रोशनी में बदला

हैं। कुछ भाई तो उस टाईम पर यह समझाते थे कि इस बिजली से गांव का कोई लाभ नहीं होगा परन्तु आप जानती हैं कि बिजली एक ऐसी ताकत हैं जिससे आजकल कि जिन्दंगी की सारी जरूरियात पूरी होती हैं। आज सस्ते दामों के अन्दर अच्छे से अच्छी चीज बिजली के जरिए पैदा की जा सकती हैं। आज बिजली से कारखानों चलते हैं, खेती के अन्दर काम सारा बिजली से होता हैं, क्योंकि बिजली की बदौलत ही ट्यूबवैल से पानी दे सकते हैं। बिजली से घरों के अन्दर रोशनी होती हैं, बिजली की रोशनी बच्चों की पढ़ाई ठीक होती हैं। यह सारी नेमतें, यानी दुनियां की बड़ी से बड़ी नेमत हरियाणा प्रान्त ने सब से पहले गरीब लोगों को दी हैं। इसके बाद हरियाणा प्रान्त के अन्दर आमतौर से जो झोंपड़ियों में और कच्चे मकानों में रहते थे, रेत और दलदल के अन्दर चलते आये थे, जो अपने सिरों पर एक–एक मन की गठरी रख कर चलते थे उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए हरियाणा प्रान्त के हरेक गांव को पक्की सड़क के साथ जोड़ने का फैसला किया हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप खुद जानती हैं और अम्बाला जिला तो आपका घर भी हैं। अम्बाला जिलों के बीचों बीच जो सड़क निकाली हैं वह अम्बाला जिले के लोगों को एक प्रकार से नया जीवन देगी। इस तरीके से यातयात की सुविधायें सरकार की ओर से दी जा रही हैं और भविष्य में भी अधिक दी जायेंगी। सैंकड़ो सालों से लोग इस परेशानी का सामना करते आये हैं, इस सरकार ने उनकी परेशानी को हमेशा के लिए खत्म

कर दिया हैं। आज लोगों के घरों के दरवाजे के सामने से पक्की सड़के गुजरती हैं। जो सड़के अभी तक बन पायी हैं उनके लिए सरकार का प्रोग्राम हैं कि अगले साल 23 जनवरी,1972 तक सब की मुकम्मल हो जायेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि हरियाणा सरकार बधाई के पात्र हैं। यह काम ऐसा हैं जो कि एक मुहं बोलती खुद तस्वीर हैं। इसके विषय में किसी को कहने की जरूरत नहीं हैं। कोई भाई माने या न माने परन्तु यह बड़ा भारी काम किया जा रहा हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अब हम न मानने वाली इसी बात खत्म करना चाहते हैं। हरेक आदमी अपने प्रान्त से बाहर जाता हैं और हम भी दूसरे प्रान्तों में जाते हैं। परन्तु जब दूसरे प्रदेश का आदमी हरियाणा की बाउण्डरी में आ जाता हैं तो उसको उसी समय यह पता लग जाता हैं कि वह अब दुसरे प्रान्त में दाखिल हो गया हैं। हमारे यहां जब यह देखता हैं उस प्रान्त के गांव में अन्धेरा और हमारे प्रान्त के गांव में रोशनी हैं। हमारे यह ट्यूबवैल का पानी और उनके प्यासे खेत हैं। तो इस प्रकार से यह सभी मुंह बोलती तस्वीर हरियाणा की तरक्की की हैं। इसलिए गर्वनर साहिब ने जिन बातों का अपने एड्रैस में जिक्र किया हैं वे सभी ठीक हैं।

इसके आलाव जहां तक गन्दगी का ताल्लुक हैं उसके विषय में भी थोड़ा सा अर्ज कर दूं। हरियाणा प्रान्त एक पिछड़ा हुआ प्रान्त था। पहले किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हरियाणा बनने के पश्चात् हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में उन्नति

करने के लिए ध्यान दिया हैं। हरियाणा प्रान्त बनने के पश्चात् बड़े–बड़े रैस्ट हाउसिज बनाये गये हैं। ये रैस्ट हाउसिज सरकारी कर्मचारियों के लिए, आनरेबल मैम्बर्ज के ठहरने के लिए और आम आदमी के लिए बनाये गये। जब भी वे कहीं जायें, किसी जगह पर इकट्ठे हों, किसी सम्मलेन में, किसी मीटिग में तो वे आराम से ठहर सकें। बड़े–बड़े गांवो के अन्दर भी सरकार ने पार्क तब बनाये हैं। हरियाणा की जनता के सामने एक नया नक्शा दिया हैं ताकि नयी जिन्दगी बसर करने का एहसास हो, वे महसूस करें कि हरियाणा प्रान्त देश के दूसरे प्रान्तों से आगे हैं। आज हरियाणा एक चोटी का प्रान्त माना गया हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, आज से पांच साल पहले जब हरियाणा प्रान्त नही बना था तो उस वक्त जब हरियाणा के लोग आते थे तो उनको ठहरने तक के लिए जगह नहीं मिलती थी और उनको हिकारत की नजर से देखते थे। उनसे हाथ मिलाना या उनसे गले मिलना तो–दर–किनार, उनसे बात करना भी अपनी शान के शायां नहीं समझते थे। आज हरियाणा प्रान्त के अन्दर एक बदला हुआ नक्शा नजर आ रहा हैं। यहीं नहीं, सारा ढांचा ही तबदील होता जा रहा हैं। क्या गांवो में, क्या शहरों में, क्या सड़को में, क्या घरों में, क्या सरकारी इमारतों में, जहां भी हम जायें हमें तबदीली ही तबदीली होता जा रहा हैं मतलब यह कि एक इन्कलाब नजर आता हैं। जिस तरफ भी हम देखें, चाहे कालेजो की तरफ देखें, अस्पतालों की तरफ देखें, यूनिवर्सिटियों की तरफ देखें, या रैस्ट हाउसिज की तरफ देखें, सब तरफ नक्शा ही बदला हुआ हैं।

चौधरी हरद्वारी लालः स्कूलों की तरफ भी देखें।

चौधरी सरूप सिंहः यह मसला तो मैंने चौधरी हरद्वारी लाल जी के लिये छोड़ा हुआ हैं क्योकि यह ऐजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। हमें तो केवल यह देखना हैं कि ये जहां पर काम को छोड़ गये थे, हम वहां से कितने ऊपर पहुंच पाये हैं। हरियाणा प्रान्त की जो तस्वीर हमारे राज्यपाल महोदय ने इस भाषण के अन्दर खीचीं हैं, मैं समझता हूं वह बड़ी शनदार हैं इस छोटे से भाषण के अन्दर उन्होंनें सारे हरियाणा प्रान्त की तरक्की का एक नक्शा सा बाध कर रख दिया हैं। जहां तक आगे कि तरीकी का ताल्लुक हैं, उसके बारे में भी तेजी करनी चाहियें। यह जो फर्क हैं कि पैप्सू के इलाके में कुछ मुख्तलिफ कानून लागू हैं और हरियाणा प्रान्त में जो पहले पंजाब का इलाका था, में कोई दूसरा कानून लागू हैं, इस फर्क को मिटाना चाहिए ताकि लोगों के अन्दर यह विश्वास बढ़ जाये कि यह सरकार भेदभाव समाप्त करना चाहती हैं। उनके अन्दर बराबरी का भाव आये और हम यह कह सकें कि अमीर और गरीब का फर्क मिटाने की तरफ हम बड़ी तेजी से चले हुए हैं।

इसके साथ ही मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां हमारा ध्यान लैंड रिफार्मज की तरफ जाना चाहिए वहां शहरी जायदादों की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक हैं क्योकि हम गांव को शहरों के बराबर रखना चाहते हैं। हम किसरी से भी ना–बराबरी का सलूक नहीं करना चाहते। हम यह नहीं चाहते कि

शहरों के अन्दर बड़े–बड़े धनाढ्य पनपते रहें। वे धनाढ्य बनते रहें। इसलिये शहरी जायदादों की कोई सीलिंग मुकर्रर करना भी बहुत जरूरी हैं। मैं समझता हू कि आने वाले सालों के अन्दर ये दोनो चीजें साथ–साथ चलेगीं। एक बात की ओर मैं इस आगस्ट हाउस का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। वह यह हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हरियाणा के अन्दर डैमोक्रेसी फले और फूले, अगर हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रान्त एक चोटी का प्रान्त बने, अगर हम चाहते है कि हरियाणा प्रान्त एक चोटी का प्रान्त बनें, अगर हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रान्त के लोंगों को एक नई जिन्दगी मिले तो हरेक आदमीः चाहे वह विधायक हो चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह खेत में काम करने वाला हो या चाहे दुकानदार हों, हरियाणा प्रांत के हरेक रहने वाले को यह सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि क्या वह अपने कर्तव्यो का पालन सच्चाइ और ईमानदारी से कर रहा हैं या नहीं ? अगर हम ऐसा नहीं करते तो लोगो ने हम पर जो जिम्मेदारी डाली हैं, विश्वास व्यक्त किया हैं और हमारे जिम्मे हरियाणा प्रान्त की सेवा करने का बोझ उठाना चाहते हैं, अगर हम उसे पुरी तरह से नहीं निभा सकेंगें। अगर हम यह बोझ उठाना चाहते हैं, अगर हम हरियाणा प्रान्त के अन्दर जमहुरियत की जड़े मजबूत करना चाहते हैं तोरूलिंग पार्टी की तरफ से भी और अपोजीशन पार्टी की तरफ से भी हमें यहां अच्छे से अच्छे रवायत कयाम करने होंगें। इस सिलसिले में मुझे आशा की एक छोटी सी किरण नजर आती हैं क्योंकि इस दफा बहुत इन्टैलीजैंन्ट और सुलझे हुए सियासतदान

हमारी विधान सभा के अन्दर आये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि हम सब वक्त की नजाकत का अहसास करते हुए अपनी–अपनी जिम्मेदारी को समझेंगें और हाउस को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश करेंगें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आखिर में एक बात और कहते हुए मैं अपना स्थान लूगां। वह यह हैं कि जहां तक एजुकेशन इन्स्टीच्यूशन का ताल्लूक हैं, आप भी जानते हैं और हमारे सब विधायक साथी भी जो यहां बैठे हैं, यह जानते हैं कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर अगर कोई बीमारी हैं तो वह जाति–पाति की बीमारी हैं। तरक्की के कामों में यह बीमारी हमेशा रोड़ा बनती रहती हैं। अगर हमनें तरक्की करनी हैं तो हमें इस भेदभाव को भी मिटाना होगा। हमें इससें ऊपर उठना पड़ेगा और हम उसी वक्त ऊपर उठ सकेंगें जबकि हमारे यहां जो प्राइवेट इन्स्टीच्यून्ज हैं, उन तमाम को नैशनलाईज कर दें। उन्हें सरकारी तौर पर अपनी तहवील में ले लें। जाति–पाति का जहर जहां से फैलता हैं और जहां पर यह बीमारी पलती हैं, अगर हम उसी जगह पर उसका इलाज वगैरा न करें और उसको चोटी पर जाने के बाद दवाई छिड़कें, तो वह बीमारी हमेशा के लिए नहीं जा सकती हैं। इसी कारण आपकी मार्फत मैं हाउस ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इन बातों के साथ–साथ, मित्तल साहब ने जो प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभावक पर पेश किया हैं, उसकी पुरजोर ताईद करता हूं। जय हिन्द।

Deputy Speaker: Motion moved:

That the address be presented to the Governor in the follwong terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 4th April, 1972".

I have received notice of an amendmeat from Shri Kanwal Nain Gulati, M.L.A. This amendment, as also any others to be received hereafter, will be deemed to have been read and moved. The Members may, however, take part in the discussion.

1.Shir K.N. Gulati:-

That in the motion, the following be added at teh end, namely:-

"But regret that no mention has been made:-

1) That there will be one tax out of Property tax and house tax:

2) That there wil be nmo professional tax;

3) That there will be now excise duty instad of Sales tax:

4) That the recommendations of Employees-wage-Board will be implemented:

5) That Haryana Government emplouyees will get and Government teachers will sweve in their home places:

6) That Haryana Governmet employees and Governmet teachers will seve in their home places:

7) That fair compenstaion will be paid for land aquired with no profit;

8) That Sherab Bandi will be ordered:

9) That Government will slove the major two problems of water and sanitation fo Faridabad block:

10) That worst position of B.K. Hospital adn E.S.I. Hospital of Faridabad will be changed into good postion;

11) That free education and free treatment iwill be provided upto Rs.500/ P.M.income;

12) Reg. Labour colony in Galf club place at Faridabad.

चौधरी रिजक राम(राई): डिप्टी स्पीकर साहिबा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव श्री मित्तल साहब ने प्रस्तुत किया हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरियाणा के विकास के बारे में बहुत चर्चा की गई हैं। सड़को के बारे में, बिजली के बारें में और इंडस्ट्रियल तथा दूसरी जो प्रगति हुई हैं, उनके बारे में इसमें

खास तौर से चर्चा की गयी हैं। चुनाव के बारें में भी उन्होंनें फरमाया हैं कि हरियाणा में चुनाव बड़े शान्ति पूर्ण ढंग से हुए हैं।

जहां तक विकास का और चुनाव का सम्बन्ध हैं, बेशकरूलिंग पार्टी बहुमत में आयी हैं, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इनकी जो विकास योजनांए हैं, उन पर इन्हें ज्यादा गौरव करने की गुजांईश नहीं हैं। आप देखिये, मेरे ख्याल में इस चुनाव में हरियाणा ही एक ऐसा प्रान्त हैं जहां पर कैबिनेट के पांच वजीर चुनाव हारे यानि पराजित हुए हैं। सारे देश के किसी भी दूसरे प्रान्त में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। वजीर भी वह हारे हैं जो रोड्ज के महकमे के इन्चार्ज थे, जो डिवैल्पमैंट (विकास) के महकमें के इन्चार्ज थे, और जो प्लानिग और फाईनास के महकमे के इन्चार्ज थे। उनके हल्के के लोगोनही ही उन्हें रिजैक्ट कर दिया कि जो उनका काम हैं और जो सरकार की नीति हैं वह उन्हें पसन्द नहीं हैं।

चौधरी रिजक रामः मैं उस वक्त मिनिस्टर नही था।

चौधरी रिजक रामः पर हारे तो थे !

चौधरी रिजक रामः आप कल तो पैदा हुए हैं, क्या हुआ अगर जल्दी तरक्की कर गये ? थोड़ी देर मेरी बातें सुन लो। कोई ऐसी–वैसी बात नहीं हैं। तो पांच वजीर हारे हैं। पांचो के बारे में मैंने सच्ची बात की तो उसमें श्री भजन लाल को थोड़ी तकलीफ हुई।

चौधरी भजन लालः मैंने सच्ची बात कही हैं।

चौधरी रिजक रामः चार के बारे में मैं कहता हूं पांचवे के बारे में शायद इनका हाथ हो।

चौधरी भजन लालः हमारा तो किसी के हराने में हाथ नहीं हैं।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कह रहा था कि जितने वजीर इस हरियाणा में हारे हैं उतने वजीर हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हारे। जिस विकास की यह लोग इतनी डींग मारते हैं, जिन विकास योजनाओं की, जिस प्रगति की यह इतनी चर्चा करते हैं और गर्वनर महोदय ने भी जिसकी चर्चा की हैं उसको जनता ने स्वीकृत नहीं किया। इस चीज का और इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता हैं कि पांच वजीर यहां पर हारे हैं और वे वजीर चुने गए हैं उनके बारे में भी मैं अर्ज करता हूं। मित्तल साहब ने मुख्य मंत्री के हल्के के बारे में चर्चा की। मैं व्यक्तिगतरूप में किसी हल्के की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देखिए ऐजुकेशन के बारे में बड़ी चर्चा हुई मैं एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बताऊं कि जितनी राय ऐजुकेशन मिनिस्टर ने लीं उनसे दुगनी राय विरोधी उम्मीदवारों ने ली। इसका मतलब यह हैं कि लोगों ने उनके प्रति भी अविश्वास प्रकट किया हैं। इसी तरह से इरीगेशन वजीर के हल्के को आप ले लीजिए विरोधी उम्मीदवारों ने उनसे दुगनी से भी

ज्यादा राय हासिल की। यह किस बात की डींग मारते हैं। अगर आप ईमानदारी से देंखें तो हरियाणा की जनता ने साफ बतला दिया की आपकी नीतियां उचित नहीं हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूंकि आज भी इस चुनाव के बाद हरियाणा की सरकार को सोचना चाहिए कि जब विकास के इतने काम किए है, प्रान्त में इतनी तरक्की हुई तो फिर क्या त्रुटि हैं कि हरियाणा ही एक ऐसा सूबा हैं कि विरोधी दल के उम्मीदवार और प्रान्तों के मुकाबले ज्यादा आए हैं। इनको इसकी खोज करनी चाहिए, आत्म निरीक्षण करना चाहिएं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर हम कोई सुझाव दें तो शायद यह नहीं मानेगें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं गवर्नर साहब ने एक बात की अपने ऐड्रैस में बडी़ प्रसंशा की हैं और कहा हैं कि चुनाव पीसफुल हुए। उन्होंनें यह नहीं कहा कि फेयर हुए हैं। लेकिन यह बात नही बताते कि उनके हल्के में कितनी राय राजस्थान की बनवाई, कितने ट्रक के ट्रक भरकर आए। मैं क्या बताऊं हिसार जिले की बात कह रहां हूं। एक हल्के के एक गांव के एक घर के लोगों ने 192 वोट डालीं और वह राय सारी की सारी मर्दों की हैं, कोई जनानी राय नहीं हैं। मुझे पता नहीं हैं कि औरतों के बगैर यह पैदा कैसे हुए ?(व्यवधान) भजन लाल को ज्यादा पता हैं क्योकि उनके हल्के में...

चौधरी भजन लाल: ऐसा कहना गलत हैं कि उनकी राय बनी थी।

चौधरी रिजक रामः जहां ऐसी बातें हुई हैं वहां मैं एक बात अफसरान के बारें में भी कहना चाहता हूं। पब्लि के ऊपर इनके जरिए बड़ी धींगमुश्ती हुई हैं, दबाव डाले गए हैं, बहुत दख्लअन्दाजी की गई हैं, बहुत कुछ हुआ हैं और यह सब कुछ ऊपर के इशारे पर हुआ हैं। बहुत से ऐसी भी अफसर थे जो निष्पक्ष रहें, गैरजानिबदार थें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि जो जानिबदार रहे उनके लिए नाजायज तौर पर तरक्की के साधन बनाए गए और जो वेचारे गैरजानिबदार रहे वे मुश्किलात में रहें। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूगां। एक बात इस चुनाव के सिलसिले में और कहना चाहता हूं कि यह चुनाव कितने फेयर हो सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मेरी एक बात से ही अन्दाज लगा सकती हैं कि तीन तारीख को सैशन शुरू हुआ और आठ तारीख को राज्य सभा के मैंम्बरों का चुनाव हो रहा हैं। परसों तीन तारीख थी, क्या आप कह सकती हैं कि राज्य सभा के जो चुनाव हैं वह फेयरवेली होंगी। इनकी एक ही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मैंम्बरों पर डालें 1 लाख, डेढ़ लाखरूपये का प्रलोभन दिया जाएगा, क्या उनकी राय तोड़ने के लिए सरकारी अफसरान जैसे डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कप्तान द्वारा दबाव नहीं डाला जाएगा। इन वजीरों से यह उम्मीद कर सकते हैं: यह वजीर हों ओर फिर हरियाणा में इलैक्शन फेयर हो जाएं। डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कप्तान के द्वारा दबाव डाला गया। एक एस0 डी0 ओ0 के बारे में कहा गया कि उसके यहां से पोजीशन का कंडीडेट जीत कर आ गया। उनको तोड़ने की तरह–तरह की

कोशिशें की जा रही हैं, तरह–तरह के प्रलोभन दिये जा रहे हैं। कहीं पर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने का वायदा, कहीं कुछ और वायदा । एक मिनिस्टर का घर तो मैंम्बरों के समलिंग का अड्डा बना हुआ हैं। मैंम्बरों को किडनैप करके ले जाया जाता हैं, रात भर उसको रखते हैं, तरह–तरह के दबाव डालते हैं, जब इस प्रकार की हालत हो, शराब की छूंट हो, रिश्वत बांटी जाती हो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसी बातों को सुनकर कैसे कहा जाता सकता हैं कि इंलैक्शन फेयर हुए हैं। इन हालात में हरियाणा में डैमोक्रेसी कैसे चल सकती हैं। क्या–क्या बातें हुई मैं उनकी चर्चा न करते हुए इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तकरूलिंग पार्टी हैं, बेशक इनका सदन में बहुमत हैं लेकिन आज अपनी इस जीत पर गर्व नहीं कर सकती। जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया, सरमाएदारों की मदद से, अफसरों के द्वारा नजायज दबाव डालकर मत हासिल किए गए, उस पर यह गर्व नहीं कर सकते। जिस तरह हरियाणा को जनता ने इनके प्रोग्राम को ठुकराया हैं इस पर ये गर्व नहीं कर सकते। गर्व तो विरोधी दल के लोगों को होना चाहिए कि इस तरह की नाजायज बातों के होते हूए भी हरियाणा ही एक ऐसा सूबा हैं जहां पर सब से ज्यादा तादाद में अपोजीशन कामयाब होका आई हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहब मैं अपने भाषण में बिजली तथा सड़को के विकास का जिक्र किया। यह बताया गया कि इतने थोड़े से अर्से मे सारे हरियाणा में बिजली पहुंच गई।

यह भी कहा गया कि अगले साल 26 जनवरी तक हर गांव को सड़क दें देगें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको बहुत तजुर्बा हैं यह जो सड़क और बिजली को प्रोग्राम हैं इसमे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लोगों को 26 जनवरी तक सड़क मिल जाएगी, बड़ी अच्छी बात हैं। लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। बिजली भी पहुची हैं यह भी अच्छी बात हैं। लेकिन जहां तक प्रोग्राम का सवाल हैं जिस ढंग से बिजली का फैलाव किया, जिस ढंग से सड़को का काम किया, हरियाणा में इस प्रकार के कैश प्रोग्राम की क्या जरूरत थी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक केश प्रोग्राम का ताल्लुक हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता हैं। जहां तक बिजली फैलाव का ताल्लुक हैं इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के अरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा गवर्नर को मेमोरेंडम दिए गए हैं कि इसमें करोंड़ोरूपये बिजली बोर्ड के अफसरों ने और जिसमें मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, खाए हैं। पता नहीं इस बारें में इन्क्वायरी हो या न हो। लेकिन एक बात हैं जहां तक कैश प्रोग्राम का ताल्लुक हैं आप भी इस बात को मानेगी कि केश प्रोग्राम सेरूल्ज की वायोलेशन करेके एस्टीमेट तैयार होते हैं। खुद इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने यह बात मानी हैं कि हम बहुत जल्दी में काम कर रहे थे इसी लियें किसी मशीनरी को खरीदने में, किसी चीज को खरीदने में, हमने बाकायदा एस्टीमेट तैयार नहीं करवाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, चैक बुकें अफसरों को दे दी गई है और कहा गया हैं कि जैसें भी हो जाकर सामान खरीद लाओ। यह सब कुछ उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया।

जहां पर ऐसेरूल्ज की बेकायदगी हो तो आप ही बताइयें कि वहां ईमानदारी कैसे रह सकती हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को माना हैं कि जो बिजली का फैलाव का काम हुआ हैं, उसमें इन्क्वायरी होनी चाहियें और आज इसकी विजिलैंस डिपार्टमैंट के जरिये तहकीकात भी हो रही हैं। इसी लिये आयोग की मांग की गई हैं क्योंकि जांच आयोग के जरिये ही लोगों को अपनी शिकायतो सुनाने का मौका मिल सकेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक सड़को का सम्बन्ध हैं, इस बारे में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मंन्त्री महोदय बैठे हैं, शायद उनके नोटिस में हो। गुडगांव में इंजीनियरिंग सैक्शनल आफिसर्ज, हरियाणा की एक कांफ्रेंस हुई और उस कांफ्रेंस में उन्होंनें रेजोल्यूशन पास किया कि सड़कों पर जो काम चालू हैं वह बन्द कर दिया जाए। इनेक पी0 डब्ल्यू0 डी0 बी0 एण्ड0 आर0 के0 एस0 ओ0 खुद इस रैजोल्यूशन को पास करते हैं उन्होंनें खुद हरियाणा सरकार से इस बात का अनुरोध किया कि सड़कों पर जो काम चालू हैं वह उस वक्त तक बन्द किया जाए जब तक कि सब–स्टैंडर्ड मैंटिरियल, जो सड़को पर लगाया गया हैं, के बारें में यह न देखा जाए कि इसका जिम्मेदार कौन हैं, इनके कैश प्रोग्राम का बहाना बनाकर कि जिन अफसरों ने, आदमियों ने यह काम किया हैं, उनके अपने ही अफसर हैं, वहीं रैजोल्यूशन पास करते हैं कि जो सब–स्टैंडर्ड मैटिरियल सप्लाई किया गया हैं,

उसको बन्द किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कोई भी सड़के कैश प्रोग्राम के जरिये नहीं बन रही हैं। एक तरफ मिट्टी डाली हैं, मिट्टी दबी नहीं दूसरा काम शुरू कर दिया और ऊपर से बरमात आ गई, आधे से ज्यादा सड़क टूट जाती हैं, इसका कारण यह हैं कि मिट्टी की कोई पड़ताल नहीं होती, रोड़ी की कोई पड़ताल नही, ईटों की कोई पड़ताल नहीं। इस तरीके से हरियाणा की गरीब जनता कारूपया बरबाद किया जा रहा हैं, जिसकी तरफ हरियाणा को ध्यान देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके अलावा मैं एक और बात आप से अर्ज करना चाहूगां कि गर्वनर साहब ने जहां इनके कामों की प्रसंशा की हैं, उसका कोई जिक्र नही किया गया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी सरकारी बैन्चिज से बोलते हुए मेरे एक साथी ने बतलाया कि जब हरियाणा बना उसमें कोई साधन नहीं थें, न पानी का साधन था और न दूसरे साधन थे और आज जो कुछ हरियाणा में हुआ हैं, वह बहुत सन्तोषजनक हैं। सड़को के बारें में, बिजली के बारें में, सरकार ने सड़को की बात कहीं कि 26 जनवरी,1973 तक हम हर गांव को सड़कों से मिला देंगें। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के अलावा इतने प्रान्त इस देश में हैं क्या कोई प्रान्त हरियाणा से ज्यादा समृद्धिशाली हैं। ये कैश प्रोग्राम सड़के बनाने का जिसका ये जिकर कर रहे हैं, इसको सब कामों की बैलैंस्ड डिंवैल्पमैंट करते हुए कैसे पूरा करेंगें। जो दूसरी स्टेट्स हैं, जो

अभी तक कैश प्रोग्राम नहीं कर सकीं क्या उनके पास इतने साधन नहीं थें, क्या उनकी ज्यादा मुश्किलात थी(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, हर गांव को सड़को से मिला दिया जाएगा, यह कैसे होगा ? क्या सरकार ने यह बात जांचने की कोशिश की। इस बारें मेरी राय हैं कि हमारी डिवैल्पमेंट योजनाएं तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि ये प्लेन के मुताबिक काम नहीं करेंगें और नही इनकी एकोनमी काबू में आ सकती हैं। स्पीकर साहिबा, अगर इन्होंनें प्लेन के मुताबिक काम नहीं करना हैं, अपनी मर्जी से काम करना हैं तो क्या जरूरत हैं प्लेंनिग की, क्या जरूरत हैं एनुअल प्लेन की क्या जरूरत हैं 5 साला की प्लेन की। आखिर प्लेन हरियाणा सरकार के जिम्मे, हरियाणा की जनता के जिम्मे, केन्द्र सरकार का 200 करोड़रूपया हैं। हर साल जितना केन्द्र सरकार से हम कर्जा लेते हैं, उससे ज्यादा हम ब्याज हम ब्याज केरूप में वापिस देते हैं। 19 करोड़रूपया वर्लड बैंक से हमने ले रखा हैं। ओवर ड्राफ्ट भी 28–30 करोड़ का हैं। आज हमारी हालात यह हैं। नान–प्लैंड एक्सपेन्डीचर कितना बढ़ गया हैं। आज यह सारा खर्च जो हो रहा हैं, आखिर में सरकार इस पर काबू नहीं पा सकेगी। इन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार अगर ओवर ड्राफ्ट को अगर बन्द कर देती हैं तो आज सरकार को इतनी मुश्किलात होगी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं हैं। अगर प्लेन को तोड़ा जाएगा। तो एकानोमी बहुत बिगड़ जायेगी। आप देखिये हरियाणा सन् 66 से पहले पंजाब का हिस्सा था। पंजाब प्रगतिशील प्रदेश था, समृद्धिशाली था और

हरियाणा उसका एक हिस्सा था। जब से यह प्रदेश अलग हुआ, सन् 69 में फिफ्थ कमिशन की रिपोर्ट आई। पांच रिपोर्टस देश के सामने हैं, हरियाणा की जनता के सामने हैं और सरकार के भी सामने हैं। पांच फाइनेंस कमीशनों ने कभी भी पंजाब को और पंजाब से **(4.00 P.M.)** अलग होने के बाद हरियाणा को कोई ग्रान्ट–इन–एड नहीं दी। क्यों नहीं दी ? क्योंकि पंजाब तो बहुत तरक्की पर था और हरियाणा को इसलिये नहीं दी कि फाइनेंस कमीशन ने यह इकरार किया था कि जोरूपया तकसीम होगा वह बैकवर्ड स्टेट्स के हिसाब से होगा। पांचवे फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा और गुजरात ये तीन चार ऐसी स्टेट्स हैं जिनको सैण्ट्रल गवर्नमैंट से ग्रान्ट–इन–एंड नहीं मिली हैं हालकिं कुछ राशि इसके लिये प्रोवाइड थी। बी0 एड0 पांडे कमेटी की रिपोर्ट हैं और वाचू कमेटी की रिपोर्ट हैं उनमें 3–4 क्राइटेरिया हैं। एक तो इलाके की जांच करने के लिए कि कौन सा इलाका बैकवर्ड हैं और कौन सा नहीं, कौन से इलाके में सड़के हैं, कौन से इलाके में रेलवेज हैं, कौन से इलाके में बिजली फैली हुई हैं, कौन सा इरीगेटिड हैं और कौन से इलाके की कितनी पर–कैपिटा इंकम हैं। 1960–61 में महाराष्ट्रकी पर–कैपिटा इंकम 409रूपये थी और पंजाब की 374रूपये थी। हरियाणा उस वक्त पंजाब का हिस्सा था लेकिन फिर भी हरियाणा की हालात खराब थी। हरियाणा को अलग बनाने की मांग भी इसलिये पैदा हुई कि हरियाणा नैगलैक्टिड था। स्पीकर साहब, आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं वह राजस्थान से लगता हैं। हिसार, महेन्द्रगढ़

और गुडगांव के जिले ज्यादातार डैजर्ट इलाके हैं। इन इलाकों में अगर तो बारिश हो जाती तब तो कुछ पैदावार हो जाती हैं वरना कुछ पैदा नहीं होता। हरियाणा एक ऐसा प्रान्त हैं जिसमें फलड्ज और कहत एक साथ पड़ते हैं। यह एक ऐसा सूबा हैं जिसमें कोई तरक्की नहीं हुई अफसोसनाक बात यह हैं कि जिस वक्त हरियाणा पंजाब का हिस्सा था तो उस वक्त सारी सत्ता पंजाब के लोगों के हाथ में ही थी, हरियाणा की कोई आवाज नहीं थी यह दिखाने के लिए हरियाणा तरक्की कर रहे हैं, यहां के जो फैक्टस और फिगर्ज थे। वह जानबूझकर कर गलत बनाये गये। यहां कि डिवैल्पमैंट के जो आकड़े थे वे गलत थे। आज भी हमें इस बात का अफसोस हैं कि सरकार ने उन आकड़ो को दूरस्त करने की कोशिश नहीं की। स्पीकर साहब, में आपकी जरिये यह कहना चाहता हूं कि ये आकड़े तो कभी ठीक हुआ ही नहीं करते। जब कोई वजीर या सरकारी अफसर किसी बात का जबाव ठीक से न दे पाये तो वह स्टैटिसटिक्स की आड़ लेता हैं कि उसमें ऐसा लिखा हुआ हैं। जहां तक हरियाणा की पर–कैपिटा इंकम और तरक्की के आकड़ो का सवाल हैं वें आकड़े गलत हैं। आप देखिऐ यहां पानी के साधन बहुत कम हैं, यहां कोई दरिया नही हैं। इस प्रान्त में कुछ पानी तो जामुना से आता हैं और कुछ भाखड़ा से आता हैं। जमुना का जो पानी हैं उसमें हरियाणा के लिये वाटर एलांउस 43 फीसदी हैं और पंजाब के लिये 2.4 था। हमारी अपर बारी दुआब में इनटैन्सिटी 43 फिसदी हैं और पंजाब की 83–84 फीसदी हैं और कैपेसिटी फैक्टर .38 बीघों को एक दफा भी पानी लग जाये

तो उस सारी जमीन की गिरदवारी हो जाती हैं। जब इसके बारे में पूछा जाता हैं तो वह कह देते हैं कि जितना पानी परमिसीबल था हमने दे दिया और कुछ नहीं कर सकतें। इन आंकड़ो के आधार पर आज हरियाणा सरकार ने यह लिखती हैं कि हरियाणा में इतना रकबाइरीगेटिड हैं। हमारे गोहाना के मंत्री बैंठे हैं, बाबू भजन लाल जी को तो शायद आब–पाशी का इतना तजरूबा न हो। आज हर एक आदमी जानता हैं कि हरियाणा में जितनी भी गिरदावरी होती हैं वह बोगस होती हैं और गरीब किसानों के ऊपर नाजायज बोझा डाला जाता हैं। स्पीकर साहिबा, इस हद तक ज्यादती होती हैं कि अगर कोई आदमी अपनी जमीन को ट्यूबवैल से पानी लागत है और उस पानी को नहर के खाल में से निकाल ले तो नहर वाले अपने पानी की गिरदावरी कर देते हैं। और अगर ड्रेन से निकालकर पानी दे लें तो भी आबियाना नहर का ही लेते हैं

सैण्ट्रल गवर्नमैंट ने इस प्रान्त की पर–कैपिटा इंकम के आकड़ो को देखकर प्रान्त को ग्रान्ट–इन–एड से वचिंत किया। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आंकड़े इरीग्रेशन से ताल्लुक रखने हो या इंडस्ट्रियल से इन सबकी पड़ताल होनी चाहिए और जो बे–इन्साफी हरियाणा से हुई हैं उसको दुरूस्त करें। मैं यह महसूस करता हूं कि प्रैक्टिल तौर पर देखा जाये तो इस सदन का हर मैंम्बर यही समझेगा कि जो आंकड़े इस वक्त हैं, वे गलत हैं और उनमें दुरस्ती होनी लाजमी हैं। स्पीकर साहब, आपको याद होगा

कि खुद स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक दफा बोलते हुए कहा था कि जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की कीताबें है, उनको समुद्र में फेंके दो ताकि ये वुजरा साहिब गलत आकड़ो के सहारे जनता को गुमराह न करे। मैं यह कहना चाहंता हू कि जो आपके आकड़े है उनमें बहुत गलतिंया हैं और उनको ठीक करने के लिये हमें कदम उठाने चाहिएं।

विकास मंत्री (श्री श्याम चन्द): कौन से आंकड़ गलत हैं ? (व्यधान)

चौधरी रिजक रामः दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जिसकी तरफ गवर्नर महोदय ने अपने एड्रैस में तवज्जो नहीं दिलाई। बिजली के बारे में बात की जाती हैं लेकिन में पूछना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी बिजली पैदा करती हैं और कितनी खप्त दिखाती हैं। अभी श्याम चन्द जी ने फरमाया कि आंकड़ो को आप कैसे गलत कहते हैं ? आप अगर पड़ताल करें कि कितनी बिजली हरियाणा को मिलती हैं और कितने यह बोर्ड वाले खप्त दिखाते हैं तो आपके सही चीज का पता लग जायेगा। जितनी बिजली हमें मिलती हैं उसमें से कुछ तो रास्ते में लीकेज हो जाती हैं और कुछ ट्रांसमीशन में खर्च हो जाती हैं। उसमें से कुछ तो रास्ते में लीकेज हो जाती उसके बाद जो बचती हैं उसका और जो कंजम्पशन दिखाई जाती हैं उसका अन्तर देख ले। आप नये मिनिस्टर बने हैं इसलिये इसकी पड़ताल करवा लें। You will have ample opportunity to find out. ये कहते हैं कि हरियाणा में

बिजली पैदा होती हैं । जितनी पैदा होती हैं उससे कई गुना ज्यादा कंजम्पशन के बिल हर महीने लोगों के मत्थे मारे जाते हैं और बिजली बोर्ड का यह सख्त हुक्त हैं कि कोई आदमी यह एतराज नहीं कर सकता कि यह गलत बिल हैं। जो गरीब आदमी झोपड़ी में बैंठा हुआ हैं उसे अगर सौरूपये का बिल आ जाए तो उस के पास कोई चारा नहीं होता, उसको देना पड़ेगा और अगर वह नहीं देगा तो उस का कनैक्शन कट जाएगा। ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जहां किसी की कन्जम्पशन हैं उनका पांच–पांच सौरूपये का बिल आता हैं।

श्री श्याम चन्दः चौधरी साहिब फ्री भी बहुत जलती हैं।

चौधरी रिजक रामः श्री श्याम चंद जी आप अभी नये मिनिस्टर बने हैं, आप इन बातों का पता कर लेना। आज हालत यह हैं कि इतनी धांधली चल रही हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। स्पीकर साहब, आज बिजली का फैलाव ठीक हैं बहुत हो गया हैं लेकिन बिजली की जितनी रिक्वायरमैंट हैं वह पूरी नहीं हो रही, आज एक लाख किलोवाट बिजली मध्यप्रदेश से उधार ले कर काम चलाया जा रहा हैं। मैं कहता हूं कि जो आप ने जो बिजली के फैलाव का काम किया हैं, वह अच्छा हैं, आपने देहातों में बिजली दी। लेकिन आप ने जब बिजली दी हैं तो आपको रैजिडैंश्यिल,कमर्शियल और टयूबवैलों के लिए जितनी बिजली लोगो को चाहिए थी उसका इन्तजाम करना चाहिए। आप ने तारें और खम्बे तो गाड़ दिए हैं और बिजली पूरी देने का कोई

इन्तजाम नहीं किया इससे तरक्की नहीं हो सकती। जहां–जहां पर तारें बिछाई गई हैं वहां पर क्या बिजली दी जा रही हैं, यह आप बताएं, उतनी बिजली देने का इन्तजाम आप कर रहें हैं। आज इत्तिफाक की बात हैं कि हमारे प्रान्त में न तो कोई पहाड़ हैं और न ही कोई ऐसा दरिया हैं जिस में कि बिजली पैदा की जा सकें, मगर हिमाचल प्रदेश में बहुत से दरिया हैं और उनका यह फैसला हैं कि सारी बिजली जो हमारी भूमि में से निकलती हैं, जो दरिया उनकी स्टेट में से निकलती हैं उससे वह सारी बिजली खुदा पैदा करेंगें और या अगर कोई दूसरी स्टेट जैनरेट करेगी तो उस से पूरी कीमत वसूल करेंगें, हालकि स्पीकर साहिब सैंट्रल गवर्नमैंट का यह फैसला था कि जो भी बिजली का प्रोजैक्ट चालू हो वह वह इस ख्याल से बनाया जाए कि उस में रिजनल ग्रिड को हिस्सा मिल सकें। जैसें यू0 पी0, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर वगैरा जो भी स्टेट बिजली इन्वैस्टीगेट करे वह सारे रीजन के लिए होगी। लेकिन अगर इस स्थिति की कोई स्टेट नही मानती तो हरियाणा किसी तरह बिजली पैदा ही नहीं कर सकता, थर्मल पलांट बेशक लगा ले लेकिन बहुत महंगी पड़ती हैं। जमुना दरिया एक ऐसा हैं जो हरियाणा से गुजरता हैं, इस में हमारा हिस्सा हैं लेकिन वह सारा पलेन हैं। यह यू0 पी0 टैरटरी में से भी गुजरता हैं, यू0 पी0 वालों ने वहां पर पावर हाउस लगा दिए लेकिन हिमाचल गवर्नमैंट ने बड़ी आपत्ति उठाई हैं और इन्होंनें कहा कि हमारी टैरटरी से दरिया आता हैं इसलिए हमें बिजली का हिस्सा दो बनी हम गुजरने नहीं देंगें। उस झगड़े का अभी फैसला

हुआ हैं और यू0 पी0 की सरकार हम बिजली का 25 फीसदी हिस्सा उनको देगी हालकिं हिमाचल को बिजली की जरूरत भी नहीं हैं, और वह उस बिजली को बेच कर बीस लाखरूपया मुनाफा कमाते हैं। मगर इधर हालत यह हैं कि हमारे हरियाणा को अपनी जरूरत के लिए भी बिजली नहीं मिलती। मैं अपनी सरकार को यह सुझाव देता हूं कि यू0 पी0 सरकार ने जो दो पावर हाउस बनाए हैं उस मे से हमारी सरकार हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार सोई पड़ी हैं। आज हरियाणा की सरकार हमें यह बताए कि उन्होंनें यू0 पी0 गवर्नमैंट से इस बारे में कोई एतराज किया हैं कि जमुना पर दो पावर हाउस जो यू0 पी0 सरकार बनाने लग रही हैं उन में से हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें हमारा हिस्सा बनता हैं लेकिन उस के बारें में एक लफज भी नहीं कहा गया। जितनी भी जमाना की बिजली हैं वह यू0 पी0 वाले एक्सपलायट कर लेंगें। इसी तरह नंगल डैम के पास पंजाब सरकार दो पावर हाउस 55 मैगावाट के बना रही हैं, हिमाचल सरकार बाकी दरियाओं से बिजली पैदा करने जा रही हैं लेकिन हमारी हरियाणा की सरकार बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहीं। मैं कहता हूं कि हरियाणा के लोगों के क्लेम की रक्षा करने के लिए उनका सैंट्रल गवर्नमैंट के फैसले के मुताबिक जो बिजली में हमारी स्टेट का हक बनता हैं उस की मांग करनी चाहिए ताकि हमारे सूबे में जहां बिजली के फैलावे का काम हुआ हैं लोगों को जरूरत के मुताबिक बिजली दी जा सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेगें तो सूबे में मौजूदा बिजली से काम

चलना मुश्किल हो जायेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे गवर्नर साहिब ने अपने भाषण मे जिक्र किया की हरियाणा सरकार जुई, लोहारू और सिवानी कैनाल्ज निकाल रही हैं और उन के लिए इतने करोड़रूपया खर्च कर रही हैं। स्पीकर साहिब, यह अब नहरें उस इलाके में हैं जो सारा बारानी हैं, जिस में आए साल कहत पड़ते हैं। मुझे उस इलाके में बहुत ज्यादा जाने का इत्तिफाक हुआ। वह इलाका ऐसा हैं जिसमें बहुत से गांव में पीने का पानी नहीं हैं। वहां पर अगर पीने का पानी दिया जाए तो वह पुन्य का काम हैं और इस संबध में जो कुछ आप ने किया वह अच्छा हैं उसके के लिए कोई एतराज नहीं कर सकता लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह जो नहरें हैं वह कोई नई स्कीम नही हैं नाम बेशक नया रखा दिया हैं वह और बात हैं लेकिन वह पहले से स्कीम थी। लोहारू कैनाल का जहां तक ताल्लुक हैं, हम ने डाईवर्शन ड्रेन नम्बर आठ के इलावा भी सरवे करवाया था दोहान नदी का भी उसमें पानी जा सकता है। जो नाई नाला वगैरा से रोहतक के आस–पास के इलाके बरबाद होते हैं उनका पानी भी अगर बुटाना ब्राचं के जरिए उस में ले जाया जाए तो काफी लोगों को पानी मिल सकता हैं और दूसरे जो नुक्सान होते हैं उसे भी उस में भी बचाया जा सकता हैं। जितनी सरकार ने इस काम के लिए तवज्जो दी हैं उस के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि नहरे तो आप बनाने लग रहे हैं लेकिन उन में पानी कहां से आएगा, पानी तो हरियाणा में हैं ही नहीं। आप को स्पीकर साहब अच्छी तरह से

ज्ञान हैं कि हमारे प्रान्त में पानी के दो सिस्टम हैं, एक जमाना कैनाल सिस्टम हैं और दूसरा भाखड़ा कैनाल सिस्टम हैं। भाखड़ा कैनाल सिस्टम का आप को तजूरबा हैं कि वह नहरें रेतीले इलाके से निकलती हैं और उन में जो पानी निकलता हैं वह बहुत कम हैं। जहां तक जमना कैनाल सिस्टम का ताल्लुक हैं , उसके इलाके में जितने रजवाहे और नहरें हैं वहां 42/45 दिन के बाद टर्न आती हैं, पानी बहुत ही कम मिलता हैं। और जब से यह सरकार बनी हैं मालूम नहीं क्या कारण हैं उन्होनें पानी चलाने का नया ढंग अख्तयार कर लिया हैं, जितनी भी मोरियां हैं मूनक से देहली तक यह सब रीमौडल कर दी हैं, ईटें लगा दी हैं, किसी में सीमैंट लगा दिया हैं और अब तो लोहे के छल्ले लगा दिए हैं जिन में से पानी बहुत ही कम चलता हैं। इस साल रोहतक में पानी की कमी की वजह से गन्ने की फसल जितनी कमजोंर हुई हैं उतनी कमजोर कभी पहले नहीं हुई। यू0 बी0 डी0 सी0 वाटर अलाउंस 3.5 परसैंट हैं लेकिन हमारे यहां 1.5 परसैंट है या शायद अब 2.4 परसैंट किया गया हैं। यह हालत हैं कि पानी हैं ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जब जमना ट्रैक्ट में पहले ही पानी कम हो तो दूसरी नहरें बनाने में कोई फायदा नहीं पहुंच सकता जब तक कि सरकार पानी को न बढ़ाये स्पीकर साहब, आपको मालूम होगा कि जो पानी इन्डस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को देते थे वह 31 मार्च, 1970 को ट्रीटी खत्म हो जाने के बाद बंद हो जाता था और उसमें से हमें पानी मिलना था लेकिन वह पानी हम नहीं ले सकें और कितना ही पानी कोई 14 मिलीयन एकड़ फीट पानी

आज भी पाकिस्तान को जाता हैं। इससें ज्यादा और क्या अफसोस हो सकता हैं कि हम अपना हिस्सा नहीं लें सकें। इसमें अकेले हरियाणा सरकार का मैं मानता हूं दोष नहीं हैं और यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि केन्द्रीय सरकार का भी दोष हैं और ऐसा करके उन्होंनें हरियाणा, पंजाब और देश के साथ अच्छा सलूक नहीं किया हैं। अगर वह उस पानी को हासिल कर लेते हैं और वह पानी हम ले पाते तो और पानी हमारा बढ़ सकता था। गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रैस में सतलुज व्यास लिंक का जिकर किया हैं मैं भी इसके बारें मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं । जहां तक रावी का पानी हैं वह तो हम ले नहीं सकते और यह सरकार कोई जवाब नहीं सकती। व्यास सतलुज लिंक 1972 में तैयार होना था, अब 1973 में तैयार होना हैं और शायद 1974 तक चला जाये। इस पर हरियाणा को पानी मिलना हैं लेकिन मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास कोई साधन हैं उस पानी को हरियाणा में लाने का ? स्पीकर साहब, हरियाणा में वह पानी पहुंच नहीं सकता जब तक रोपड़ से करनाल तक एक कैरियर कैनाल न बनाई जाये। रोपड़ से करनाल तक यह कैनाल कभी मन्जूर थी और बनाई जानी चाहिये थी जिस में यह व्यास सतलुज लिंक का पानी जो हमें मिलना हैं हरियाणा ले लाया लाया जाना हैं लेकिन अफसोस हैं कि आज तक उसके लिये यह जमीन नहीं लें सकें।1973 में यह व्यास सतलुज लिंक तैयार हो जायेगा, इस पर अरबोंरूपया खर्च हो रहा हैं और गवर्नर साहब ने हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाया हैं कि वगैर उस नहर को बनाये आप

कैंसे वह पानी हरियाणा में दें देगें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बगैर उस नहर को बनाये आप कैसे वह पानी हरियाणा में दे सकेगें (विघ्न) स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि आज से दो साल पहले हमारे इन्जिनियर्ज रोपड़ गये थें लेकिन पंजाब की पुलिस और डी0 सी0 ने उनको धक्के मार कर निकाल दिया था। आज तक एक लफ्ज भी इनकी जवान से नहीं निकल सका कि पंजाब सरकार को क्या हक हैं कि वह ऐसा करें अपने हिस्से का पानी हरियाणा में लाने के लिये जो नहर हरियाणा बनाना चाहती हैं उसे पंजाब सरकार बनने न दे और उसका सरवे न करने दे। आप कैसें कहते हैं कि आप पानी नहीं देगें ? आपके किसी अफसर की और वजीर की हिम्मत नहीं हुई हैं कि वहां सरवे करा सकें। आप तो खुशामदें करने का काम कर सकते हैं। पंजाब सरकार के बादल साहब चीफ मिनिस्टर थे और वासी साहब वजीर आवपाशी थे। उन्होंनें बार–बार एलान किया कि रावी–व्यास के पानी में से हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देगें और यह नहर बनने नहीं देगें। मैं पूछता हूं कि क्या एक्शन लिया आपने ? आप बतायें कहीं अगर सरवे हुआ हो और सैंट्रेल गवर्नमैंट पर दवाब डाल कर पंजाब से इस काम के लिये जमीन हासिल की हो।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल): वह चले गये अब सब कुछ होगा।

गृह मंत्री(श्री के0 एल0 पोसवाल): चीफ इन्जिनीयर के दफतर में जाकर सरवे के सारे नक्शे देख लो।

चौधरी रिजक रामः यह नक्शे आप ही बता देना कौन से हैं।

चौधरी भजन लालः सब कुछ हो गया पता नहीं कहां रहते हैं।

चौधरी रिजक रामः यह नक्शों की बात करते हैं। वह तो जब प्राजैक्ट बना था उस वक्त नक्शे बना लिये थें और उस वक्त शायद यह तीसरी चौथी जमात में पढ़ते होगें। मैं कहना चाहता हूं कि यह निहायत गम्भीर मसला हैं। इसमें कोई मजाक की बात नहीं हैं जिसमें हमारी नुक्ताचीनी करने से ही मुराद हो। अगर आपने सब कुछ कर लिया हैं तो आप बधाई के पात्र हैं और अगर नहीं कर रखा हैं तो इसकी तरफ मैं सरकार की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि अगर यह कदम न उठाया गया तो हरियाणा को बहुत नुकसान होगा और हम पानी से महरूम रह जायेंगे। अगर हम नजर दौड़ा कर देंखें तो आप पायेगें कि केन्द्र सरकार की तरफ से हरियाणा को पूरा इन्साफ नहीं मिल पा रहा हैं। मैंन पहले आपको ग्रांटस इन एड के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब एक ओर बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में जो सैट्रल सरकार की पब्लिक अंडरटेकिग्ज हैं उन पर कोई 4500 करोड़रूपया लगा हुआ हैं और एक मध्यप्रदेश स्टेट में ही यह 700 करोंड़रूपये की अंडर टेकिंग्ज लगी हुई हैं। मैं आप से पूछता हूं कि आप बताये कि हरियाणा का इन में कितना हिस्सा हैं ? सिर्फ सात करोड़रूपये की लागत की पिजौंर

में मशीन टूल्ज की फैक्टरी लगी हैं बाकी मामला साफ हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट की पब्लिक एन्ट्रप्राईजिज की जेा एलोकेशन कमेटी हैं उस ने 1970 में सिफारिश की थी हरियाणा में पैट्रोलियम रिफाइनरी और स्कूटर फैक्टरीज लगाई जायें लेकिन वह भी नहीं लगवा पाये हैं। अब वह शायद हरियाणा में न लगकर गाजियाबाद में लगने जा रहे हैं। इन अंडर–टेकिगंज से जहां जिस स्टेट में लगती हैं लोगों को रोजगार मिलता हैं लेकिन इस मामले में हरियाणा के साथ बेइन्साफी हुई हैं और हो रही हैं। फिर आप देखें हरियाणा में कितने भारी फल्ड आये और फेमिन आये हैं। 1968 में यह सरकार पावर में आई हैं । उस वक्त से आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें फेमिन और फल्डज के लिये ग्रांटस नहीं हासिल कर सके हैं। स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि तमिल नाडु में एक जिला में कहत पड़ा था तो उस एक जिला के लिये सैंट्रल गवर्नमैंट ने 16 करोड़रूपया दिया था लेकिन हरियाणा में उससे भी बड़े–बड़े फल्ड आये कहत पाड़े मगर एक पैसा नहीं दिया।

एक आवाजः आप भी तो वहां राज्य सभा के मैंबर थे आपको दिलाना चाहिये था।

चौधरी रिजक रामः तामिल नाडु सरकार तो आखें दिखा कर पैसा ले सकती हैं लेकिन यहां की सरकार की मैं क्या बात कहूं अगर कोई नाराज हो जाये तो इसको कुरसी का खतरा हो जाता हैं (विघ्न) अभी कह रहे थे कि मैं राज्य सभा का

मैंबर था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं बतौर राज्य सभा के मैंबर के एग्रीकल्चर मिनिस्टरी में गया था और उनसे कहा कि आप सब को पैसा दे रहे हैं हरियाणा को क्यों नहीं दे रहे हैं। कितने अफसोस की बात हैं कि उनके बार–बार लिखने पर भी हरियाणा की सरकार ने कोई रिप्रेजैशन नहीं भेजी मैंमोरैंडम नहीं भेजा कि उनकोरूपया चाहिये। दूसरे लोगों ने भेजे और उनको पैसे मिल गये और उन्होंनें ले लिये। फिर भी आप कहते हैं कि मैं मैंबर था वहां और हमारे फर्ज की बात करते हैं लेकिन अपने फरायज को भी तो देखो। फिर आप देखें कि डैम रावी पर बन रहा हैं जिसमें जायंट पंजाब में हरियाणा, तो पंजाब अकेलाा उसे बनता हैं। हरियाणा की सरकार फैसला नहीं करा सकी कि उसमें हरियाणा का भी हिस्सा हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बगैर पानी के इस तरह नहरें बनाने के कोई फायदा नहीं होगा। एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में डाले देने से और इस तरह गरीबी बांटने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्डस वाटर ट्रीटी का पानी हासिल करने के लिए और रावी व्यास का पानी हासिल करने के लिये सरकार को पूरी ताकत से काम करना चाहिए।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नर साहब ने अपने एड्रैस में लैंड रिफार्मज का जिकर किया हैं और फरमाया हैं कि हरियाणा सरकार जल्दी ही लैंड रिफामर्ज लायेगी। वैसे तो इस सरकार का इलैक्शन के दौरान भी और बाद भी गरीबी हटाओ का नारा था और हरिजनों के बारे में काफी आसू

बहाये जा रहे थे लेकिन इस एड्रैस को पढ़कर आप देख लें इस में कहीं भी गरीबी हटाओ को कोई जिकर नहीं हैं। सारे ऐड्रैस में गरीबी हटाओ नाम को कोई शब्द नहीं हैं क्योकि इलैक्शन जीत लिया हैं। इलैक्शन हौने के बाद ये लोग समझते हैं कि हरिजनो की गरीबी अपने आप ठीक हो गई। मैं लैंड रिफार्म के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूं । ज? जहां तक हरियाणा में लैंड रिफार्म करने का ताल्लुक हैं, यह होना चाहिए । मैं मानता हू ंकि यह मामला बहुत पेचीदा हैं। लैंड रिफार्म करने में बड़ीरूकावटे हैं। हरियाणा में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें बरसात के दिनों में दो साल के बाद बारिश हो जाए तो पैदावार हो जाती हैं, लेकिन जहां बारिश नहीं वहां कुछ नहीं होता। लैंड रिफार्म का मसला सन!1974 से चला आ रहा हैं लेकिन अभी तक इस इस अमल नहीं हआ। इसकी लम्बा करने से आपस में तनाव फैलता रहता हैं, यह मसला फौरन हल होना चाहिए। लोगों के सिर पर रोज फिक्र सवार रहता हैं कि जमीन के सम्बन्ध में कानून तब्दील होना हैं, कल तब्दील होना हैं, इस चिन्ता से खेती प्रोडक्शन में बाधा पड़ती हैं। अगर सरकार ने कोई कानून बनाना हैं, जिस तरह से भी बनाना हैं, बनांए। किस से जमीन लेनी हैं किसको जमीन देनी हैं, यह आपका अपना प्रोग्राम हैं। आप फौरन प्रोग्राम बनांए और जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करें। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लोक सभा चुनाव के एक हफ्ते बाद यह बयान दिया था कि तीन महीने के अन्दर–अन्दर हरिजनों की जमीन बाटं देंगें, भूमिहीनों को जमीन बांट देंगें। यह मार्च 18, 1971 की बात हैं

जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एलान किया था। एक साल से ज्यादा अर्सा हो गया और कल बयान देते हैं कि छः महीने के अन्दर–अन्दर बांट देंगें। जब तीन महीने एक साल के बराबर लम्बे हैं तो छः महीने न जाने कितने सालों के बराबर होगें। मैं समझता हूं इस मामले को ज्यादा देर तक लटकाना स्टेट के फायदे में नहीं हैं। लम्बा लटकाने से एक तरफ किसानों के दिल में दहशत फैलती हैं कि हमारी जमीन छीनी जा रही हैं और दूसरी तरफ भूमिहीनों लोगो के दिलों में झूठी आशा बंधती हैं क्योंकि गरीब आदमिंयो को आशा दिलाते हैं कि तुमको जमीन दी जाएगी। इस तरह दोनों तबकों में खाहमाखाह तनाव पैदा हो रहा हैं। जिसमें जमीन लेनी हैं ले, देनी हैं दें। जिस वक्त हाउस में बिल आएगां उस वक्त हम सरकार को सुझाव देने की कोशिश करेंगें, कंस्ट्रक्वि सुझाव देंगें इतनी अर्ज जरूर करना चाहता हूं कि इस मामले को लम्बा न लटकाएं, यही हमारी आप से प्रार्थना हैं।

स्पीकर साहब, दूसरी तरफ से बोलते हुए हमारे एक साथी ने अन–इम्पलायमैंट का जिक्र किया। मुझे ताज्जुब हुआ जब उन्होंनें यह कहा कि जिस प्रकार से विकास के प्रोग्राम लाये गये हैं उन से हरियाणा में बेकारी खत्म हो गई हैं। उन्होंनें यह तक कहा कि इस स्टेट में कोई आदमी बेकार नहीं हैं बल्कि दूसरे सूबों से ला–ला कर लोंगों से काम करवाया जा रहा हैं। मुझे खुशी हैं कि काई बेरोजगारी आदमी नहीं हैं लेकिन इसके साथ–साथ थोड़ा बहुत अफसोस भी हैं कि मेरे काबिल दोस्त को

कहां से यह गलत इत्तालाह मिली की हरियाणा में बेरोजगारी नहीं रहीं। चाहे शिक्षित युवक हो या अशिक्षित, हरियाणा में बेरोजगारी का मसला बड़ा अहम हैं। इतनी बेरोजगारी हैं कि पढ़े–लिखे लड़के हजारों तादाद में बेकार फिरते हैं । इनमें बी0 ए0 हैं, एम0 ए0 हैं, दसवीं पास का तो ठिकाना ही नहीं। आज पढ़े–लिखें लड़कों की गिनती बढ़ती जाती हैं। थोड़ा अर्सा हुआ, सरकारी तौर पर सर्वे हुआ था और मालूम हुआ था कि अकेले रोहतक जिले में ही 12 हजार ग्रेजुएट अन–इम्पलायड हैं जिन के पास काम करने का काई साधन नहीं हैं। आप चारों तरफ नजर दौड़ा लें हरियाणा में अन–इम्पलायड सबसे से ज्यादा हैं। पंजाब सरकार ने गवर्नमैंट सर्विस के लिए पंजाबी लागू कर दी हैं। तमिलनाडु में तमिल जानने वाले को यानी तामिलनाडु के निवासी को ही सर्विस देने का क्राइटीरिया बना दिया हैं। और दूसरी स्टेटों में भी इसी तरह से हो गया हैं। यहां तक कि दिल्ली सरकार ने यह क्राइटीरिया लगा दिया हैं कि किसी प्रदेश में स्थिति कारखानो में उस आदमी को नौकरी दी जाएगी जो उस प्रदेश का रहने वाला हो, लेकिन हरियाणा में ऐसी बात नहीं हैं। बंगाल में भी ऐसा ही कर दिया गया हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही हो गया जबकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और श्री सुखाडियां चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंनें लिखकर आर्डर कर दिए थे कि जो कारखानों लगे उसमें राजस्थान के आदमी को प्रैफ्रैंस दी जाए। जब कारखानों लगाने वालों को कर्जे देना शुरू किए तो उनसे पहले यह शर्त लिखवा ली कि कर्जा उस को मिलेगा जो राजस्थान को प्रैफ्रैंस देंगें।

लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हैं, यहां से चाहे सारे लोग भाग जांए, ये ऐसा कोई क्राइटीरिया नहीं बनायेंगें, अकेले ही राज करेंगें, मेरे ख्याल में ऐसी ही सूरत पैदा करना चाहते हैं। ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से बोलते हुए एक साथी ने कहा की हरियाणा में बेरोजगारी हैं ही नहीं, मुझे अफसोस हुआ यह सुनकर। गांवो में ऐसे आदमी बसते हैं जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए मकान नहीं मिलता। जिन गरीबों ने सरकार से कर्जे लिए उन को गिरफ्तार किया जाता हैं। हजारों की तदाद में लोग गिरफ्तार होते हैं। श्याम चन्द जी मिनिस्टर हैं, इनको पता हैं। लो सभा के इलैक्शन के पहले हजारों की तदाद में लोगों को पकड़–पकड़ कर हवालात में बन्द कर दिया। तहसील दार जी, इन्दिरा गांधी जी तुमसे राजी हैं। उन को जीपों में भर कर ले आये और जिन के जिम्मे कर्जे थे उन सब को हवालात में भेज दिया। एक हमारा भी साथी बन्द हो गया। हमने पूछा कि तू हवालात में कैसे बैठा हैं ? उसने कहा कि हवालात में हमारे लिए किल्ले कटने लग रहें हैं। जो किल्ला गांव में कटना था वह हवालात में कट रहा हैं। इन लोगो ने गरीब लोगों के किल्ले हवालात में कटवा दिए। स्पीकर साहब, हरियाणा में बेरोजगारी का मसला बहुत हैं, आप देखें, कितने ही नौजवान लडके हैं जिनको धन्धा मिलता ही नहीं हैं।

स्पीकर साहब, सरकारी कर्मचारियों के बारे में गवर्नर महोदय ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेरे ख्याल में जितने सरकारी

मुलाजिम हरियाणा में तंग हैं उतना शायद ही कोई तंग हो। तीस–चालीस हजार सरकारी स्कूल के टीचर्ज हैं, आप को मालूम हैं उनकी किस तरह से दुर्गति हो रही हैं। उन को अपने घर से सौ–सौ, दो–दो सौ मील दूर पटक दिया गया हैं जहां रहने के लिए मकान नहीं। बहुत रो लिए, धरने देकर देख लिया लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। चौधरी माडू सिंह शिक्षा मंत्री थे, उन्होंनें आशा दिलाई थी कि तब्दीली की नीति बदलेंगें शायद उनकी बात चली नहीं होगी जिसके कारण वे नीति नहीं बदल सके। कोठारी कमीशन की सिफारिश आज ती लागू नहीं की। इसी तरह से और भी मुलाजिम हैं जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर मुलाजिमों का चार साल का रिकार्ड देखें तो पता चलेगा कि जितनी रिट पैटीशन्ज सरकारी मुलाजिमों ने की हैं हरियाणा में, उतनी किसी दूसरी स्टेट के मुलाजमों ने नहीं की। यह इसलिए हुआ कि इनकी मेला–फाइडी इन्टेशन थी। जब सरकार ने देखा कि साबित होने वाला हैं तो उन की बात मान ली। इस तरह से वे सब इन्फ्रक्चुअस रिट्स हो गई हैं। इसके अलावा जो अफसर ईमानदारी से जानबदारी से काम करना चाहते हैं वे ठीक ढंग से नहीं रह सकते, वह अफसर ठीक ढंग से रह सकता हैं जो नाजायज काम करें। उसको छूट हैं वह जितनी मर्जी चाहे रिश्वत ले। मैं वजीर साहब को इस बात के लिये खुले तौर पर दावा करता हूं, सोनीपत में मैं एक अफसर दिखाऊंगा जो ईमानदारी से काम करना चाहता हैं लेकिन करने नहीं दिया जाता। ऐसे भी डिप्टी मिनिस्टर थे जिनके मुजारों के लिए नए बेदखली

के केसिज थे, उस अफसर के पास बार–बार मुजारे के खिलाफ सिफारिशें की गई और कहा गया कि इनके हक में करो। लेकिन उस अफसर ने नहीं किया। इन्होंनें उस अफसर के भाई को कहा कि यह अफसर एक हफ्ते से ज्यादा नहीं ठहर सकता और दूसरे दिन उसको तब्दील कर दिया जाता हैं। जो दूसरे अफसर हैं, जो इनके आगे–पीछे फिरते हैं उन की तब्दीली के चार दफा आर्डर गए लेकिन उनको बदल नहीं सके क्योकि वे किसी न किसी तरह इन्तजाम कर लेते हैं। आज हमारे अफसर ईमानदारी से, हिम्मत से काम नहीं कर सकते। जो अफसर इनसे दब कर रह सकता हैं वही हरियाणा में खुशी से रह सकता हैं। जो दब कर नही रह सके, जो मिनिस्टर्ज की मदद, एम0 एल0 एज0 को डिफैक्ट करवाने में मदद नहीं करेगा, वोटरों पर दवाब नही डालेगा वह यहां ठीक ढंग से नहीं रह सकता। जो इन कामो में सहयोग देगा वह मौज करता हैं, आप भी खायेगा और दूसरों को भी खिलायेगा। पोसवाल साहब को मालूम हैं, वे देख रहे हैं। तो मैं, स्पीकर साहब, बैठने से पहले एक बात अर्ज करना चाहता हूं और यह हैं कि यहां का किसान और सरकारी कर्मचारी, चाहे वह बिजली का लाईन–मैंन हैं या कोई दूसरा कर्मचारी हैं, विकास की जो तस्वीर आपने हाउस के सामने रखी उससे खुश नहीं हैं। कोई भी तबका ऐसा नहीं, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं चाहे वह कर्मचारी हैं, किसान हैं या कोंई दूसरा हैं, वह राजी नहीं। हां, राजी है वे जो मिनिस्टर्ज हैं या मिनिस्टरों के कहने से पार्टी बदल कर चले जाएं और चेयरमैन बन जाएं। स्पीकर साहब, जो ये डिफैक्शन की बात कहते हैं और

जिसके बारे में अपने भी फरमाया था कि नए चुनाव हुए हैं, आपस में मिल कर नई रवायाव डालेगें लेकिन नई रवायात का नमूना आप देख रहें हैं। जो पहले डिफैक्शन के लिए कहा गया उससे ज्यादा सरगर्मी के साथ भजनलाल जी और साथियों ने मुहिम तेज कर दी।

चौधरी भजन लालः शुरूआत आप ने की थी।

चौधरी रिजक रामः पैसा तक्सीम किया जाएगा। पीछे चैयरमैन इतने थे जिस का कोई ठिकाना नहीं एक इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट हमारे सोनीपत में भी हैं लेकिन आज तक वहां एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। उस एम0 एल0 ए0 को एक हजाररूपये तनखाह, कोठी सारा स्टाफ–सैक्रेटरी, क्लर्क, स्टेनों सब कुछ मिला हैं लेकिन एक पैसे का काम भी नहीं हो रहा हैं। श्याम चन्द जी को इन सब बातों का पता हैं। सारी कमेटीज इन्होंनें तोड़ी, मार्किट कमेंटियां तोंड़ी, फैडरेशन्ज बनाई और कारपोरेशन्ज बनाई सब जगह लेकिन इसके बावजूद भी इन बातों को छोड़ते हुए आखिर में मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि जहां विकास का इतना ढिंढोरा पीटा जाता हैं वहां इन सब बातों की तरफ भी ध्यान दें। ये देखें कि व्यापारियों की आज क्या हलात हैं ? चार सालों से जो नीति इस सरकार ने चलाई हैं उससे तो यहां व्यापार खत्म हो गया हैं। स्पीकर साहब, आप देखें कि हरियाणा इधर तो पंजाब से लगता हैं और उधर दिल्ली से लगता हैं। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन पर दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में सेल्ज टैक्स और

दूसरे टैक्सों में फर्क हैं। फूड–ग्रेन्ज को ही ले लिजिए। फूड–ग्रेन्ज पर हरियाणा में तीनरूपये सैंकड़ा टैक्स हैं, दिल्ली में बीस पैसे सैंकड़ा की मार्किट फीस हैं जबकि हरियाणा में एकरूपया हैं। एक सौ रूपये अनाज अगर कोई किसान हरियाणा की मंडी में बेचता हैं तो उसे पौने चाररूपये ज्यादा टैक्स देना पड़ता हैं और अगर दिल्ली में बेचता हैं तो इतनी रियायत से बिक जाता हैं। इसी तरह से पंजाब में बेचने से भी उसे फायदा रहता हैं क्योंकि वहां सैकड़े के ऊपर केवल एकरूपया सेल्ज टैक्स हैं। तो स्पीकर साहब, आज इस वजह से सारी सोनीपत तहसील का, सापला और बहादुरगढ़ के इलाके का और जींद तक का अनाज जो हैं वह दिल्ली, नरेला, नजफगढ़, और पंजाब में बिकता हैं। यही नहीं, आप देखें कि मैडिसन्ज और जनरल गुडज के ऊपर भी हरियाणा में तीनरूपये और छःरूपये सैंकड़ा टैक्स हैं। ऐक्सपोर्ट और री–ऐक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता हैं उसमें भी इमत्याज है और इसकी वजह से जो नरेला में बैठा हुआ दुकानदार हैं वह बम्बई से माल मंगवाता हैं और कलकत्ते में भेजते हैं मगर उसको री–ऐक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं देना पड़ता हैं। आज यहां व्यापार खत्म हो रहा हैं।(विघ्न) आप असलियत को देखने की कोशिश करें। आपको इस बात का पता नहीं हैं। आप ओम प्रभा जी से पूछिए जिनको बार–बार व्यापारियों ने डेपुटेशन लेकर कहा मगर उन्होंनें सुना नहीं और उन्होंनें नतीजा देख लिया। आपके पास यह महकमा नहीं था। इस टैक्स के रहते हुए अगर आप इस महकमे को चला कर देंखें तो फिर आपको पता लगेगा। स्पीकर साहब, मैंने आपकी कृपा से इस

हाउस का काफी टाईम लिया और आपनी सूझ के मुताबिक दो–चार बातें सरकार के सामने रखी हैं मगर बैठने से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोई बुराई या नुक्ताचीनी की वजह से नहीं बल्कि जो हम महसूस करें, उनको गौर से देखें और ऐग्जामिन करे और अगर उनसे हरियाणा का फायदा हो सकता हैं तो जरूर उन पर अमल करना चाहिए। मैं विरोधी पार्टी के सभी सदस्यों की तारफ से आपकी मार्फत, स्पीकर साहब, सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जितनी भी कोआप्रैशन इनको दे सकेंगें जरूर देगें मगर स्पीकर साहब को–ओप्रेशन तो रेसीप्रोकल होता हैं। उधर से अगर कोआप्रेशन होगा तो जो भी कोआप्रेशन हरियाणा के बनाने में, हरियाणा के फायदे में, हरियाणा के जो हक्क को हासिल करने के लिए , उनकी रक्षा के लिए हम सरकार को पूरा सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

चौधरी दल सिंह(जींद): माननीय स्पीकर साहब, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। जो बातें कही जा चुकी हैं मैं समझता हूं कि उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं। अलबत्ता कुछ बातें जो बहुत जरूरी हैं उनका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। गर्वनर साहब ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले चुनाव का जिक्र किया हैं और यह बात दोहराई हैं कि हरियाणा के अन्दर चुनाव बड़ी शान्ति और अमन से हुए। उन्होंनें यह भी कहा कि हरियाणा के अन्दर ला एंड आर्डर की सिचुएशन

बहुत अच्छी हैं और यही कारण हैं जिसकी वजह से यहां 70 फीसदी वोट अब पड़े हैं जबकि 68 के मध्यावधि चुनाव में 57 फीसदी वोट पड़े थे। स्पीकर साहब, अगर आप सन् 68 का अभिभाषण देखें तो उसमें भी ला एंड आर्डर की बड़ी तारीफ की गई हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर ला एंड आर्डर अच्छा होने से अब वोट 70 फीसदी पड़े हैं तब तो जब 57 फीसदी वोट पड़े थे उस वक्त ला एंड आर्डर खराब था। लेकिन वहां भी तारीफ की गई हैं। स्पीकर साहब, सरकार ने जो गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं वे भी छुपाए नहीं जा सकतें। औफिशयल मशीनरी का बड़ा भारी दुरूपयोग दो–तीन तरीकों से किया गया हैं। कुछ अफसरों ने वोट डालते वक्त इनकी मदद की हैं, कुछ अफसरों ने गिनती के वक्त मदद की हैं और कुछ नेरूपये और शराब से मदद की हैं। यह ठीक हैं कि बहुत से अफसर शामिल नहीं थे लेकिन यह भी ठीक बात हैं और साफ बात हैं कि अगर आप 12 तारीख के बाद के नतीजे देखें तो आप यह महसूस करेंगें कि चीफ मिनिस्टर के जीतने का जब एलान हो गया तो उसके बाद अपोजीशन की शिकस्त हुई हैं जबकि उससे पहले उसके ज्यादा मैंम्बर जीतते रहे हैं।(विघ्न) घबराईये नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने डुप्लिकेट बैलट पेपर्ज छपवा कर हरियाणा के अफसरों को तंग करके डलवाए हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, ये बिल्कुल गलत बात कहते हैं...(शोर).....

चौधरी दल सिंहः (बैलट पेपर हाथ में लिए हुए) स्पीकर साहब, एक बैलट पेपर आप देख सकते हैं।

चौधरी भजन लालः जनता ने आपको चुनकर भेजा हैं, कुछ ढंग की बात कहो।(शोर).....

चौधरी दल सिंहः आप न मानें, हमारा क्या हैं ? (विघ्न एवं शोर) आपको दर्द क्यों होता हैं। स्पीकर साहब, इनको मरोंड़ क्यों लगतें हैं। यह बैलट पेपर सरकारी हैं और हल्के का नहीं हैं।

चौधरी भजन लालः आपने अपना छुपा लिया होगा।

चौधरी दल सिंहः दूसरा ले लो।

चौधरी भजन लालः दूसरा किसी भाई का होगा।

चौधरी दल सिंहः तीसरा ले लो।

चौधरी भजन लालः तीसरा आपकी बीवी का हो सकता हैं।

चौधरी दल सिंहः चौथा ले लो।

चौधरी भजन लालः यह दूसरी बीवी का होगा। स्पीकर साहब , इनके बीवियां भी दो हैं।...(शोर).....।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि ये बैलेट पेपर्ज सरकारी प्रैस से छपे हैं और

इलैक्शन के सही बैलेट पेपर्ज हैं। मैं इनको आपकी मार्फत सदन की मेज पर रख रहां हूं कि ताकि ये भाई–बन्ध इनको देख सकें। स्पीकर साहब, इन्होंनें हरियाणा के अन्दर यह तमाशा बनाया हुआ हैं और बड़ा अफसोस यह हैं, बदकिस्मती हमारी, यह हैं कि ये बात सुनते नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः आप इनको बोलने दीजिए.....(विघ्न).....

चौधरी दल सिंहः बदकिस्मती यह हैं कि आप सुनते ही नहीं हैं और सच्ची बात को मानते नहीं हैं।

चौधरी भजन लालः आपके खिलाफ तो चोरी का पर्चा लिखना पड़ेगा।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, चोरी का पर्चा तो इनके खिलाफ लिखवाना पड़ेगा। हमारे पास तो सैंकड़ो बैलेट पेपर्ज डाक से आए हैं। आपको चाहिए हों तो कल ला दूगां। आपको परेशानी क्यों हैं ? (विघ्न)

स्पीकर साहब, मैंने बाई–इलैक्शन 70 में लड़ा था। आपकी सरकार उस वक्त थी। मैंने इसी हाउस में आपके चीफ मिनिस्टर साहब को चैलेन्ज किया था कि मैं आंयदा जींद से इलैक्शन लंडूगा और जीतूगां। और मैं जीता भी हूं। (विघ्न)

*अध्यक्ष महोदय ने बैलेट पेपर्ज मेज पर रखने की अनुमति नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : मैंम्बर साहिबान बीच में बातें न करें। इस प्रकार से हाउस का समय बरबाद होता हैं।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश यह हैं कि अगर इस प्रकार से मुझे बीच में टोकते रहें तो मैं ठीक प्रकार से नहीं बोल सकता हूं। मैं पहले कह रहा था कि इस सरकार ने इलैक्शन के दौरान सरकारी मशीनरी का इतना दुरूपयोग किया हैं जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। जब यह असैम्बली डिजाल्व हुई थी उस टाईम पर विधान सभा के केवल 78 मैंम्बर्ज थे। 55 कांग्रेस के थे और बाकी दूसरी पार्टीज के थे। परन्तु इस इलैंक्शन में ये केवल 52 मैम्बर्ज कांग्रेस के आये हैं।

चौधरी भजन लालः हम 52 मैंम्बर्ज नहीं हैं बल्कि 62 हैं।

चौधरी दल सिंहः यूं तो मैंम्बर्ज को पैसा देते रहे और मैम्बर्ज को तोड़ते रहे तो बात अलहदा हैं। परन्तु यह बात आपको माननी ही पड़ेगी और हमने साबित करके दिखाई हैं कि आप केवल 52 मैंम्बर्ज आए हैं 81 में से जबकि पहले आप 55 मैम्बर्ज थे। इसलिए आपकी इस इलैक्शन में हार हुई हैं। इस इलैक्शन में गन्दी और बड़ी नजायज बातें हुई हैं कि सरकारी मशीनरी का जो प्रयोग हुआ हैं यह नहीं होना चाहिए था। प्रजातंत्र के अन्दर इस प्रकार से धक्केशाही नहीं होनी चाहिए। आप पिछली हिस्टरी को देखें और कितनी ही मिनिस्ट्रीज आयी और कितने ही चीफ

मिनिस्टर आए परन्तु ऐसी हालत कभी नहीं हुई। प्रजातंत्र में किसी किस्म की भी धक्केशाही प्रजातंत्र के ताबूत में कील गाड़ने के समान हैं।

स्पीकर साहब, गर्वनर साहब ने अपने अभिभाषण में बंगला की चर्चा की हैं परन्तु बड़े अफसोस की बात हैं कि जहां उन्होंनें बंगला देश की चर्चा की वहां उन्होनें अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा कि अब बंगला देश का कोंई मसला नहीं हैं। न लडाई का ही मसला हैं न रिफ्यूजीज का मसला हैं। जब बंगला देश का कोई मसला ही नहीं हैं तो फिर उन्होंनें इन टैंक्सों का क्यों नहीं कोई जिक्र किया हैं। यह किस लिए अब भी सरकार ने लगाए हुए हैं। अब भी टैक्सों का लगा रहना, कितनी गम्भीर बात हैं। सैन्टर के द्वारा लगाये गये टैक्सो की बात मान भी लें परन्तु जो हरियाणा सरकार की ओर से टैक्सिज लगाये गये हैं उनको लागू रखने की कौन सी वजह हैं। आज भी बंगला देश के नाम से टेक्सिज लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से गुजारिश कंरूगा कि जो भी इस प्रकार से गलत टैक्सिज लगाये हुए हैं वे अब खत्म होने चाहिए । बंगला देश का मकसद हल हो गया हैं, बंगला देश आजाद हो चुका हैं, रिफ्यूजी प्रोबलम भी खत्म हो चुकी हैं इसलिए ये टैक्सिज खत्म कर देने चाहिए। (विघ्न)

स्पीकर साहब, इस अभिभाषण के पेज तीन पर कहा गया हैं कि फोर्थ फाईव ईयर प्लान के पहले दो वर्षो के अन्दर राज्य की आमदनी के अन्दर 15.191 प्रतिशत बढ़ोत्तरी रही जबकि

सारे देश की वार्षिक वृद्धि पांच प्रतिशत थी। परन्तु इसी सरकार का जो 10 जनवरी सन् 1972 का जो गवर्नर एड्रैस हैं उसके पेज चार पर जो बढ़ोत्तरी दिखायी गयी हैं वह 16.19 प्रतिशत की हैं। मेरी यह समझ नहीं आता कि यही सरकार उस गर्वनर के अभिभाषण को तैयार करने वाली हैं, यही गवर्नर साहब पढ़ने वाले हैं, फिर क्या कारण हैं कि इसमें 15.91 की वृद्धि दी हुई हैं और पहले वाले में 16.91 की वृद्धि दी हुई हैं। इस सरकार ने अजीब तमाशा बनाया हुआ हैं। गवर्नर साहब के अभिभाषण में भी गलत बातें लिखी जाती हैं और भी जो फिगर्ज दी गयी हैं वे भी गलत हैं। इन्होंनें कहा हैं कि गेंहू की वसूली में सरकार ने बड़ी भारी बढ़ोत्तरी की हैं। इस एड्रैस के सफे चार के अन्दर कहा गया हैं कि सरकार ने सन्1971 में 7.1 लाख टन की गेहूं की वसूली की हैं परन्तु जो अभिभाषण 10 जनवरी, 1972 को दिया गया था उसके पेज पर सात पर कहा गया हैं कि सन् 1971–72 में 7.09 टन गेहूं की वसूली की गयी हैं। अब मेरी यह समझ में नहीं आता कि इनकी कौन सी बात सच्ची मानी जाये। यही सरकार उसको तैयार करने वाली हैं और यही गवर्नर साहब उसको पढ़ने वाले हैं। यह तो अजीब किस्म का अभिभाषण रखा गया हैं। बड़े अफसोस की बात हैं। इस विषय में एक बात और खास काबिले गौर हैं। जहां इन्होंनें वसूली का जिक्र किया हैं वहां गर्वनर साहब ने डार्क पहलू तो रख दिया परन्तु ब्राइट पहलू की ओर नहीं देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने फैसला किया हैं कि इस साल गेहूं की कीमत पर चाररूपये क्विंटल के हिसाब

से कम होगी परन्तु दूसरी ओर सरकार ने खाद के ऊपर टैक्स लगा दिया हैं, ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया हैं! मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस खाद को कौन इस्तेमाल करता हैं। जब खाद की कीमत बढ़ी हैं और ट्रैक्टर की कीमत भी बढ़ी हैं तो किसान जो कुछ प्रोड्यूस करता हैं उसकी चीजो की कीमत भी घटनी चाहिए। अभी पिछले दिनों में पंजाब सरकार ने स्टेटमैंट दिया हैं कि अनाज की जो कीमते घटी हैं उस बारें में हम भारत सरकार पर जोर डालेंगें कि ये बढ़ायी जायें। परन्तु बढ़े दुख के साथ कहना पड़ता है हरियाणा सरकार के किसी भी मिनिस्टर या किसी भी मैम्बर ने एक भी लफ्ज आज तक नहीं कहा कि जो किसान की पैदावार की कीमतें घट रहीं हैं ये हम नहीं घटने देगें। जो कीमतें पहले किसानों को मिलती थी वहीं कीमते मिलेंगी। अब कन्ज्यूमर, उपभोक्ता को भी ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी क्योंकि भारत सरकार ने जो 120 करोड़रूपये की सबसिडी रखी हुई थी अब 80 करोड़ घटा कर केवल चालीस करोड़ रह गयी हैं। अब जो भी गरीब मजदूर होगा उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। इसलिए आज उस बेचारे पर दोहरी मार पड़ेगीं फिर यहां पर यह कह जाता हैं कि हरियाणा में भी बड़ी भारी तरक्की हुई हैं। हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि गरीब और किसान के लिए इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं हैं।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब दो बातें मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। इनके अफसर भी कहते हैं और वजीर साहिबान भी अलाप करते हैं, हर असैम्बली सैशन में इलैंक्ट्रीसिटी का जिक्र किया हैं कि हमने गांव–गाव के अन्दर सप्लाई की हैं और 26 जनवरी तक गांव–गांव में सड़क पहुंचा देंगें लेकिन डार्क पहलू की ओर नहीं देखा। वैसे तो चौधरी रिजक राम जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया हैं परन्तु फिर भी मैं कुछ और भी बातें इनके नोटिस में लाना चाहता हं। जमीदारों से एम0 सी0 जी0 का एग्रीमेंट करते हैं परन्तु मैं तो ईमान से यह कहूगां कि कोई भी बिजली का कनैक्शन रिश्वत के बगैर नहीं दिया जाता हैं।

चौधरी भजन लालः चेयरमैंन साहब जब भी ये स्पीच करते हैं सिवाए कुरप्शन के कोई रिश्वत ही नहीं करते है।

चौधरी दल सिंहः मैंने तो बात वैसी ही करनी हैं जैसी होगी।

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहब अभी इन्होंनें कहा हैं कि मैं ईमान से कहता हूं कि कोई भी कुनैक्शन बगैर रिश्वत के नहीं देते है। यह सब गलत हैं।

Chaudhri Dal Singh: This is not teh way. This is not the proper way to interrupt.

Mr. Chairman: No interruptions please.

चौधरी दल सिंहः चेयरमैन साहब इनके महकमे का भी जिक्र नहीं हैं। मेरी गर्ज किसी को बदनाम करने की नहीं हैं और न ही मेरा किसी मिनिस्टर पर लान्छन लगाने का विचार हैं।

चौधरी भजन लालः चेयरमैन साहब, इन्होंनें अभी कहा हैं कि ईमान से कहता हूं कि कोई भी कनैक्शन बगैर पैसे के नहीं मिलता हैं। क्या इनका यही ईमान हैं जो कि कितनी बेबुनियाद बात हैं ?

चौधरी दल सिंहः मेरी गर्ज यह हैं और अगर आपको दिमाग में जंच जाये और ठीक बात जंचे तो मान लेना। आपका और सरकार का यह फर्ज हैं कि जेा कमिंया हम बतायें उनका इलाज करें। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके कर्मचारी गरीब जमीदारो के ट्यूबवैलों पर जाते हैं और उनके ट्यूबवैलों के मीटर को खराब करके बन्द करके आ जाते हैं। अब आप ही बताइये कि जब वह मीटर बन्द हो गया तो घाटा किस को हुआ, वह स्टेट को घाटा होता हैं। वे कर्मचारी जमींदारों से दसरूपये या 15रूपये ले लेते हैं और मीटर को बन्द कर देते हैं जो इन्कार करता हैं उसकी एक्स0 ई0 एन0 और एस0 डी0 ओ0 को रिपोर्ट कर देते हैं कि फला जमीदार का मीटर डैड पड़ा पाया गया हैं इसलिए उस पर जुर्माना किया जाये। इस तरह से जमींदारों से पैसा लिया जाता हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो भ्रष्टाचार हैं बिजली के डिपार्टमैंट में, इसको दुरूस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत हैं।

अभी पिछले दिनों हमने चीफ मिनिसटर साहब के खिलाफ एक ममोरेन्डम दिया था उसके बारे में कोई सुनायी नहीं होती हैं, हमने बार–बार कहा हैं कि उस पर गौर करना कोई भलाई की बात नहीं हैं।

अब मैं एम0 सी0 जी0 के विषय में भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह आपके हक की ही बात हैं (विघ्न) ट्रांस्फार्मर जल जाते हैं और बिजली नहीं पहुचती हैं तो भी सरकार एम0 सी0 जी0 का पैसा वसूल करती हैं (विघ्न) जब एम0 सी0 जी0 मुकर्रर कर रखी हैं तो बिजली की सप्लाई पूरी करनी चाहिए। जब सप्लाई पूरी नहीं कर सकते तो एम0 सी0 जी0 का पैसा किस लिए मांगते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस अर्से के अन्दर, जिस पीरियड के अन्दर पूरी बिजली की सप्लाई नहीं दे सके हैं उस पीरियड की एम0 सी0 जी0 लागू नहीं होनी चाहिए। मुझे पता लगा हैं कि सरकार अब जल्दी ही एम0 सी0 जी0 का सिस्टम भी खत्म करने जा रही हैं।

एक बात मैं और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। क्योंकि **(5.00 P.M.)**आपका मैंटीरियल इन्फीरियर क्वालिटी का लगा हुआ हैं इसलिये बिजली के मीटर जले हैं। पहले यह कायदा था कि अगर कोई मीटर जलता हैं तो उसकी वजह से मालूम करते थें कि उसमें कसूरवार कौन हैं, आया कन्जयूमर की गल्ती से वह मीटर जला हैं या किसी सरकारी कर्मचारी की गलती से या इलैंक्ट्रिसिटी का लोड ज्यादा होने की वजह से जला हैं ? लकिन

अब क्या होता हैं ? मीटर चाहे किसी के भी कसूर से जला हो, किसान को 272रूपये जमा कराने पड़ेगें तब जाकर उसको नया मीटर मिलेगा। वह बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता। चाहे उसका कसूर हो या न हों, उसे पैंसे भरने पड़ते हैं। अगर वह कुछ कहें भी तो कह देते हैं कि आपके मीटर को लैबोरेटरी में भेजेगें। वहां से टैस्ट होने के बाद जो तय करेंगें, वह काट कर, बाकी पैसे आपको वापिस कर देंगे।(विघ्न) मिनिस्टर साहब, श्री भजन लाल जी आप तो वैसे ही नराज होते हैं, मैं तो केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं । जिला जीन्द में हजारों की तादाद में मीटर जले हैं। यदि उनमें से किसी एक को भी मीटर की कीमत वापिस मिली हो तो मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे दूगां। आपने किसानों को लूटने का यह तमाशा सा बना रखा हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि यह किसानों की सरकार हैं मगर दूसरी तरफ बात की तहकीकात करवाइये कि जिला जीन्द में कितने मीटर जले हैं और उनमें से अगर एक मीटर के भी पैसे आपने वापिस किये हुए हों तो जो सजा आप कहेंगें , मैं भुगतने के लिए तैयार हूं ।यह न करो कि अफसरों और मुलाजिमों को डिफैन्ड करते रहो। यही बात पिछली दफा हुई। जीन्द के अन्दर आपके यहां से चोरी हुए बिजली के ताम्बे के तार बरामद हुए। अव्वल में तो ताम्बे के तार आपके पास हैं ही थोड़े फिर भी जो एक आध थे, वह जब बरामद हुए तो जिन कर्मचारियों ने वे तार बेचे थे, उनकों कोई भी पकड़ने वाला नही था क्योंकि आप उनके डिफैन्डर रहे हैं। जिन गरीब आदमियों के घर से तार बरामद हुए, उनके खिलाफ आप

मुकदमें चलाते हैं लेकिन तार बेचने वालो के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। मैं मानता हू कि वे कसूरवार हैं, लेकिन क्या यह जरूरी हैं कि अगर किसी का नाम एफ0 आई0 आर0 में दर्ज हुआ हैं, जो गरीब आदमी हैं और व्यापार करता हैं, आप सिर्फ उसी को सजा दें। मैं तो यह कहता हूं कि दोनों ही कसूरवार हैं। दोनों के ही खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। ताकि हमें यह पता लग जाये कि उसमें आपका कौन सा एस0 डी0 ओ0 या एक्स0 ई0 एन0 इन्वाल्वड हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आज हरियाणा के अन्दर बिजली आयी ही नहीं, बिजली गिर गयी हैं। अगर आपकी यही हालत रही तो सारे हरियाणा प्रान्त के बारें में तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन जीन्द के बारे में कहता हूं कि हो सकता हैं, यहां पर लोग कुनैक्शन कटवाना शुरू कर देगें। वहां के कुछ लोग तो अब भी कुनैक्शन कटवा रहें हैं। आपके 90 प्रतिशत बिजली के बिल गल्त होते हैं। सरकार ने अब ये इन्स्ट्रक्शन्ज जारी कर दी हैं कि बिल की रसीद पर कन्जयूमर के हस्ताक्षर होने चाहियें। आप इसी बात की पड़ताल करवाइये। अगर 50 प्रतिशत बिलों के बोगस दस्तखत न हुए हो तो मैं कसूरवार ठहरूंगा। आपको अपने स्टाफ के साथ भी स्ट्रिक्ट होना चाहिये क्योंकि आपका बिजली बोर्ड उन्हें तनख्वाह देता हैं और तमाम सहूलियतें देता हैं। उनमें से जो कुरप्ट हैं, उनके खिलाफ एक्शन लो और जो ईमानदार हैं, उनको तरक्की दो। एक तो आपके कर्मचारी बिजली के बिल वक्त पर नहीं देते, दूसरे कई बार जान–बुझकर बोगस दस्तखत करके कन्जयूमर को बिल नहीं देते।

बिल न मिलने की वजह से वह बेचारा बिल नहीं दे पाता और उसकी बिजली डिस–कुनैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद उस को 25रूपये जुर्माना भरना पड़ता हैं, तब कहीं जाकर उसे कुनैक्शन मिलता हैं। गेहूं की अब फसल निकलनी हैं , आप कभी जीन्द में आ जाना। मैं आपको ऐसे मीटर दिखाऊंगा जो बिना किसी कार्यवाही के और बिना किसीरूकावट के हेराफेरी से चलेंगे। ऐसे एक–आध नहीं, सैंकड़ो चलेंगे। इस बारे में यदि मैं कुछ कंहूगा तो आप हरियाणा के अन्दर मची हुई है, वह खत्म होनी चाहिये ताकि किसानों का भला हो सके। पिछली बार 10 जनवरी को गवर्नर महोदय ने जो एड्रैस इस सदन के सामने पढ़ा था, उसमें यह कहा गया था कि हरियाणा के अन्दर सन् 1971 के दौरान 9 एलोपैथिक डिस्पैंसरियां और 10 आयुर्वैदिक डिस्पैंसरिया खोली गयी हैं यह एक अजीब सा तामाशा हैं कि जीन्द का हल्का जो कांग्रेस का हल्का हो रहा हैं, में एक बड़े गांव में भी कोई डिस्पैंसरी नहीं हैं। अपोजीशन की बात आप न मानें, यह आपकी मर्जी हैं। हमारे यहां पर एक मटोर गांव हैं, उसकी 9000 की आबादी हैं, आप यह सुनकर हैंरान होंगें कि वहां पर कोई डिस्पैंसरी नहीं हैं, न वैटरनरी डिस्पैंसरी हैं, न एलोपैथिक डिस्पैंसरी हैं और न ही आयुर्वैदिक डिस्पैंसरी हैं। इस गवर्नमैंट के कौन से अफसर का दिमाग हैं जो प्लांनिग करता हैं और जिसने इस किस्म की कोताही की हैं कि हरियाणा के एक बहुत बड़े गांव में, जो जीन्द का सबसे बडा़ गांव हैं, कोई डिस्पैंसरी न हों। उस गांव तक सड़क जाती हैं और वह 4 मील लम्बी हैं परन्तु वहां तक

बस का कोई प्रबन्ध नहीं हैं। गांव के लोग 4 मील पैदल चल कर जाते हैं, तब कहीं उन्हें बस मिलती हैं। आप बहुत शेखी मारते हैं कि हमने इतनेरूट नैशनेलाईज कर दिये लेकिन मैं पूछता हूं कि आपने उन्हें कौन सी सहूलियत दी है ? यह इतना बड़ा गांव हैं कि वहां का रिप्रजैटेशन 3,500 वोटो का हैं। चेयरमैन साहब, उस गांव तक सड़क अवश्य बनी हुई हैं लेकिन उस गांव के अन्दर बसें नहीं जाती। मेरी गुजारिश यह हैं कि अगर वाकई आप हरियाणा का भला चाहते हैं तो चाहे कोई भी गांव क्यों न हो और किसी भी हल्के में क्यों न पड़ता हो, वहां पर और इस बड़े गांव के अन्दर, एक–एक डिस्पैंसरी का बन्दोबस्त होना बहुत जरूरी हैं। हरियाणा सरकार के भी यह हित में है।

मैं सड़को का भी यहां जिक्र करने जा रहा था। सड़कों के मामले में भी यहां एक अजीब सा तमाशा बना हुआ हैं। चौधरी रिजक राम ने इस बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार किस चीज का क्रैडिट लेती हैं। इस अभिभाषण में लिखा हैं कि सड़को के निर्माण के लिये 1970–71 मैं 87 लाखरूपये मार्किटिंग फीस द्वारा इकट्ठे किये गए। चेयरमैन साहब, आप मार्किटिग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, इसलिए आपको यह पता हैं कि यह फीस पहले 100रूपये पर 20 पैसे होती थी। लेकिन अब इस सरकार ने यह फीस 100रूपये पर 100 पैंसे कर दी हैं। यानि यह फीस पांच गुनी बढ़ा दी हैं। 1970–71 में इस फीस से 87 लाखरूपया इकट्ठा किया हैं और

1971–72 में 300 लाखरूपया इकटठा कर रहें हैं जिससे 500 किलो मीटर लम्बी सड़के बन सकती हैं। आप ही देखिये, लाखों के फर्क हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का तमाम एक्सपैंडिचर अन–प्लान्ड और अन–प्रोडक्टिव हैं। ये हरियाणा का जल्दी ही दिवाला निकालने वाले हैं। सड़को में ईटें दोयम दर्जे की लगा दीं, रोड़ी कम डाल दी , तारकोल खा लिया और इस तरह की कोई दूसरी हेरा–फेरी कर ली, यही इनका काम हैं। आज हरियाणा में यही चीज ज्यादा हो रही हैं। मैं ईमान से कहता हूं कि यह जो तरक्की कहते हैं और शेखी मारते हैं कि हर गांव में सड़के पहुंचानी हैं, इसने गांव–गांव का दिवाला निकाल देना हैं। अगर आपकी कान्शीयस ठीक हैं तो हरियाणा का दिवाला निकलने से अभी भी बचा लो। अगर आपके हाथ रिश्वत से रंगे नहीं हैं तो मैं गुजारिश कंरूगा कि जिस तरह से चौधरी रिजक राम ने कहा है, बेशक आपके आफिसर्ज यह प्रोग्राम बन्द कर दें, मगर इसे जारी रखना है तो जारी रखें पर अच्छा मैटिरियल लगायें ताकि ये आये दिन टूटे नहीं। जो सड़क उचाना से पलवल की बनी हैं, वह टुटी पड़ी हैं। मेरे हल्के में जुलाना से लजवाना कलां तक की सड़के को आप जाकर देख लीजिए। मतलब यह है कि आज सड़कों की बहुत बुरी हालात हैं। उचाना से करसन्धु की सड़क को भी आप देख सकते हैं, उसकी क्या हालत हैं ? यह बड़ी हैरानी की बात हैं और फिर मेरे कहने मे आपको दर्द होता हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि हरियाणा के अन्दर आपने जो लूट मचा रखी हैं, इसे खत्म करना चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके।

एक और बात इम्प्रूवमैंट की बाबत कहना चाहता हूं। आपकी मार्फत वजीर साहब का ध्यान इस बात की और दिलाना चाहता हूं। इन इम्प्रूवमैंट का कौन सा फायदा हैं जो बना रखे हैं ? इन्हें अब खत्म करनाा चाहिए। पहले तो ठीक था, क्योकि आपकी तादाद कम थी और आपने लोगों को ओवरलाईज करना था, इसलिये उनके रिश्तदारों को इम्प्रूवमैट ट्रस्ट्स का चेयरमैन बना दिया। जितना आपने इन्हें इस्तेमाल करना था कर लिया। अब इन्हें खत्म करना चाहिये क्योंकि अब तो आपकी तादाद ज्यादा हैं। अब कौन सी ऐसी वजह हैं कि अब भी आप ने चेयरमैन रखे हुए हैं। जीन्द के इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के बारे में मैं आपको बतलाऊं। इस ट्रस्ट ने सड़कों में एक ईट भी अव्वल दर्जे की कहीं नहीं लगाई हैं, जबकि अव्वल दर्जे की लगनी चाहिएं। इन्होंनें दोयम दर्जे की ईटें लगायी हैं और सड़के जगह–जगह से टूट रहीं हैं। आबादी वाली जमीन को इस ट्रस्ट द्वारा एक्वायर किया जा रहा है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिये। इस ट्रस्ट ने तमाम सैनियों की जमीन और हरिजनों के मुर्दघाट की जमीन एक्वायर कर ली हैं। इस ने यह एक बड़ी भारी गलती की हैं। लोगों को ये कहते हैं कि 5000रूपये दो, आपकी जो जमीन एक्वायर हो रहीं हैं, वह छूट जायेगी और असल में वह एक्वायर होनी ही नहीं होती । इन्होंनें वहां पर गदर मचा रखा हैं। इसलिये मेरी गुजारिश यह हैं कि इस लूट को खत्म किया जाना चाहिए। अगर इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट वाकई शहर की इम्प्रूवमैंट करने के लिये बनाये हैं तो अवश्य बने रहने चाहियें लेकिन ऐसी चीजें अवश्य खत्म होनी चाहियें। जीन्द में तो

आपने तमाम इलाके को ही कन्ट्रोल्ड एरिया करार दे दिया हैं। इसलिये अब वहां पर कोई भी प्राइवेट कालोनी नहीं बन सकती । चीफ मिनिस्टर साहब ने यहां आश्वासन दिया था कि आइन्दा सरकारी तौर पर यानी अपने जरिये से कालोनी बनाई जायेगी। मैं पूछता हूं कि उस इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की क्या जरूरत हैं ? उसके चेयरमैंन को एक–एक हजाररूपया तनख्वाह देते हैं, 250रूपया वे कार के लेते हैं और फिर कहते हैं कि यहां कालोनी नहीं बन सकती। आप देखिये कि भिवानी रोड पर आपके इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन का बाकायदा बोर्ड लगा हुआ हैं और उसने वहां कालोनी सी बना ली हैं और आप उसको रोक नहीं सकते है।

हरियाणा में जब इस तरह के हालात हों और हम उसका जिक्र न करें तो इसका मतलब होगा कि हम अपने फर्ज को निभाने में कोताही कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप हरियाणा को तबाही से बचाना चाहते हैं तो ऐसे इम्प्रूवमैट ट्रस्ट जहां कुछ काम नहीं होता, जहां पिछले डेढ़ साल में कुछ भी काम न हुआ हों, जहां 20–30 हजार भी साल में खर्च न होता होता हो, को खत्म कर देना चाहिए।

ऐजुकेशन की बाबत भी बड़ा जिक्र किया गया। ठीक हैं, शिक्षा का फैलाब होना चाहिए।

चेयरमैन साहब, आप तो एजुकेशन की लाइन में रहें हैं, आपको टीचरों की तकलीफात का एहसास हैं। मैं आपसे गुजारिश

कंरूगा कि आप चीफ मिनिस्टर को समझांए, ऐजुकेशनल वजीर को समझांए कि वह टीचरों की तकलींफो को दूर करें । अगर पिछले इलैक्शन में कोई ऐसी बात हो गई थी तो कम से कम अब तो वह नाराजगी दूर हो जानी चाहिए।

किसी देश का समृद्धशाली उसके बच्चों पर निर्भर करता हैं। बच्चें तभी अच्छे और योग्य बन सकते हैं जबकि टीचर उन्हें अच्छी शिक्षा देंगें। जब टीचर संतुष्ट ही नहीं होंगे, उनके दिमाग में परेशानी बनी रहेगी; वह सोचेगें कि हमारे साथ बेइन्साफी हो रही हैं तो वे अच्छी शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं। आज हालत यह हैं कि वे बेचारे अपने घरों से दूर पड़े हैं, गांवो में उनके रहने के लिए मकान नहीं मिलते, उन्हें अपने बाल बच्चों की चिन्ता रहती हैं, ऐसी स्थिति में वे बच्चों को कैसे योग्य बना सकते हैं। आज हरियाणा में पढ़ाई की बहुत ही हालत खराब हैं। अगर यही हालत रही तो हरियाणा में सिर्फ स्कूल की बिल्डिगें ही रह जाएंगी बाकी सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि टीचरों के साथ इन्साफ होना चाहिए। जो बड़े–बड़े गांव हैं और जहां के लोग बिल्डिग की शर्त को पूरा करते हैं वहां के स्कूल को अपग्रेड कर देना चाहिए। ढाकल और बरहा खुर्द दो गांव हैं जहां पर पिछले दस साल से बिल्डिंग बनी हुई हैं। वहां मिनिस्टर गए भी थे और एलान मेरे सामने किया कि इन स्कूलों को अपग्रेड कर देंगें लेकिन आजतक कुछ नहीं हुआ। कोई सुनायी नहीं हैं। जींद जंकशन के स्कूल में एक हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। तीन सौ

लड़कियां यहां से पढ़ने शहर में जाती हैं। आजकल जमाना कितना खराब हैं। जवान लड़कियां इतनी दूर पढ़ने शहर में जाती हैं। कितनी मुश्किल आती हैं लेकिन उसको अपग्रेड नहीं किया गया। मैं तो इस साल ही आया हूं पिछले साल तो बाबू दया कृष्ण थे। उस वक्त तो वहां पर बनाना ही चाहिए था। मगर सरकार को डिपार्टमैंट की मार्फत छान–बीन करनी चाहिएकि जो बड़े–बड. गांव है चाहे वे किसी कांग्रेंसी मैंम्बर के हल्के में हो या अपोजीशन मैंम्बर के हल्के में हो और जहां पर वाकई जरूरत हो तथा वे बिल्डिंग की शर्त को पूरा करते हों तो वहां पर स्कूल को अपग्रेड किया जाए।

लैड रिफार्म के बारे में चेयरमैंन साहब इन्होंनें बड़े नारे लगाए। लोक सभा में इलैक्शन के समय भी इन्होंनें कहा कि हम तीन महीने के अन्दर जमीन दे दें देगें, फिर कहनै लगे कि कोई जमीन नहीं हैं। फिर फेमिली प्लानिंग की एक स्कीम आई कि इसके लिए जमीन के बहाने हरिजनों को फांसाया जा सकता हैं। चुनाव तीस तारीख मुकर्रर कर दी। लोगों को कहा गया कि जिसको अर्जी देनी हो वह दे दो, मैंने जींद के अन्दर हजारों की तादाद में लोगों को कतार में खड़े देखा। सवारूपये का टिकट पांचरूपये बलैक में बिका और फिर तहसीलदार साहब फरमाने लगे कि दो किल्ले जमीन चाहिए तो एक नसबंदी करा लो, अगर चार–पांच किल्ले चाहिए तो दो तीन की नसबन्दी करा लो। इस सरकार ने हजारों गरीब हरिजनों को खस्सी करा दिया और एक

इंच जमीन नहीं दी। आज भी यह कहते हैं कि हम जमीन देंगें। यह हैं इनके लैंड रिफार्म की हालातं। मैने पिछली असैम्बली में यह पूछा था कि हरिजनों को कितना कर्जा दिया गया ? जवाब आया कि 34 लाख। अब पता चला हैं कि 56 लाखरूपया लैप्स हो गया। एक तरफ तो हरिजनों की भलाई के ढोल पीट रहे है और दूसरी तरफ 56 लाखरूपया लैप्स हो गया। कहते हैं कि मन्जूरी नहीं मिली। मैं कहता हूं कि मन्जूरी देनी तो आपके हाथ में थी। मन्जूरी देने में किसने कोताही की, इस पर एक्शन होना चाहिए और गरीबों को ठीक प्रकार से कर्जे देने चाहिए जिससे उनकी मदद हो सकें। मैंने एक सवाल ट्रैक्टरो के सम्बन्ध में पूछा था। उन्नीस ट्रैक्टरों के दाम नौ हजार फी ट्रेक्टर के हिसाब से ये गुलाब सिंह बैठे हैं, ये ले गए, 81 हजार हुन्नामल ले गए। मैंने पूछा कि जब हरिजनों के पास एक किल्ले जमीन नहीं हैं तो वह ट्रैक्टर चलाएगें कहां, क्या करेंगें वे। जाली हरिजन नामो से ट्रैक्टर लेकर किसी और को दे दिए जाएंगे। इस बात का जवाब सरकार के पास कुछ नहीं हैं। जो सच्चाई हैं उसको क्यों छुपाते हो। गरीबों के साथ कुछ तो हमदर्दी रखनी चाहिए। आज हरिजनों के बच्चे बेरोजगार फिरते हैं। कहा यह जाता हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी नहीं हैं। मैं तो यही कहता हूं कि यहां पर काफी बेरोजगारी हैं, काफी पढ़े–लिखे बेकार फिरते हैं और जिनको नौकरी दी जाती हैं उसमें भी कहां तक पक्षपात होता हैं इसकी भी मैं एक मिसाल रखना चाहता हूं। पिछले साल की ही बात हैं 19 ए0. एस0 आई0 इन्होंनें लिए। इनमें से 13 ए0 एस0 आई0

सिर्फ तहसील भिवानी से लिए और बाकी दो और जिलों से लिए और जिंद का एक भी नहीं। यह साफ पक्षपात हैं, नेपोटिज्म हैं और बात करते हैं इंसाफ की, ईमानदारी की। मेरा कहना तो यही हैं कि जिस किसी को भी नौकरी दी जाए वह मैंरिट पर हो, क्वालीफिकेशन के आधार पर हो। चाहे फिर वह किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

एक और बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो कि हरियाणा के लिए बड़ी घातक हैं और जिसके लिए पूज्य महात्मा गांधी ने भी मना किया था, वह हैं शराब। आज हरियाणा में शराब की खुली छुट्टी हैं। पिछले साल जींद में सात लाख का ठेका देकर कोई भी अंग्रेजी शराब की दुकान खोल सकता हैं। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहें हैं, आप हरियाणा के करैक्टर को बरबाद कर रहें हैं, यहां के इखलाक को खत्म कर रहें हैं, आप हरियाणा के दिमाग को खत्म करना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि आप कोई अच्छी स्कीम बनांए, कोई कारखाने खोलें, यह नहीं होना चाहिए कि शराब की दुकानें खोलते चले जाएं। आज ऐसे कितने ही जमींदार हैं जो शराब पीने से बरबाद होते चले जा रहें हैं। सरकार को शराब की कमाई को कम करना चाहिए नहीं तो जमींदारों के बहुत घर तबाह हो जाएंगे।

एक आखिर बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। बडे अफसोस की बात हैं कि गवर्नर महोदय ने बहुत सी बातें कहीं

सरकार के कार्यों की, मगर सरकारी कर्मचारी जो बहुत करप्ट हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया। आज हरियाणा के अन्दर कोई जगह नहीं जहां बिना रिश्वत के काम हो जाए। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं हैं। हर जगह रिश्वत का बाजार गर्म हैं। जब यही लोग एम0 एल0 ए0 को तोड़ने के लिए पन्द्रह–बीस हजार की रिश्वत दे सकते हैं तो फिर कैसें आशा की जा सकती हैं कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करें। मैं यह गुजारिश करूंगा कि यह चीज बन्द होनी चाहिए। जो लोग पैसा लेकर काम करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ जो यह प्रस्ताव रखा गया हैं मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

मलिक सतराम दास बतरा(कलानौर): माननीय चेयरमैन साहब, बड़ी खुशी की बात है नव–निर्वाचित विधान सभा के स्पीकर श्री बनारसी दास गुप्ता चुने गए हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ पत्रकारों ने पता नहीं कि वे किस प्रकार का काम करते हैं, एक ऐसा चित्र छाप दिया जो कि आज से काफी साल पहले का एक मृत महाशय का हैं। मैं इस बात को खासकर इसलिए लाया हूं। कि यह बड़ा अप–शकुन हैं। स्पीकर साहब यहां बैंठे नहीं हैं, मैं आपकी मार्फत उनसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई यज्ञ हवन कराना चाहिए।

चेयरमैन महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सारे हरियाणा की तरक्की का बड़ा स्पष्ट चित्र हाउस के सामने रखा हैं और जो वास्तविकता थी, जिन चीजों की जरूरत थी,

असलियत में सारी बातें रखी हैं। खासकर देश के गौरव तथा सम्मान के लिए जो हमारी फौज ने काम किया हैं और जिसके कारण हमारा सिर ऊंचा हुआ हैं, उसका वर्णन भी राज्यपाल महोदय ने किया हैं। हमारे वीर सैनिक जिन्होंनें अपनी देश की उन्नति के लिए, अपने देश के गौरव के लिये, बलिदान दिया, जो बड़ा काम उन्होनें किया, उसके लिये हम उन्हें हार्दिक बधाई पेश करते हैं। अभी–अभी हमारे बुजुर्ग चौधरी रिजक राम जी ने खासकर बिजली के बारे में , काफी टीका टिप्पणी की हैं। मैं समझता हूं कि वह आई0 पी0 एम0 रहें हैं। जब वह आई0 पी0 एम0 थे, उस समय की पुरानी गाथा की एक बड़ी लम्बी चौड़ी पुस्तक उन्होंनें पढ़कर सुनाई। असल बात तो यह हैं कि हरियाणा में बिजली की कमी की जितनी चर्चा थी, उसको पूरा करने केल लिए बोर्ड ने अनथक प्रयास किया हैं, मेहनत की हैं, जिसके कारण गांव–गांव में बिजली पहुंची हैं। दरअसल जो असलीयत हैं वह यह हैं कि अगर कहीं कोई कमी है या कोई टैक्नीकल कमी हैं, वह तो हम बोर्ड के सामने ला सकते हैं लेकिन यह कहना बिजली की बहुत शार्टेज हैं, यह बात नहीं हैं। अभी–अभी यहां पर पावर स्टेशन लगे हैं जो 440 के वी की लाईन हैं, रात के वक्त, वहां पर 460 के0 वी0 तक वोल्टेज हो जाती हैं। अभी मेरे बुजुर्ग दोस्त ने बिजली की कमी के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि बोर्ड के अन्दर जो इन्जीनियर्ज हैं वे बहुत अच्छा काम रहे हैं । अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रहती होगी तो उसे वे जल्द दूर करेंगें। एक बात सुझाव के तौर पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि

कुछक जगहों पर जमींदार लोग बिजली का प्रयोग ठीका तरह से नहीं कर सकते, वहां पर सरकार को चाहिए कि कोई न कोई इन्डस्ट्रीज लगांए क्योंकि ऐसे कई इलाके हैं, जहां पर बिजली का सही फायदा नहीं उठाया जा सकता करनाल सोनीपत का इलाका, जिसके पास के चौधरी रिजक राम जी निवासी हैं, वहां पर कृषि का काफी विस्तार हुआ हैं, वहां बढ़िया बीजों के साथ–साथ बढिया सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई हैं।

चेयरमैन साहब, रोहतक जिला और खासकर हिसार और महेन्द्रगढ़ जहां पर जमींदार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा दस्तकारी लगाकर जमींदारो केा फायदा पहुंचाया जाए। बिजली के बारे में कहना कि थर्मल प्लांट नहीं हैं, असल बात तो यह हैं कि बिजली गांव–गांव में पहुची हैं और ठीक चल रही हैं। जो पावर स्टेशन बने हैं, वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लैन्ड–रिफार्मज की बात जोकि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं उस में तो हो सकता था कि मेरे बुजुर्ग दोस्त यह कहते बने हैं, कि जमीन पर सीलिंग का ध्यान रखा जाए बजाये यह कहने के कि किसानों में लड़ाई होगी, हरिजनों को नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं हैं। कुछ बड़े–बड़े जमींदार खासकर सन्त, महात्मा और साधू लोग जिनके पास हजारों एकड़ की भूमि हैं उन पर सीलिंग हो सकती हैं लेकिन जिस किसान के पास थोड़ी सी भूमि हैं और उस पर वह खुद काश्त करता हैं तो उसकी सीलिंग का ध्यान रखा जाएगा। कुछ एक बात मैं आपके

द्वारा हाउस के सामने लाना चाहता हूं जो कि किसान से ताल्लूक रखती हैं, किसानो को बैंकों के जरिये लोन लेने की बड़ी दिक्कत होती हैं। जब कभी किसान को पैसे की जरूरत होती हैं जैसे बिजाई के समय अच्छी खाद लेने के लिए, अच्छे बीज खरीदन के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए, इन सब बातों के देखते हुए अगर बैंकों के जरिये उसके लोन की कोई लिमिट मुकर्रर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी ताकि जमींदार को कर्जा लेने में और कृषि के उत्पादन बढ़ाने में सुविधा हो। भूमि की सीलिंग की चर्चा भी आज कल चल रही हैं। सरकार के पास जो सर–प्लस भूमि हो, उसमें–से दो तीन किल्ले गरीब हरिजनों को भूमि दी जाए तो यह एक अन–एकानमीकल होलडिंगज होगी इससे तो आदमी घर से बेघर हो जाता हैं। उन्हें कम से कम 10 एकड़ जमीन दी जाए जिससे कि वे अपने बाल बच्चों का गुजारा कर सकें। सरकार का काम किसी किसान को नुकसान पंहुचाना नहीं होता हैं यह तो सेन्ट्रेल गवर्नमैंट की पालिसी हैं, और इसके साथ हम सहमत हैं। पर यह कहना कि इससे गरीब किसानों में, हरिजनों में लड़ाई होगी, किसानो को नुकसान पंहुचेगा गल्त हैं। चेयरमैंन साहब, आगे चल कर मैं नहरों पानी के मुताल्लिक भी कुछ बातें कहना चाहता हूं। बदकिस्मती की बात तो यह हैं कि हमारे हरियाणा में एक ही नदी हैं, यमुना नदि। इसके अलावा कुछक छोटी–छोटी नदिंया और पड़ती हैं। सरकार सोचती हैं कि हरियाणा में पानी की काफी किल्लत हैं, इसको कैसे पूरा किया जाए फिर भी ये कहते हैं कि मुफ्त पैसा लगा रहें हैं, नहरें बना रहें हैं। इनके ऐसा

कहने में कोई वास्तविकता नहीं हैं। बिजली के जरिये जो ट्यूबवैल लगे हैं, उनके कारण अनाज में इतनी वृद्धि हुई हैं जिसे सरकार को संभालना भी मुशकिल हो रहा हैं। यहां पर लोहारू कैनाल का भी जिक्र किया गया। नहरों के जरिये हरियाणा को बड़ा फायदा हुआ हैं, राई और रसोई जैसे इलाके हैं, जो कि फल्ड के पानी से डूबे रहते थे, सरकार ने उस पानी अच्छी तरह से कन्ट्रोल किया हैं और सरकार उस पानी का अब अच्छे ढंग से प्रयोग करती हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना हैं कि अगर सरकार पानी की व्यस्था और ठीक ढंग से कर दे तो देश में अनाज के उत्पादन में और वृद्धि हो सकती हैं। कृषि के मुताल्लिक भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सकेंत किया कि बीजों में सुधार हुआ हैं और खासकर जो आलू की फसल हैं, उसकी एक वैरायटी को बाजार में लाया गया हैं, जिस में काफी वृद्धि हुई हैं, और हरियाणा ने उस में कमाल कर दिखाया हैं। जहां तक गेहूं का ताल्लुक हैं और दूसरी फसलों का ताल्लूक हैं उनका भी बहुत विकास हुआ हैं। इंडस्ट्रीज के म ुताल्लिक मैंने अभी भी अर्ज किया था कि उन गांव के अन्दर जहां बिजली के अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सका वहां पर इंडस्ट्रीज लगाई जाये। ये जो बातें मैंने कहीं ये वास्तविकता को जाहिर करती हैं। विरोधी दल ने तो विरोध करना ही हैं चाहे अच्छे काम हुए हों तब भी अगर अच्छा काम न हुआ हो तब तो करना ही हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण बहुत सून्दर था जो उन्होनें यहां पर पढ़ा। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री के0 एन0 गुलाटी (फरीदाबाद): माननीय चेयरमैन साहब, माननीय गवर्नर साहब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो एड्रैस यहां पेश किया मैं यह समझता हूं कि वह सारा एड्रैस उनको लिखकर दिया गया था और उन्होंनें उसको यहां पढ़ दिया। मैं यह समझता हूं कि इस एड्रैस से हरियाणा की आम जनता की एक फीसदी भी तसल्ली नहीं हुई हैं। मैं उन सब बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनके लिये मिडल क्लास परेशान हैं। मैं चाहूंगा कि जो बातें मैंने अमैंडमेट के जरिए यहां रखी हैं अगर गवर्नर साहब के एड्रैस में होती तो जनता की तसल्ली हो जाती। सबसे पहले मैं यह निवेदन करूगा कि हरियाणा के अन्दर जो दो किस्म के टैक्स हैं प्रापर्टी टैक्स और हाउस टैक्स ये दोनों एक ही चीज हैं और एक ही तरह से इनकी असैस्मेंट होती है। क्या ही अच्छा होता अगर एड्रैस में यह चीज होती कि इन दोनों टैक्सों को मिलाकर एक ही टैक्स लगाया जायेगा और सही तरीके से इनकी रिकवरी की जायेगी।

जो प्रोफैशनल टैक्स हैं यह बड़ी भारी लानत हैं इसको खत्म करना चाहिए।

नम्बर तीन सेल्ज टैक्स को एक्साइज ड्यूटी में बदलनाः सेल्ज टैक्स सारी जनता और कस्टमर्ज के लिये एक बड़ी भारी लानत हैं। पिछली दफा हरियाणा के दुकानदारों ने बहुत थोड़ी संख्या में टैक्स जमा कराये लेकिन उस पर भी सरकार की तसल्ली नहीं हुई इसका कारण यह हैं कि हर मामले में पालिटिक्स

चलती हैं। दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर यमुना नगर में बहुत भारी एजीटेशन हुई। खुद सरकार ने बोगस फर्मो को रजिस्टर कया और सालों भर वे बोगस फर्मे चलती रहीं लेकिन कुछ सालो के बाद फिर दुकानदारों को नोटिस देकर लाखोंरूपये जमा करवाये गये। मैं कहता हूं कि जैंसे कपड़ा , अनाज चीनी पर एक्साइज ड्यूटी है उसी तरह से सेल्ज टैक्स को खत्म करके एक्साइज ड्यूटी में तब्दील किया जाये।

पवा्यट नम्बर चार, रिकमैंडशन आफ एम्पालाइज वेज बोर्ड के बारे में हैं हमारे एक साथी ने कहा कि गरीबी हटाई जाएगी। मैं उनसे पूछता हूं कि गरीबी कैसे हटेगी। हमारे यहां ज्यादातर तो मजदूर हैं जिनकी हालत बहुत खराब हैं। मजदूर ही एक ऐसा आदमी हैं जो एक पैसे का सौरूपये बनाता हैं लेकिन उसके लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया हैं। उनकी गरीबी कैसे हटेगी ? इंजीनियरिंग वेज बोर्ड की रिक–मैंडेशन आज तक लागू नहीं की गई हैं लेबर बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं करता। किसी भी मजदूर को गरैच्यूटी नहीं मिलती हैं। इ0 एस0 आई0 की स्कीम खोली गई हैं। मजदूरों से पैसे लेकर तो जमा कर लिये जाते हैं लेकिन उनको दवाई नहीं मिलती हैं।

मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा के एम्पलाई भी हिन्दुस्तानी के शहरी हैं। सैण्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से उसके एम्पालाइज को भी पे–स्केल या इंटैरिम रिलीफ मिलता हैं वह हरियाणा एम्पालज को भी मिलना चाहिए। सरकारी

मुलाजमों में जो करप्शन आती हैं वह इसी वजह से आती हैं कि उनको ठीक भत्ते नहीं मिलते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर हरियाणा के एम्पालाइज को भी सैण्ट्रल गवर्नमैंट के पे–स्केल और इंटरिम रिलीफ मिल जाये तो यह कुरप्शन हट जायेगी।

सरकार ने अपने मुलाजिमों और टीचरों को उनके घरों से बहुत दूर लगाया हुआ हैं सरकार से मेरी प्रार्थना हैं कि उनको घरों के नजदीक लगाया जाये ताकि वे अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकें।

अगला प्वांयट मेरा यह हैं कि जमींदारो की जमीनो को एक्वायर करके जो उनको कम्पैनसेशन दिया जाता हैं वह बहुत थोड़ी हैं। जमीनें दो–तीनरूपये गज कि हिसाब से एक्वायर कर ली जाती हैं और फिर उस जमीन की डिवैल्पमेंट पर भी तीन–चाररूपये गज खर्च आता हैं लेकिन उस जमीन को बेचा जाता हैं तीस–पैंतीसरूपये के हिसाब से। मैं चाहूंगा कि डिवैल्पमेंट का खर्चा लगाकर ठीक तरह से हिसाब करके जमींदारों को उनकी जमीनों की सही कीमत दी जाये। अगर सही कीमत नहीं देनी हैं तो उनकी जमीनें एक्वायर न की जायें।

शराब बन्दी पर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया। जो हकूमत आज हमारे भाई चला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ महात्मा गांधी जी का ही

हैं। महाम्मा गांधी जी की इच्छा थी कि शराबबन्दी हो लेकिन आज हमारी सरकार का काम शराब के रेवेन्यू से ही चलता है। आज जगह–जगह शराब बेचने और पीने की खुली छूट हैं। बस स्टैण्ड पर चलें जायें वहां शराब का अड्डा होगा, किसी स्कूल को देख लें उसके पास शराब का अड्डा होगा कहने का मतलब हैं कि हर जगह शराब के अड्डे आपको मिलेंगे। हमने भी आजादी के लिये आन्दोलन में हिस्सा लिया, हमने भी लाठियां खाई, महात्मा गांधी के हम भी फालोअर हैं और यह सरकार भी महात्मा गांधी के नाम पर चल रही हैं। इसलिये मैं चाहूगा कि सरकार को सबसे पहले शराब बन्दी करनी चाहिए।

इसके बाद चेयरमैन साहब, मैं आपका ध्यान फरीदाबाद टाउनशिप की तरफ दिलाना चाहता हूं। फरीदाबाद हरियाणा का one ot the important हैं। करोंड़ोरूपये का रेवैन्यू वहां से आता हैं, करोंड़ोंरूपये का बिजनैस इस टाउन के थ्रु होता हैं लेकिन इस चीज को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता हैं कि इस टाउन को आज कुछ नहीं मिला हैं सिवाये दो–चार इंडस्ट्रीज के चेयरमैन साहब, आप हैरार होंगे कि वहां कि जनता पानी के लिये तड़प रही हैं, वहां पर सेनीटेशन की हालत इतनी खराब है जिसकी वजह से वहां मच्छर बहुत ज्यादा हैं मैं गवर्नर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब को दावत देता हूं कि वे किसी रैस्ट हाउस वगैरह में न जाकर किसी के मकान में एक दिन रह कर देंखें तो उनको मां–नानी याद आ जायेगी कि कितने मच्छर काटते हैं। इसी

टाउनशिप में जब ए0 आई0 सी0 सी0 का सैशन लगता हैं तो पानी 24 घंटे मिलता हैं और मच्छर भी दूर हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि उसी प्रकार से फरीदाबाद की पानी और सैनीटेशन को ये प्रोबलम्बज को हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाये। स्पीकर साहब फरीदाबाद में सब से बड़ा हस्पताल बी0 के0 हस्पताल हैं लेकिन वहां पर मामूली से मामूली दवाई नहीं मिलती हैं। अगर कोई पोस्ट–मार्टम आना होना हो तो 24–24 घंटे नहीं किया जाता इसके विपरीत अगर किसी बड़े आदमी की सिफारिश नहीं आती हैं उतनी देर तक पोस्ट–मार्टम नहीं होता हैं। वहां पर अगर कोई बीमार मजदूर चला जाता हैंतो उसको एण्टर नहीं किया जाता इसके विपरीत अगर किसी बड़े आदमी का बीमार चला जाये तो उसको अच्छी सके अच्छी दवाई मिलेगी। मैं चाहूंगा कि इन खराबियों के लिये जो सुपरिनटैंडेंट अकाउंटैंट और स्टोर–कीपर वगैरह जिम्मेदार हैं उन के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाये। जिस आदमी की तनख्वाह 150रूपये महीना तक ही हैं हस्पतालों में उनका फ्री–ट्रीटमेंट होता हैं। यह फैसेलिटी पिछले कई सालों से चली आ रहीं हैं। आज जब कि इतनी महंगाई हो गई हैं तो 150रूपये एक मामूली इन्सान को मिल जाते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर आप सही मायनों में समाजवाद लाना चाहते हैं तो पांच सौरूपये माहवर आमदनी तक फ्री ट्रीटमैंट और फरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आज फरीदाबाद के अन्दर हजारों की तादाद में झुग्गी–झोपड़िया वाले मजदूर रहते हैं लेकिन उनके लिये लेवर कालोनी नहीं बनाई गई हैं। बडखल झील पर

लाखोंरूपया खर्च किया जाता हैं। वहां पर पार्टियां और पिकनिक के लिये लोग आते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही आफिस हैं लेकिन फिर भी लाखोंरूपया उस पर खर्च हो रहा हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पिकनिक और पार्टियों के लिये लाखोंरूपया खर्च हो सकते हैं तो लेबर कालोनी बनाने के लिए क्यों नहीं खर्च हो सकते ? इस वक्त इस टाउन में 50रूपये में एक कमरा किराये पर मिलता हैं। जिस आदमी की तनख्वाह 150रूपये महीना हो तो वह 50रूपये मकान का किराया देकर कैसे बरबाद हो सकता हैं। मेरा सरकार से फिर अनुरोध हैं कि आप क्लब की जो जगह पड़ी हैं वहां पर कालोनी बनाई जाये।

मैं अपनी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि फरीदाबाद में जो गाफ क्लब की जमीन हैं वहां पर लेबर कालोनी बननी चाहिए और वहां पर 50/50 गज के पलाट बना कर उन के ऊपर मकान बना कर मजदूरों को दे दिए जाएं ताकि वे गरीब लोग आबाद हो सकें। अगर आप ने गरीबी हटानी हैं और सही मायनों में आप गरीबी हटाना चाहते हैं तो आप को नो कंट्रोल और न होडिंग की पालिसी एडाप्ट करनी चाहिए। यह बात ठीक नहीं हैं कि जब आप चाहें कंट्रोल कर दें और जब आप चाहें खोल दें। आज आप ने चीनी का कंट्रोल किया हुआ हैं, कंट्रोल पर तो चीनी दोरूपये के हिसाब से फी किलो मिलती हैं और जो खुली बिकती हैं वह 3.50रूपये के हिसाब से बिकती हैं तो यह किस किस्म का कंट्रोल हुआ। अगर आप ने कंट्रोल करना हैं तो

फिर कंट्रोल रेट पर ही चीनी बिकनी चाहिए, आप बाजार में ज्यादा रेट चार्ज करने की क्यों इजाजत देते हैं ? इसी तरह कभी सीमेंट नदारद हो जाता हैं, कमी ईटें नदारद हो जाती हैं और ब्लैंक मार्किट में बिकती हैं। इस लिए यह जो पालिसी हैं यह ठीक नहीं हैं। सरकार को नो– कंट्रोल और नो–होडिंग की पालिसी पर स्ट्रिक्टली अमल करना चाहिएं। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने स्टेट में देहातो को बिजली दी हैं लेकिन मेरे हल्के में एक मांगर गांव हैं जहां परकि 600 के करीब घर हैं, वहां पर सिर्फ बिजली का एक खम्बा गाड़ रखा हैं और लोगो को महीनें में चंन्द दिन बिजली मिलती हैं और बाकी सारा महीना अन्धेरे में रहना पड़ता हैं और जो बिजली घर हैं वह भी वहां से बहुत दूरी पर हैं। मैं निवेदना कंरूगा कि सरकार को लोगों की इस तकलीफ को दूर करना चाहिए।

फरीदाबाद टाउनशिप के साथ गांधी नगर के नामों कालोनीज बनी हैं। देवताओं के नाम से यह कालोनीज बसाई गई हैं लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं दी जा रही। पहले यह बहाना लगाया जाता था कि वहां पर म्यूनिसिपैलिटी नहीं हैं इसलिए नहीं दी सकती। अब वहां पर कम्पलैक्स भी बना दिया गया हैं लेकिन फिर भी अब यह कहना शुरू कर दिया हैं कि 12 हजाररूपये जमा करवाओं मैं कहता हूं कि क्या यह गरीबी हटाने की बातें हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता हैं कि आज डैमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा हैं। मेरे भाईरूलिंग पार्टी

वाले नराज न हों तो मैं एक बात कहू। आज सरकार ने यह नीति अख्तियार कर रखी हैं कि जोरूलिंग पार्टी के साथ मिलता हैं उसका तो काम कर दिया जाता हैं और जो नहीं मिलता उसका काम नहीं होतां। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं हैं क्योंकि हम जो अपोजीशन वाले हैं इसलिए हमारे ऊपर दिमागों पर यह बोझ नहीं डाला जाना चाहिए कि हमारे काम तब किए जाएगें अगर हमरूलिंग पार्टी के साथ शामिल होंगे। यह हमारी मर्जी हैं हम जहां चाहे बैठे। इसलिए ऐसा मतभेद नहीं होना चाहिए।

इसके इलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मारकिट कमेटियां, कम्पलैक्स, कोआपरेटिव बैंक और इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट हैं उन में नामजदगियां नहीं होनी चाहिए , क्योंकि अपने आदमियों की नमाजदगी कर दी जाती हैं और फिर 10/10 साल तक इलैक्शन नहीं करवाए जाते। सरकार को चाहिए कि ऐसे अदारों में बाकायदा इलैक्शन करवांए ताकि लोगों के सही नुमायंदे इलैक्ट हो कर उनकी रहनुमाई कर सकें। मेरे हल्के में एक बडकल गांव हैं वहां पर लोग चाहते हैं कि सड़क सही तरीके से बने लेकिन पालिटिक्स की वजह से उस को खेतों से ले जाते हैं। इसी तरह एक पाली गांव की सड़के हैं, छः साल हो गए हैं वहां पर पत्थर पड़े हुए हैं और लोगों के रोज साईकल पंक्चर होते हैं लेकिन उस सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा हैं। अब आप बतांए कि गरीबी कैसे दूर हो सकती हैं। अंत में मैं आप की

मारफत सरकार से यह निवेदन करूगा कि अगर आप सही मायनो में गरीबी दूर करना चाहते हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं तो मेरी जो अमैंडमेंट हैं उनको मान कर ऐड्रैस में शामिल किया जाए। मैं इतना कह कर आपका धन्यवाद करता हूं।

कामरेड राम किशन आजाद (जुंडला, एस0 सी0): स्पीकर साहिब, गवर्नर साहिब ने अपने एड्रैस में हरियाणा की तरक्की का जो जिक्र किया हैं उस का सेहरा हमारे चीफ मिनिस्टर श्री बंसी लाल के सिर पर हैं क्योंकि उनहोंनें दिन रात मेहनत करके हरियाणा की तरक्की की हैं। मैं इस लिए उनको बहुत–बहुत बधाई देता हूं। स्पीकर साहब, हरियाणा देश के दूसरे प्रान्तों से पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ अभी पिछले दिनों जो लड़ाई हुई उसमे देश की रक्षा करने के लिये हमारे सूबे के नौजवानों ने बड़ी कुरबानियां दी जिससे कि हरियाणा का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा।

हमारे गवर्नर साहिब ने अपने अभिभाषण में हरियाणा का जो नक्शा पेश किया हैं उस में हरिजनों का कोई खास जिक्र नहीं किया। मुझे मालूम हुआ हैं कि पहले एड्रैस में उन्होनें इस के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एड्रैस में भी उनको जिक्र करना चाहिए था। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहिब का ध्यान हरिजनों की डिवैल्पमैंट की तरफ दिलाना चाहता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक हरिजनों की तरक्की के लिए जो स्कीमें बनती रही हैं उनका केवल हरिजनोंके एक ही

फिरके को फायदा पंहुचता रहा हैं जिस का नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के जो बाकी वर्ग हैं वह पिछड़े ही बैंठे हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि अब की बार हरिजनों के लिए जो स्कीमें बनाई जाएं उसमे एक बात का ख्याल रखा जाए कि सब हरिजनों को बराबर फायदा पहुचें। सन् 1952 से लेकर आज तक सिर्फ हरिजनों के एक ही फिरके ने फायदा उठाया हैं, मैं इस की ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात का खास ख्याल रखें। हमारी हरियाणा सरकार इसलिए बधाई की पात्र हैं कि हिन्दोस्तान में यह पहला सूबा हैं जिस ने सफाई मजदूरों की बेहतरी के लिए कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जांच पड़ताल करके सरकार को उनकी बेहतरी के लिए रिपोर्ट दी हैं। इस का जहां सेहरा श्री बंसी लाल के सिर पर हैं वहां मुझे यह कहने से भी गुरेज नहीं हैं कि चौधरी खुरशीद अहमद ने भी जो कि उस वक्त मिनिस्टर थे इसमें बहुत पार्ट प्ले किया था, उनका उस कमेटी के बनाने में बहुत बड़ा हाथ था, हम उन के भी शुक्रगुजार हैं। मैं आप के द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सफाई मजदूरों के लिए जो उस कमेटी ने रिर्पाट दी हैं सरकार का उसे जल्दी लागू करना चाहिए। लैंड रिफार्मज के बारे में भी गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में जोर दिया हैं। इससे पहले जितने भी कानून थे वह कमजोर थे जिस की वजह से हरिजनों और किसानों की आपस में काफी लड़ाई होती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अब जो कानून बनाएगी उसमें उस किस्म की कमी नही रहने देगी ताकि किसान और मजदूर आपस

में मिलकर रहेंगें। अभी–अभी एक मैंम्बर हाउस में बोल रहे थें और उन्होंनें एक बैलट पेपर हाउस में दिखाया था। मैं कहता हूं कि इस बात की तहकीकात करवाई की जाए कि उनके पास यह बैलट पेपर कैसे आया और कैसे उस की चोरी हुई, सरकार की बदनामी के लिए जो गलतफहमी यहां पर पैदा हुई हैं वह दूर होनी चाहिए। इन अलफाज के साथ मैं गवर्नर साहिब के भाषण के लिए जो शुक्रिया का प्रस्ताव पेश हुआ हैं उसकी ताईद करता हूं।

चौधरी शिव राम वर्मा(नीलोखेड़ी): माननीय चेयरमैन साहिब आज माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही हैं और बहुत से सज्जनों ने उस के बारे में काफी विस्तार से कहा हैं, मैं उनकी बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मैं कुछ न कुछ बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे राज्यपाल महोदय का तो यह भाषण नाम मात्र हैं, सरकार की नीति इस में होती हैं जो सरकार ने उनको लिख कर दे दी और उन्होंनें यहां पर उस को पढ़ दिया। लेकिन उस के अन्दर भी कई बातें इस ढंग से कही गई हैं जिन के कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं निकलते और सरकार जैसे चाहेगी उनको मोढ़ सकती हैं। यहां पर भूमि सुधार की बातें कही गई हैं। इस के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लैंड रिफार्मज का सरकार केवल एक ही अर्थ लेती हैं और वह यह हैं कि लैंड सीलिंग कम की जाए और वह समझती हैं कि उस से भूमि सुधार हो जाएगा। यह चीज कई बार सरकार देख चुकी हैं लेकिन अभी तक इस संबन्ध में कोई सुधार

होता दिखाई नहीं देता। हां एक बात में सरकार जरूर कामयाब हुई हैं और वह हैं लोगों को बहकाने मे और सरकार ने हर गांव में दो घड़े बना कर रख दिए हैं। केवल भूमि के नाम पर हरिजनों में लालसा पैदा कर दी कि हम आप को भूमि देंगे और उधर जमींदारों के दिलों में उन के प्रति सन्देह पैदा कर दिया। हमारे हरियाणा के अन्दर वह जमींदार तो नहीं जो हिन्दोस्तान के दूसरे हिस्सों में जमीदार कहलाते हैं। यहां पर दो बीघे का मालिक भी जमींदार कहलाता हैं जो लोग पुशतैनी खेती करते आ रहे हैं उनके मन में इन्होंनें भय पैदा कर दिया हैं और वह सोचते हैं पता नहीं उनकी जमीन रहेगी या नहीं। दूसरी तरफ दूसरे लोगों में लालच पैदा कर दिया हैं लालसा जगा दी हैं कि उनको जमीन दी जायेगी। इस तरह करके गांव मे दो धड़े पैदा कर दिये और उन में कशमकश पैदा कर दी हैं। इससे साफ जाहिर होता हैं कि सरकार के मन में देश की भलाई नहीं हैं बल्कि इनके मन में यह हैं कि अगर गांव में दो धड़े होंगे तो एक धड़ा तो इनको वोट देता ही रहेगा। इसी नीयत से यह लोगों को बहका रहे हैं और 25 साल से बराबर यही प्रचार चल रहा हैं कि भूमि सुधार लायेंगे और भूमिहीनों को जमीन देगे लेकिन मेरी समझ में यह नही आता कि यह किस प्रकार का सुधार करना चाहते हैं कि जो पुशतैंनी किसान हैं जिन्होंनें ने देश के अनाज संकट को दूर किया हैं उनके मन में भय पैदा किया जा रहा हैं कि उनकी जमीन उनके पास नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति गलत हैं कि एक बार भूमि की सीमा निर्धारित हो जाने के बाद उसे

बार–बार प्रचार का साधन बनाया जाये। इससे देश को नुकसान होगा और पैदावर कम होगी। अगर अब फिर आप लैंड सीलिंग कम करेंगें तो इससे देश का भला नहीं होगा और किसान के मन में बेचैनी पैदा होगी जिससे देश में जो पैदावार बढ़ रही हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह अस्थिरता खत्म करतनी चाहिये और इस मामला को बार–बार छेड़ना देश के हित में नही हैं। एक बात को हम भूल जाते हैं कि जमीन पहली ही छोटे–छोटे टुकड़ो में बटती जा रही हैं कि लोगों को खेती करना मुश्किल हो रहा हैं। कितने लोग हैं जिनके पास इकनामिक यूनिट जमीन का बनता हैं जिससे वे अपने परिवार का गुजरा कर सकें अच्छे मकान में रह सके, अच्छे कपड़े पहन सकें, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकें और अच्छे रहन सहन से रह सकें ? मैं कहता हूं कि बहुत कम होंगें वह नहीं के बराबर हैं। किसान का तो पहले ही गुजारा नहीं चल रहा हैं। जमीन को आगे बटने से रोका जाना चाहिए और जमीन का बटवारा करने के लिए के लिए हमने जो गलतियां हम ने पहले की हुई हैं उनको सुधरना चाहिए न की गलती करनी चाहिए। पहले तो लड़को में ही जमीन तो लड़को में ही जमीन बटती थी और इस तरह जमीन के टुकड़े होते थे लेकिन इन्होंनें जो कानून बनाया हैं उससे अब जमीन लड़के–लड़की दोंनों में बटती हैं। अब तो जमीन की हालत यह हो गई हैं कि कई लोग तो आपको एक एकड़ के मालिक भी नहीं मिलेगें। एक तरफ तो यह हाल हो रहा हैं दूसरी तरफ दूसरे लोगों में जिनका खेती पुशतैनी काम नहीं हैं जमीन की लालसा

लगाई जाती हैं। इससे देश का भला नहीं होगा। जिन लोगों का खेती करना पुशतैनी काम हैं और जो लोग सिवाये खेती के दूसरा काम नही जानते हैं उनके पास इकनामिक यूनिट जमीन का नहीं रहा हैं और उनके सामने जमीन का सवाल हैं लेकिन अब उनके पास एक और सवाल पैदा किया जा रहा हैं और उनमें भय पैदा किया जा रहा हैं कि उनके पास जमीन रहेगी या नहीं रहेगीं। यह पालीसी बहुत खतरनाक देश के लिये साबित होगीं सरकार को जमीन के इकनामिक यूनिट बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए था लेकिन यहां पर तो जमीन को और बिखेरने की तरफ ध्यान दिया जा रहा हैं ताकि लोगों के पास जमीन का इकानमिक यूनिट न रहें क्योंकि अगर सभी लोगों का अर्थिक तौर पर कमजोर कर देंगे तो उनके पास सरकार के आगे हाथ जोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह करने से देश की भलाई नहीं होगी सरकार का इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो लोग पुशतैनी खेती करते हैं कम से कम उनके पास इकनामिक यूनिट तो रहें और यह जो लड़के और लड़की में डबल बंटवारा जमीन का हो रहा हैं इसे बंद किया जाये। लड़की को बजाये पिता की जायदाद के पति के जायदाद में हिस्सा दिया जाये ताकि जमीन का बंटवारारूके। जिनके पास जमीन नहीं हैं या थोड़ी हैं उनमें बजाये जमीन की लालसा पैदा करने के यह बेहतर होगा कि उनको और काम दिया जाये और उनके लिये लघु उद्ययोग कायम किये जायें। सरकार उनके लिये शिक्षा का प्रबंध करे, उनकी ट्रेनिग का इन्तजाम करे और उनके

लिये पैसे का इन्तजाम करे जिससे वे लघु उद्योग लगा सके। सरकार नारे लगा रही हैं कि वह गरीबी दूर करेगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वह कैसे गरीबी दूर करेगी। पिछले दिनों कहा जाता था कि यह जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हैं इन से गरीबों को पैसा मिलेगां। मेरे पास लोग आते हैं कि हमें पैसा दिलाओ हम काम करना चाहते हैं और मैं भी कोशिश करता हूं लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता हैं। उनको कहा जाता हैं कि आप किसी जमानतदार मिलता नहीं हैं और अगर मिल जाए तो मैं पूछता हूं कि क्या उनके पास उसके पास रहने देगा। मैं कहता हूं कि सरकार अपनी जमानत पर लोगों को पैसा दें। मेरे अपने गांव में कुछ गैर आबाद अनुसूचित जातियां के लोग रहते हैं जो छाज बनाने का काम करते हैं। यह छाज सरकंडो के बनते हैं और अनाज बरसाने के काम आते हैं वे लोग अच्छे दस्तकार हैं और हजारों की तादाद में छाज बनाते हैं। लेकिन उनके पास काम चलाने का पैसा नहीं हैं। यह जो हरिजन कल्याण बोर्ड बना हैं मैंने कोशिश की कि उस से उनको पैसा मिल सके ताकि वे अपनी दस्तकारी चला कर अपना गुजरा कर सकें लेकिन वहां तो सवाल गंदम जवाब चना मिलता हैं। अगर वे लोग किसी साहूकार से पैसा लेते हैं तो सूद का रेट 75 प्रतिशत तक हैं और सौं में से अगर 75रू0 वे उसे दे दें तो उनके पास क्या बचेगा खाने के लिये । वहां से जवाब मिलता हैं कि डेरी फार्म खोलो उस के लिए कर्ज मिलेगा। कितनी हैरानी की बात हैं कि उन लोगों के पास रहने के लिए तो मकान नहीं चीथडों के तम्बू बना कर या सरकंडे की

सिरकियों में तो वे रहते हैं भैंसे कहां पर बाधगें। जो काम वे पुशतैनी करते आ रहे हैं उनके लिए तो उनको पैसा नहीं देते कहते हैं डेरी फार्म खोलो तो कर्ज देंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो लोग पुशतैनी दस्तकार हैं अच्छा काम करते हैं उनके लिए पैसे का प्रबन्ध किया जाये ताकि वे अपना गुजारा कर सके। लोगों में जमीन की लालसा पैदा करने बजाये उन्हें उनका पुशतैनी काम चलाने में मदद दी जाये। अगर ऐसा न किया गया और इसी तरह से जमीन के नाम पर धडेबंदी पैदा की गई तो एक आध बार तो शायद कांग्रेस को वोट मिल जाये लेकिन उसके बाद देश में पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैंने जमीन के बारे में कही हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और ऐसा करने में ही देश की भलाई हैं।

गवर्नर साहब ने अपने एड्रैस में पुलिस का भी जिकर किया हैं ओर कहा हैं कि पुलिस का अब अच्छा प्रबन्ध हैं और पुलिस लोगों में भय नहीं रहा हैं। इस बारे में मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं। अभी 15 दिन की बात हैं थाना बुटाना में सौखड़ा गांव का एक हरिजन पंच हैं। उसने पिछले सरपंच के हक में सरपंच बनने के लिए वोट नहीं दिया और उसकी बजाये कोई दूसरा सरपंच बन गया। उस सरपंच ने जो पहले था एक साथी को लेकर सरेबाजार तरावड़ी मंडी में उस हरिजन पंच को पीटा। वह थाने में गया और थानेदार ने कहा कि मैं कार्यवाही करूगा और रपट लिख ली लकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। वह

ही डी0 एस0 पी0 के पास गया और उसके सामने थानेदार ने कहा कि कार्यवाही करूंगा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई हैं। गरीब की तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती लेकिन यहां कहा जाता हैं कि पुलिस का काम बहुत अच्छा हैं। जो तगड़े आदमी हैं वे तो पुलिस को भी डरा लेंगें लेकिन जो गरीब हैं उन की तो थाने में जाने की जुर्रत नहीं हैं तगड़े आदमियों के साथ तो पुलिस अच्छा सलूक करती हैं लेकिन गरीबों को दबाकर रखती हैं। मैं समझता हूं कि पुलिस का भय जो अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा हैं उससे ज्यादा अब भी चल रहा हैं। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर कहा गया हैं कि सिचांई के साधन बढ़ाए जाए जा रहे हैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं। जिला करनाल में अच्छी खेती हो रही हैं और वह पैदावर में हरियाणा में लीड कर रहा हैं लेकिन वहां नहरों में पानी कम कर दिया गया हैं और अब एक चौथाई सिंचाई भी नहीं हो रही हैं। मोधे ऊंचे कर दिये गये हैं और इस तरह पानी आगे ले जाया जा रहा है।

6.00 P.M

नहर के पानी की कमी को पूरा करने के लिए सरकार किस तरह से अन्धाधुंध ट्यूबवैल्ज लगा रही हैं। ऊपर के पानी को खींचने के लिए किसानों ने अपने ट्यूबवैल्ज लगाये हैं और नीचे के पानी को खींचने के लिए सरकार ने बड़े–बड़े ट्यूबवैल्ज लगा कर पानी नहरों में डाला हैं। अब एक और नहर 50 मील लम्बी बन रही हैं जिसका जिक्र यहां हाउस में आया हैं, इस नहर को 15

करोड़रूपये की लागत से बनाया जा रहा हैं। इसके दोनो तरफ ट्यूबवैल्ज लगेगें। जो भाखड़ा नहर हैं उस के दोनों तरफ भी ट्यूबवैल्ज लगा रहें हैं। जब ट्यूबवैल्ज से पानी खिंचेगा तो पता नहीं नहर में पानी जाएगा भी या नहीं, करनाल जिला में किसानों के ट्यूबवैल्ज में पानी नहीं रहेगा क्योंकि पिछले साल लाडक के पास कई गांवों में, गर्मियों के दिनों में ट्यूबवैल्ज ने पानी देना बन्द कर दिया, सब ट्यूबवैल्ज ने पानी देना छोड़ गए, पानी ऊपर उठता ही नहीं था। पीने के पानी का भी यही हाल हैं। अगर गांवो का यही हाल रहा और ट्यूबवैल्ज चलने के दो घंटे बाद पानी बंद हो गया तो न जाने करनाल मैं भी पानी मिले या न मिले क्योंकि पानी का स्तर नीचे जा रहा हैं। सरकार बिना किसी सर्वे किये, बिना सोचे समझे ट्यूबवैल्ज लगाती जा रही हैं, यह नहीं देखती कि पानी का स्तर नीचे जा रहा हैं। मैंने इस बात का जिक्र करनाल में भी किया था जब प्लानिंग कमीशन की टीम आई थी। मैंने कहा था कि सरकार इस चीज का सर्वे करवाये तब ट्यूबवैल्ज लगाये। अगर इस तरह अन्धाधुंध ट्यूबवैल्ज लगाते रहे तो पांच दस सालों में, मुझे डर हैं कि यहां की जमीर बंजर न बन हो जाए। इस जिला करनाल में हिसार का नक्शा न खिच जाए। जिस तरह सरकार एक तरफ से गरीबी हटाने की तरफ सोच रही हैं, इधर से गरीबी हटाई और उधर डाल दी, उसी तरह से कहीं ऐसा न हो कि करनाल का पानी हिसार में डाल दें और पांच सात सालों में करनाल हिसार की तरह हो जाए जहां पानी मिलता । जो ट्यूबवैल्ज आप लगा रहे हैं, पांच सात सालों के बाद इनका

कोई फायदा नहीं होगां। अगर इसी तरह से अधांधुंध ट्यूबवैल्ज लगाये गये तो मुझे साफ दिखाई देता हैं कि यहां पानी सूख जाएगा, जमीन सूख जायेगी क्योंकि पानी का स्तर तेज रफ्तार से नीचे की तरफ जा रहा हैं और कुछ सालों के बाद कोई ट्यूबवैल्ज पानी नहीं उठाएगा। इस समय पानी की जो कठिनाई मुझे दिखाई देती हैं, चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस और विशेष तौर से खीचना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मैं किसान हूं और सिवाये खेती से मेरा और कोई रोजगार नहीं हैं। अगर कोई दूसरा धंधा होता तो मैं समझता हूं कि मैं अपना गुजरा कर सकता था, लेकिन खेती के सिवाये मेरा और कोई धंधा नहीं हैं। अगर पानी चला गया तो जिला करनाल के किसानों के लिए मौत से भी ज्यादा बुरी चीज होगी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसान को उचित मूल्य दिलाने की बात की हैं लेकिन उचित मूल्य दिलवाने का ढंग कुछ उलटा दिखाई देता हैं। कृषि मूल्य आयोग ने पिछले दिनों सिफारिश की हैं कि गेहूं का मूल्य 60रूपये प्रति क्विंटल होना चाहिए जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हर चीज 10 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत, कोई–कोई चीज के 100 प्रतिशत तक के मूल्य चढ़ चुके हैं। चेयरमैन साहब, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस और विशेष ध्यान दे। या तो किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलवाए या उसी अनुपात से बाजार की दूसरी चीजें सस्ती करें जिस अनुपात से गेहूं का भाव मुर्कर किया जाता हैं। आप देखें, खाद बहुत महंगा हो गया। खाद के लिये किसान की मांग पिछले

दस सालों से चली आ रही हैं। खाद का मूल्य कम होना चाहिए ताकि किसान खरीद सकें। इस साल खाद पर ड्यूटी लगने से खाद का मूल्य और चढ़ गया हैं और गेहूं का मूल्य नीचे करते जा रहें हैं। इस किस्म की पालिसी अख्तियार करने से किसान तो पिसेगा ही। अगर किसान मरेगा तो देश के लिए संकट का समय आ सकता हैं। किसान की कमर टूटेगी तो देश की कमर भी टूट जाएगी। आज किसान को सारी चींजे मंहगी मिलती हैं और पैदावार सस्ती बेचनी पड़ती हैं। इन हालात में किसान को कोई न कोई दूसरी बात देखनी पड़ेगी, दूसरे ढंग से चलना पड़ेगा। खेती का क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र हैं जिस में टैक्स लगने की गुंजाइश हैं। वे भाई जो इस विचार के हैं वे एक साल खुद खेती करें और एक साल करने के बाद फिर हिसाब किताब लगायें। हिसाब करने के बाद कहेंगें कि 100रूपये क्विंटल से कम गेहूं का भाव किसी तरह भी नहीं होना चाहिए। बल्कि इससे ज्यादा मूल्य लेना चाहेंगे। खेती में कितनी मेहनत करनी पड़ती हैं, इसका पता किसान को हैं, दूसरे भाइयों को नहीं जो बैठे–बैठें ही गेहूं का भाव निर्धारित कर देते हैं। किसान का न कोई संगठन हैं, न कोई यूनियन हैं, दूसरे सभी वर्गों की यूनियनें बनी हुई हैं, इसी के लिए उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। इसके ऊपर जितना मर्जी बोझा लाद दें, कोई इसके हम में बोलने वाला नहीं। कई बार पूछा जाता हैं कि असैम्बली के अन्दर बहुत से सदस्य किसान हैं, वे किसान की आवाज क्यों नहीं उठातें ? इस सवाल का एक ही जवाब देना पड़ता हैं कि वे अपने किसी न किसी लालच में फसें होगें इसी

लिए उनकी आवाज किसान की आवाज बन्द हो जाती हैं। अगर सर छोटू राम की तरह किसान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए तो सब कुछ हो सकता हैं। सर छोटू राम किसान के लिये हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन यहां नक्शा ही दूसरा हैं। यहां इनको अपने घर भरने के सिवाये कोई दूसरी बात नहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए सरकार किसान की ओर ध्यान दे, यह कब तक इस बोझ को बरदास्त करेगा। इसकी कमर टूटने वाली हैं, अगर किसान की कमर टूटेगी तो देश की कमर टूटेगी क्योंकि किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं। किसान को उसकी पैदावार का पूरा मूल्य मिलना चाहिए और चीजे भी सस्ती भाव पर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज किसान पैदा करता हैं उसका मूल्य 10रूपये हो और जब वह चीज कारखाने से निकले तो वह 100रूपये कि बिके। यह अनुपात कैसे चलेगा। कितने दिनों तक चलेगा, इस अनुपात को ठीक करने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक आदमी करोड़ पति होता जा रहा हैं और दूसरी तरफ किसान गरीब होता जा रहा हैं जो पैदावार करता हैं। 100 में से 95 किसान ऐसें हैं जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। इतना कर्जा हैं कि अगर कोई यह कहे कि अपना कर्जा उतार दो तो दो महीने के अन्दर–अन्दर कर्जा उतारने का प्रबन्ध नही कर सकता। अगर किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया तो किसानों को ही नहीं बल्कि सारे देश का पूरा नुकसान होगा। मुझे श्री स्वरूप सिंह जी की बात बहुत अच्छी

लगी। उन्होंनें कहा कि ईमानदारी की कदर होनी चाहिए लेकिन व्यवहार में यह बात आनी चाहिए, बातों से कुछ नहीं बनता। केवल कहने से कोई लाभ नहीं होने वाला हैं अगर हम ईमानदारी से सोचेगें तो इस बात को समझ पायेगें कि वाकई ही किसान को बहुत सहायता की जरूरत हैं अगर किसान की सहायत न की गई तो न केवल किसान का नुकासान होगा बल्कि सारे देश का भारी नुकसान होगा। पैदावार के मूल्य में इस साल घटौतरी की बजाये कम से कम दसरूपये प्रति क्विंटल बढौतरी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन हिसाब लगाता हैं, कैसे हिसाब लगाता हैं। आज बिना असलियत को जानें बूझे, जवानी बैठकर हर चीज का पता नहीं लग सकतां। अगर किसी खेत में एक साल एक हजाररूपये की पैदावार होती हैं, लेकिन अगले साल कई बार वह खेत 100रूपये भी नहीं देता क्योंकि खेती करने में कई प्रकार कीरूकावटे आती है। एक साल अगर पच्चासरूपये बच गये तो अगले साल उसी खेत में सौरूपये से लेकर चार सौरूपये तक घर से देने पड़ते हैं। यह गरीब क्यों हैं, इसी लिए गरीब हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन बातों की तरफ विशेष ध्यान देकर किसान की हालात सुधारने की कोशिश करे। राज्यपाल महोदय ने औद्योगीकरण का जिक्र किया हैं कि देश में उद्योग बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें कहीं उद्योग बढ़ते दिखाई नहीं देते। फरीदाबाद में बढ़ते होगें, लेकिन इन जगहों पर उद्योग बढ़ने से सारे हरियाणा प्रान्त को लाभ पंहुचने वाला नहीं हैं। प्रान्त के हर कोने में, हर बड़े नगर और छोटे नगर में, गांव

में जैसा रा मैटीरियल मिले, कच्चा माल मिले उसी के अनुसार वहां उद्योग धन्धे खुलने चाहिए। यदि एक ही जगह पर हम उद्योग इकट्ठे करते रहेगें तो उस इलाके के लोगों को तो शायद कुछ लाभ हो लेकिन वहां लेबर प्रौब्लम भी होगी। जहां लेबर ज्यादा होगी वहां लेबर प्रौब्लम भी कुदरती होगी। इसलिए हमेशा सरकार का ध्यान इस ओर आना चाहिए कि उद्योग बिखरे हुए हो। हर कोने में, हर नगर में और हर गांव तक उनका पंहुचना आवश्यक हैं। मैं इसके साथ ही साथ अपने निलोखेड़ी नगर के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। निलाखेड़ी नगर रिफ्यूजियों के लिए और विशेष तौर पर औद्योगिक नगर बनाया गया था। उसके अन्दर यह बात सबसे पहले रखी गई थी कि यहां के लोग दस्तकारी से गुजारा करेंगे और इसी नगर में दस्तकारी का विकास होगा। उस समय तो नेहरू जी भी वहां कई बार आए। मैं भी उन जलसों में गया था। उस समय लोग कहा करते थे कि निलाखेड़ी नेहरू जी का बच्चा हैं लेकिन आज उस बच्चे का किसी ने ध्यान नहीं। वहां जो उद्योग चले भी, कुछ उनमें से थोड़े बहुत तड़प–तड़प कर सांस ले रहे हैं। उनकी की तो कोई मदद करता हैं और कोई दूसरे उद्योग खोलने के प्रयत्न किए गए हैं। ऐसा शहर जिसकी नींव उद्योगों के लिए रखी गई हो और जिसमें हमारे प्रधान मंत्री स्वर्गीय पंडित लाल नेहरू का ध्यान रहा हो उसको इस तरह भूल जाना कोई अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तीन शूगर मिल्ज खोले जाने के बारे में कई साल से चर्चा चल रही हैं। ये मिल्ज कहा जाता हैं कि करनाल सोनीपत और कैथल

में खोली जानी हैं। करनाल के बारे में तो आज कई साल पहले कुछ हिस्से भी बांटे गए थे लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों भी सुना था कि करनाल, सोनीपत और कैथल में शूगर मिल्ज चलेंगी लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई। तो मैं, चेयरमैन साहब, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चांहूगा कि यदि तीनों शूगरा–मिल्ज चालू हो जांए तो हरियाणा की आर्थिक तरक्की में ये सहायक हो सकती हैं। इसलिए शीघ्र से शीघ्र इन मिलों को चलाए जाने की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

चेयरमैन साहब, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बिजली और ट्यूबवैल्ज की भी चर्चा की हैं लेकिन इस समय बावजूर सरकार के इस बात के कहने के कि हरेक गांव में बिजली पहुंचा दी गई हैं, मैं इस बस को छोड़ता हूं कि पहुंची या नहीं पहुंची या किस ढंग से पहुची लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं कि बिजली जिन गांवो में पहुंची हैं वहां रैगुलर सप्लाई अब थोड़े दिनों से चल रही हैं और आगे के लिये डर पैदा हो गया हैं कि आगे पता नहीं बिजली मिलेगी या नहीं और पता नहीं क्या होगा। लोगों ने ट्यूबवैल लगाए हुए हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिल रही हैं। वे इनके पीछे–पीछे फिर रहे हैं। जिस ढंग से, चेयरमैन साहब, लोगो को बिजली दी जाती हैं, ट्यूबवैल्ज के लिये कुनैक्शन मिलते हैं वह भी आप भली प्रकार से जानते हैं। हर रोज लोग हमारे पास भी आते हैं। मैंने इसकी एक सज्जन से

चर्चा भी की थी। उस समय दो सौरूपये एक कुनैक्शन की फीस ली जाती थी। और वह फीस सरकार नहीं बल्कि दूसरी थी। उस सज्जन ने कहा कि यदि सारे लोग दो सौरूपये दे दें तो कुनैक्शन मिल जायेंगे ? मैंने कहा कि फिर दो सौ की बजाये पांच सौरूपये हो जाएगें। फिर जो पांच सौरूपये देगा उसको कुनक्शन मिलेगा। यह चीज, चेयरमैन साहब, अभी हटी नहीं हैं। इस को हटाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

चेयरमैन साहब, मेरे से पहले चौधरी रिजक राम जी ने बिजली के बिलों के बारे में कुछ बातें कहीं। उन्होंनें यह बताया कि किस तरह से रींडिग ली जाती हैं। यह बिल्कुल सही बात हैं। मैं इसकी ताईद करता हूं। एक आदमी का सतारह सौरूपये का बिल दो महीने का आ जाता हैं। सतारह सौरूपये की बिजली तो एक आदमी मेरे ख्याल से 6–7 साल में भी नहीं जला सकता। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। नियम यह हैं कि पहले बिल अदा कर दो। फिर दरख्वास्त दो। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) इसलिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बजाये इसके के इस तरह से रींडिग चलें, इस तरह मीटर का हिसाब–किताब चलें, पंजाब की तरह हौर्स पावर के तीन ऊपर बिजली की दर लगा दी जाये। पंजाब में मेरे ख्याल से लगभग 60रूपये प्रति हौर्स पावर प्रति वर्ष रेट हैं। तो हमें इस बात की भी देख भाल करनी पड़गी । यदि ऐसा हो जाये तो सम्बन्धित व्यक्ति को पता रहेगा कि पांच हौर्स पावर के तीन सौरूपये देने हैं। तीन सौरूपये का प्रबन्ध वह किसी

न किसी तरह जब भी मौका लगेगा वह कर देगा। चाहे वह एक छमाही में डेढ़ सौरूपया दे और दूसरी में बाकी का डेढ़ सौरूपये दे या तीन सौरूपया इकट्ठा ही दे दें। इसका फैसला भी हो जाना चाहिय। यदि हौर्स पावर के ऊपर रेट लगेगा तो लोगों को भी सुविधा रहेगी और सरकार को भी सुविधा रहेगी। सरकार के सामने, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा भी भेजा था परन्तु दुर्भाग्य से वह प्रश्न वापिस होने वाला नहीं। उसका पता तो करेंगें परन्तु फिर भी मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस और दिलाना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का ढंग अपनाएंगे तो किसान को भी सुविधा रहेगी और सरकार को भी पूरी आमदनी होगी। आज तो उसे बिजली का बिल थानेदार की तरह दरवाजे पर खड़ा दिखाई देता हैं। जमींदार सोचता हैं कि वह किससे पैसा लेगा। कई बार उसके पास दो सौ–चार सौरूपये का बिल आकर खड़ा हो जाता हैं। इस सूझाव को यदि आप सरकार के ध्यान में लाएगें तो मैं समझता हूं कि किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। स्पीकर साहब, आगे जो महीने आने वाले हैं उनमें यदि बिजली की कमी किसी कारण से भी हुई तो अनाज सारा संभाला नही जा सकेगा। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई विशेष प्रबन्ध करना पड़े इस बात को कहने से तसल्ली नहीं होगी कि भाखड़ा झील में पानी कम हो गया हैं इसलिए बिजली की सप्लाई कम हैं, हम कहां से लाएं। पक्का अनाज जैसा पिछले सालों में खराब होता रहा हैं यदि इस साल भी खराब हुआ तो इससे किसान के अन्दर कमजोरी

आएगी, वह बेचारा मरेगा और उससे देश का भी भारी नुकसान होगा। इसलिए अभी से इस बात का प्रबन्ध किया जाना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण मैं परिवार नियोजन की भी चर्चा की हैं लेकिन परिवार नियोजन के जो ढंग अपनाए गए हैं वे ढंग केवल एक ही भाग हो सकता हैं परिवार नियोजन का वे साधन मात्र नहीं हो सकते हैं कि उनसे परिवार नियोजन हो जाए। आप देख रहे हैं कि शहर से आबादी बढ़ रही हैं। बावजूद इस बात के कि कागजों में दिखाया जाता हैं कि आबादी आगे से कम हुई हैं, वास्तविकरूप में आबादी बहुत बढ़ रही हैं। एक तरफ तो सरकारके काम चलें इस प्रकार के कि लोगों के अन्दर बच्चे पैदा करने की इच्छांए ज्यादा हो और दूसरी ओर टैम्परेरी साधन, आरजी साधन दिए जाएं और कहा जाए कि बच्चे पैदा न करो। तो इसमें पूरा लाभ पंहुचने वाला नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार के सामने कुछ थोड़े से सुझाव रखना चाहूंगा आपके द्वारा ताकि सरकार उन पर ध्यान दे सके। अगर सरकार इनको अपनाएगी तो मैं समझता हूं परिवार नियोजन में इनसे काफी सहयोग मिलेगा। परिवार नियोजन का जितना प्रचार होता हैं वह दूसरी ही बातों का होता हैं। मैंने भी एक सेमिनार में एक डिप्टी डायरैक्टर, फैमिली प्लानिंग को सुना था परन्तु वहां ब्रह्मचर्य पालन का कोई नाम तक नहीं लिया गया। मैं आपके जरिए यही निवेदन कंरूगा कि ब्रह्मचर्य पालन का प्रकार बड़े जोर से किया

जाना चाहिए परन्तु ऐसा किया नहीं जाता हैं। उसका कुछ न कुछ प्रचार लोगों में हो तो परिवार नियोजन अवश्य ही हो सकता हैं।

स्पीकर साहब, अब मैं सहशिक्षा की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। को एजुकेशन का कोई लाभ हो रहा हैं बल्कि यह बात उल्टी साबित हो रही हैं। यदि हमने को–एजुकेशन का कोई लाभ नहीं हो रहा हैं बल्कि यह बात उल्टी साबित हो रही हैं। यदि हमने को –एजुकेशन को समाप्त नहीं किया तो काफी हानि होगी क्योंकि जिस प्रकार से हम परिवार नियोजन की रट लगाते रहे हैं और परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं हो सका हैं। उसी प्रकार से को एजुकेशन से भ्रष्टाचार बढ़ने की ही सम्भावना हैं। इसलिए की अलग सिस्टम को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए और लड़के और लड़कियों की अलग अलग शिक्षा का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। यदि सरकार नहीं मानती हैं तो हम इसके साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरा अपना विचार है यह लाभदायक सिद्ध नही हो रही हैं।

इसके आलाव में गन्दे चित्रों की तरफ सरकार का ध्यान इस और आकर्षित करूंगा। स्पीकर साहब, आप ने देखा होगा कि अखबारों में मैंगजीनों में नंगी तसवीरें छापी जाती हैं। नंगी तस्वीरें फिल्मों में दिखाई जाती हैं। इस लिये इस प्रकार की गन्दी तस्वरों पर सरकार को प्रतिबन्ध लगाई जानी चाहिए। अखबारों और मैंगजीनों में ऐसी तस्वीरों छापने पर मनाही होनी चाहिये। ऐसी तस्वीरों से नवयुवकों पर बहुत बुरा असर पड़ता हैं।

दूसरे गन्दे गाने गाये जाते हैं इसका भी समाज पर और नवयुवकों पर बुरा असर पड़ता हैं। ऐसे–ऐसे गाने गाये जाते हैं कि भाई–बहिन, मां–बाप और बाप–बेटा बैंठ कर नहीं सुन सकते हैं इसलिये ऐसे गानों पर भी पाबन्दी लगनी चाहिए। परन्तु वे इन गन्द गानों को सुनना भी न चाहें तो भी उनको जर्बदस्ती सुनाये जाते हैं इस प्रकानर इन गन्दे गानों का गांव में प्रचार होता हैं उससे नौजवान लड़के और लड़कियों कि विचार दूषित हो जाते हैं। इसलिये मैं दोबारा यही अर्ज करूंगा कि इन पर भी पाबन्दी लगनी चाहिए।

आजकल हमारे प्रदेश के अन्दर शराब अधिक मात्रा में प्रचलित हो गई। चरित्रहीनता का शराब भी एक बहुत बड़ा कारण हैं। यदि शराब इसी तरह से बढ़ती रही तो देश का बहुत बुरा हाल होगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शराब की दुकानों पर पीकटिंग की थी। उन्होंनें शराब को बन्द करने के लिए कहा था क्योंकि वे समझते थे कि शराब बहुत बुरी चीज हैं। शराब से देश के लोगों का चरित्र समाप्त हो जाता हैं। यदि लोगों का चरित्र ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहता हैं। जैसा कि अंग्रेजी की एक कहावत आप ने सुनी होगी। इसलिये चरित्र ही सबसे मूल्यवान चीज हैं। इसकी रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य हैं। जहां सरकार दूसरी चीजों का इतना अधिक प्रबन्ध करती हैं, लोगों को चोरी और डाके से बचाती हैं, उनकी रह प्रकार की रक्षा करनी हैं। सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिएं। सरकार की यह

जिम्मेदारी हैं। अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए और शराब बन्दी पूरी तरह से की जानी चाहिए। दो–तीन साल पहले जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि तीन वर्षो में हरियाणा में पूर्णरूप से शराब बन्दी कर दी जायेगी तो मुझे महान प्रसन्नता हुई थी। उन्होनें अपने एलान में कहा था कि इस साल दो दिन सप्ताह में शराब बन्द करेंगें, अगले साल चार दिन के लिये बन्द कर दी जायेगी। परन्तु जैसा उन्होने कहा था उसके अनुसार बिल्कुल नहीं हुआ। सरकार ने एक साल तो दो दिन के लिए हफ्ते में बन्द कर दी थी परन्तु फिर खोल दी गई हैं। इस तरह यह प्रान्त की तरक्की करना चाहते हैं सरकार शराब के ठेके दे कर पैसा कमाना चाहती हैं। लोगों के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं। सरकार तो केवल एक ही चीज ही चाहती हैं कि उसके खजाने में पैसा आये। इस प्रकार बढ़ती रही तो चरित्रहीनता ही लोगों में आयेगी। इसी प्रकार की और भी कई एक चीजों हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी जी के जो स्वप्न थे वे पूरे हो। उनकी आत्मा को शान्ति पंहुचाने के लिये शराब बन्दी करने का पूरा–पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय गवर्नर साहब के अभिभाषण में सड़को के बारे में चर्चा की गई हैं। हरियाणा में आज कल काफी सड़के बन रही हैं। सभी को पता हैं कि उनमें कितनी हेरा–फेरा होती

हैं, उसकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि कोई सड़क अच्छी तरह से बना दी जाये तो उसे चार पांच साल तक मुरम्मत करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। परन्तु अब जो भी सड़के बन रही हैं वे एक वर्ष के अन्दर ही मरम्मत मांगने लग जाती हैं। उनके अन्दर दो–दो, तीन–तीन गज लम्बे गढ़े पड़ जाते हैं। मिट्टी जितनी डाली जानी चाहिए उतनी ही डाली जाती हैं। सड़को पर ईन्टे भी दोयम दर्जे की लगाई जाती हैं। बल्कि कई जगहों पर सोयम दर्जे की लगायी जाती हैं। जहां तक पत्थर , यानी रोड़ी का सम्बन्ध हैं वह भी हिसाब के मुताबिक नहीं डाली जाती हैं। हिसाब के मुताबिक तो चार इन्च मोटा पत्थर डाला जाना चाहिए परन्तु वहां पर दो इन्च मोटा पत्थर यानी रोड़ी डाली जाती हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): दो इन्च मोटी कौन सी ईट होती हैं ?

चौधरी शिव राम वर्मा : चीफ मिनिस्टर साहब मैंने पत्थर कहा हैं कि चार इन्च मोटे पत्थर की बजाए दो इन्च मोटा पत्थर डाला जाता हैं।

चौधरी बंसी लाल : आप एक दो सड़कों के नाम तो बताये कहां पर दो इन्च मोटा पत्थर डाला गया ताकि हम उनके बारे में इन्कवायरी कर सके।

चौधरी शिव राम वर्मा: हां मैं एक दो सड़कों के नाम भी आप को बता देता हूं। एक सड़क करनाल से कौल वाया साम्भली होती जा रही हैं उसमें पीली ईटें लगी हुई हैं। दूसरी सड़क भम्भेवा से मोरखी गयी हैं उसको आप जाकर देखिए वहां भी यही हालत है। इस प्रकार से कई सड़कें आप को मिलेंगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि लगभग हरेक सड़क ही ऐसी मिलेगी। आप इन्कवायरी करवांये हम उसमें आपका सहयोग देंगे।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब आप अपनी स्पीच कितनी देर में समाप्त करने जा रहे हैं। करीब एक घंटा हो गया हैं।

चौधरी शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब थोड़ी सी बातें रह गई हैं अभी समाप्त करता हूं। हरिजनों के विषयों में हम काफी कुछ सुनते रहे हैं परन्तु जिस प्रकार से हरिजनों का उद्धार होना चाहिए अभी तक होता नहीं दिखाई नहीं दे रहा हैं। सरकार अभी तक एक चीज समाप्त नहीं कर सकीं हैं वह हैं छुआछूत। चुनाव के दिनों में तो लोग उन गरीब हरिजनों के घरों में जाते है और दूध–चाय पी लेते हैं लेकिन बाद में उनके साथ कोई मिलना–जुलना नहीं होता हैं।

जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गांवो में जब पंचायते होती हैं वहां कोई हरिजन या दूसरी जाति कि लोग मिल–जूल कर नहीं बैठते हैं। हरिजनों को स्वर्ण जाति के लोग अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं बल्कि हरिजनों में भी दो

किस्में हैं वे भी एक दूसरे से ऊंचा–नीचा समझते हैं। इसमें भी किसी दूसरे को दोष नहीं दिया जा सकता है यह सब दोष सरकार का ही हैं। इन सब चीजों को दूर करने का प्रबन्ध सरकार को करना चाहिए। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इनकी भलाई की और विशेषरूप से ध्यानप देना चाहिए। अभी तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ हैं। इस लिए उनको कोई कुटीर उद्योग या कोई घरेलु धन्धे करने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए ताकि वे बेचारे गरीब भी तरक्की कर सके।

श्री अध्यक्षः आपका एक मिनट बाकी रह गया है। आप एक मिनट ही ओर बोले।

चौधरी शिव राम वर्माः स्पीकर साहब मैं अभी समाप्त करता हूं स्पीकर साहब मैं अभी कह रहा था कि इन गरीब हरिजनों के रहने के लिए भी प्रबन्ध करना सरकार की जिम्मेदारी हैं। जो गरीब जन–जातियों है उन सब के लिए रहने के लिए मकान का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मैंने हरिजनों के विषय में ध्यानकर्षण प्रस्ताव भी दिया था वह तो मेरे पास वापिस कर दिया हैं। परन्तु फिर भी मैं सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज तक हरिजनों के कल्याण के काम देखने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी हैं। इसलिए हरिजनों के कल्याण के लिए असैम्बली के मैंम्बर्ज की एक कमेटी बनायी जाए। वह कमेटी इस विषय में जांच करे कि हरिजनों की क्या कुछ तरक्की हुई हैं। वह कमेटी अफसरों के विषय में ख्याल रखेगी कि वे हरिजनों की ओर ख्याल रखते

हैं या नहीं, उनके कुछ भलाई के काम कर रहे हैं दूसरे कमेटी हरिजनों की भलाई के बारे में अफसरों आदि को सलाह भी देगी। इस प्रकार अगर कमेटी बना दी जायेगी तो हरिजनों की भलाई ही होगी।(अध्यक्ष महोदय की ओर से घन्टी) अध्यक्ष महोदय अब कुछ थोड़ी सी बाते ही कहने को रह गयी हैं परन्तु आपने अब दूसरी घन्टी भी बजा दी हैं इसलिए मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सभा कल दिनांक 6 अप्रैल,1973 दो बजे मध्यान्ह पश्चात तक लिए स्थगित की जाती हैं।

6.30 P.M.

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 6th April, 1972)